

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 19 मार्च 1979

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(10) 1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(10) 3
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(10) 25
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(10) 38
ध्यानाकर्षण सूचना – राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1 तथा 10 पर यातायात बढ जाने के कारण गम्भीर दुर्घटनाये बढने के सम्बंध में	(10) 63

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 19 मार्च 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर -1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान पहले भाोक प्रस्ताव होगा।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, बड़े दुःख के साथ मैं यह भाोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 8 मार्च को जब हमारा सत्र चल रहा होगा उसी दिन केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री रघुनाथ के ठाव खाडिलकर का देहावसान हो गया। आपका जन्म 15 दिसम्बर 1904 को हुआ था। स्पीकर साहब, छोटी अवस्था में ही उन्होंने युवा आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1934 में समाजवादी दल का निर्माण कांग्रेस के बीच में किया गया और वे उसके संस्थापक यानी फाउंडर मैम्बरों में से एक थे। 1930 से 1945 तक स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लेने पर कई बार जेल गए और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1948 में जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की मजदूर और किसान के प्रति सहानुभूति नहीं रही है

तो उन्होंने किसान मजदूर संगठन का गठन किया। 1957 में वे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और 1967 से 1971 तक केन्द्र में सिविल सप्लाई विभाग के मंत्री रहै और 1971 से 1973 तक लेबर और रिहैबिलीटे इन विभाग के मंत्री रहे। आपने अपने देश का प्रतिनिधित्व बाहर के देशों में किया था, विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जनेवा सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय रिप्रेजेंटेटिव का नेतृत्व किया। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री खाडिलकर देश के प्रमुख सेनानियों में से एक थे और वे एक सफल राजनैतिक तथा पार्लियामेंटेरियन थे। उनका 8 मार्च को देहावसान हो जाने से देश ने एक महान विभूति तथा स्वतन्त्रता सेनानी को खो दिया।

इसी प्रकार से श्री भाई लाल भाई कान्द्रैक्टर जो गुजरात के उद्योग मंत्री थे, का निधन पहली मार्च को गया। स्पीकर साहब, उन्होंने भी युवा अवस्था में राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि 'फिरंगियाँ भारत छोड़ो' तो वे उस आन्दोलन में कूद पड़े और उन्होंने जेल यात्रा की। 1952 से 1957 तक पांच वर्ष तक वे जिला डिवैलपमेंट बोर्ड के सचिव रहे। 1957 और 1962 में दो बार वे गुजरात विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के मंत्री पद का भार बड़ी कुशलता से निभाया। वे गुजरात की कार्पोरेट्स के चेयरमैन रहे और विभिन्न सामाजिक और ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की विकास गतिविधियों में गहरी रुचि

लेते रहे। उनकी योग्यता चतुर्मुखी होने के कारण वे बड़े लोकप्रिय थे। श्री भाई लाल भाई कान्ठेकर बडौदा भाहर के रावपुर निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधान सभा के सदस्य चुने गये। जब 1975 में जनता पार्टी ने कांग्रेस से मोर्चा लिया, स्पीकर साहब, उस समय वे जनता पार्टी की ओर से निर्वाचित हुए थे और उस समय से उद्योग मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। बीच में सरकार टूट गई। दोबारा सरकार बनने पर वे फिर उद्योग मंत्री बन गये। स्पीकर साहब, ये प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, विख्यात राजनीतिक और सुप्रसिद्ध देशभक्त थे। ऐसे व्यक्ति का इस संसार से उठ जाना इस सदन के लिए बड़े दुःख का विषय है।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार हिसार जिले के श्री निहाल सिंह स्वतन्त्रता सेनानी जो हमारे मुख्य मंत्री महोदय के बड़े निकटवर्ती मित्रों में से थे, उनका निधन 26 फरवरी 1979 को हो गया। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन 32 वर्ष की अवस्था में 'गुरु का बाग आन्दोलन' में भाग लेकर शुरू किया था और एक वर्ष की जेल काटी। 1929 में उन्होंने भोखुपुरा बम काण्ड से संबंधित होने के कारण दो मास के लिए जेल काटी। फिर इंडिविजुअल सिविल डिजाइटिमेंस आन्दोलन में बढचढ कर हिस्सा लिया और छः महीने की जेल काटी। स्पीकर साहब, इसके बाद 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में हिस्सा लिया और 1942 से 1944 तक दो वर्ष जेल की यातनाएं सहिं। स्पीकर साहब, ऐसे देशभक्त का इस संसार से उठा जाना इस सदन के लिए बहुत कष्टदायक है। इन भावों के साथ जिन तीन महानुभावों

के देहावसान के सम्बंध में मैंने जो भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मुझे भरोसा है कि यह प्रस्ताव यह सदन दिवंगत आत्माओं के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों सेम अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता है, सर्व सम्मति से पारित किया जाएगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव डाक्टर साहब ने रखा है, मैं अपनी तरफ से और सारी अपोजी इन पार्टी की तरफ से उस से सहमति जाहिर करता हूं। बडे दुख की बात है कि तीन महान आदमी इस दे आ से उठ गए हैं, जिनकी क्षति पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम है। इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत मकान काम किए हैं, दे आ की बडी सेवा की और जेलें काटी हैं। इन तीनों महान आत्माओं के चले जाने से दे आ को बडा नुकसान हुआ है। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों महान आत्माओं के जो परिवार हैं, उनको हाउस की तरफ से हमदर्दी भेजी जाए और सदन की तरफ से श्रद्धांजलि भेजी जाए। श्री निहाल सिंह को मैं जानता हूं। उन्होंने जनता के लिए बडे काम किए थे। 'क्विट इंडिया मूवमेंट' में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल काटी। और दे आ को आजाद कराने में बढ चढ कर हिस्सा लिया था। ऐसी महान आत्माओं से हम सबको सबक सीख कर उनके कदमों पर चलना चाहिए। उन्होंने जो रास्ता हमें बताया है उसी पर चलकर हम दे आ का भला कर सकते हैं। स्पीकर साहब, मेरी फिर एक बार आपसे प्रार्थना है कि इनकी फैमिलीज को हमारी तरफ से पूरी हमदर्दी भेजी जाए।

श्री अध्यक्ष: स्वर्गवासी नेताओं के बारे में सदन में काफी कुछ कहा गया है। वाकई बहुत बड़े इंसान थे और उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर पोजी नों में दे ा की बड़ी सेवा की। श्री खाडिलकर ने लोक सभा के डिप्टी स्पीकर साहब, और यूनियन मिनिस्टर साहब के तौर पर दे ा की सेवा की। श्री कान्द्रक्टर ने मिनिस्टर के तौर पर गुजरात की बड़ी सेवा की और श्री निहाल सिंह हमारे हरियाणा के ही हिसार जिले के एक सरकरदा फ्रीडम फाईटर थे। स्वर्गवासी नेताओं के बारे में साथियों ने जो विचार और भावनाएं प्रकट की हैं, मैं अपने आपको उन भावनाओं के साथ भामिल करता हूं। और इस सदन की भावनाओं और हम दर्दी को भाोक जदा परिवारों को पहुंचाऊंगर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्वर्गवासी नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए खडे होकर दो मिनट का मौन रखें

(इस ससम सदन ने दिवंगम नेताओं के सम्मान में खडे होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान अब सवाल होंगे।

Havoc caused by flood in Sahibi Nadi

***1081. Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any steps have been taken by the Government to control floods by the Sahibi Nadi in the Jhajjar Constituency: is so, teh details

thereof and, if not, the time by which such steps are likely to be taken ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): जी हां, साहिबी नदी पर मसानी गांव के पास नै नल हाई वे नम्बर 8 पर बाढ को नियन्त्रित करने के लिए एक बैराज बनाने की योजना है। बैराज के दोनों किनारों को ऊंचे उठा कर एक जलाय तैयार किया जायेगा।

कैप्टन मांगे राम : स्पीकर साहब, अभी अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में फरमाया है कि साहिबी नदी पर मसानी गांव के पास नै नल हाई वे नम्बर 8 पर बाढ को नियन्त्रित करने के लिये एक बैराज बनाने की सरकार की योजना है। क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बैराज बनने में कितना टाईम लगेगा ? क्या इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का सरकार का विचार है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, वे बाढ के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक एमबैंकमेंटस का सवाल यह है। यह काम जून 1980 तक मुकम्मल हो जाएगा और रिजरवायर व बैराज का काम जून 1981 तक होने की सम्भावना है।

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस बैराज के लिये जमीन एकवायर कर ली है, अगर जमीन एकवायर की है तो कितने एकड के करीब एकवायर कर ली है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जमीन की एक्वीजी न की कार्यवाही चली हुई है और जितनी टोटल जमीन एक्वायर की है, उसकी ठीके फिगर 19012 हैक्टेयर है।

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय कि जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई है, उन लोगों को उस जमीन का मुआवजा दे दिया गया है कि नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब से जनता सरकार बनी है तब से जिनकी जमीन एक्वायर की गई है, उन सबको मुआवजा अदा कर दिया गया है।

Mr. Speaker, I had earlier given some figure about the acquisition of land in reply to a supplementary by Rao Dalip Singh. That does not appear to be correct. I will check it up and satisfy the hon. Member.

Mr. Speaker: Will you supply him the answer later ?

Shri Verender Singh : I will satisfy him.

Roads constructed by Marketing Committee in District Rohtak

***1016. Shri Jai Narain:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the Market Committee wise total mileage of roads constructed by the Marketing committees in district Rohtak during the current financial year, separately ?

कृषि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): मार्किटिंग कमेटीज द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में जिला रोहतक में कोई सडक नहीं बनाई गई है।

चौधरी राम मिशन: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जिला जींद में मार्किट कमेटी की अच्छी आमदनी है पर वहां पर पिछले पांच सालों से कोई सडक नहीं बनाई गई है इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार के विचाराधनी ऐसी कोई प्रोजेक्ट है ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, यहां पर रोहतक मार्किट कमेटी के बारे में सवाल पर डिस्कशन हो रही है।

डा० बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, कांग्रेस सरकार के वक्त से जगाधरी के अंदर हनुमान गेट से छछरौली बाईपास जो एक सडक बन रही थी; वह अभी तक अधूरी पडी हुई है। इस बारे में, मैं मंत्री महोदय से यह इंफॉर्मेशन चाहता हूँ कि उस अधूरी सडक को कब तक बनाने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से रिकवैस्ट करूंगा कि वे जो सप्लीमेंटरीज पूछें, वे मेन सवाल से संबंधित हों। अगर मैम्बर साहिबान नई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिये उन्हें अलग नोटिस देना चाहिये, फिर उन्हें उसका जवाब अवश्य मिलेगा।

श्री जय नारायण: स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर मार्किट कमेटियों को बहुत ज्यादा आमदनी है लेकिन

पिछले चार पांच सालों से उनकी तरफ से कोई सडक नहीं बनाई गई हैं मैं जानना चाहता हूं कि इन मार्किट कमेटियों की पैसा कहां पर यूज किया जा रहा है ? क्या इस बारे मिनिस्टर साहब रोानी डालने की कृपा करेंगे ? कम से कम रोहतक जिले को उस आमदनी का हिस्सा मिलना ही चाहिये ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, असल में मार्किट कमेटियों की जो आमदनी होती है, उस आमदनी का सिर्फ 5 प्रतिशत ही उनके पास रहता है और उससे वह अपने फोरथ क्लास एम्पलाईज की तनख्वाहों की जरूरियात को ही पूरा कर पाती हैं। 65 परसेंट पैसा पीओडब्ल्यूडी वालों को सडकें बनाने के लिये दे दिया जाता है, मार्किट कमेटियां सडकें नहीं बनाती।

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने 5 परसेंट पैसे की बात की हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो पैसा जिस जिस मार्किट कमेटी से वसूल किया जाएगा क्या यह पैसा उन्हीं के लिये यूज करने की सरकार की कोई तजवीज है ?

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, अभी माननीय मन्त्री महोदय से यह फरमाया है कि हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री महोदय गये थे और उन्होंने वहां पर एलान भी किया था कि जिस एरिया का पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उसी एरिया पर उसका 70 परसेंट खर्च करेंगे। क्या मन्त्री महोदय के पास कोई ऐसी स्कीम विचाराधीन है ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया है कि यह मामला जेरे गोर है और मार्किट कमेटियों को 20 परसेंट राशि देने की प्रोपोजल है। अगर मैम्बर साहेबान चाहें तो यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है।

चौधरी हरिचंद हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि मार्किट कमेटियां जो जिला रोहतक में हैं, उनका जो असली परपज था वह क्या था ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो मार्किट कमेटियों की सड़कें हैं, उनकी मेन्टीनेंस ठीक नहीं हो पाती है और जब इस बारे में संबंधित अधिकारियों से उनकी रिपयेर वगैरह के लिये बातचीत की जाती है तो वे कहते हैं कि मार्किट कमेटियों की अपनी सड़कें हैं, वे उनकी मेन्टीनेंस आप करेंगी। उन सड़कों पर काम करने वाले जो बेलदार वगैरह हैं वे पी0डब्ल्यू0डी0 वालों के हैं। तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ये सड़कें किन के अंडर आती हैं ? क्या इन सड़कों का ठीक इंतजाम करवाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ? क्या इसके लिये मंत्री महोदय कोई आवासन देंगे ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, ऐसा मालूम होता है कि मेरे दोस्त को किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई है। जो सड़कें बनाई जाती हैं वह पी0डब्ल्यू0डी0 वालों के थ्रू बनाई जाती हैं।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटियों का जो पैसा होता है, वह एक पूल में जमा हो जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिस जिस मार्किट कमेटी का पैसा हो, क्या सरकार उसे उसी हल्के पर खर्च करने का विचार रखती है ताकि एक हल्के का पैसा दूसरे हल्के में खर्च न होने पाए ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल बहुत अच्छा है लेकिन हम तो 65 परसेंट के करीब रुपया पी0डब्ल्यू0डी0 वाले लेते हैं। उसका जवाब मंत्री जी ने कोई तसल्ली बख्शा नहीं दिया। बहुत सी सडकें काफी समय पहले से बनी हुई हैं जो पूरी तरह से टूटी पडी हैं। जब रिपेयर करने की बात आती है तो पी0डब्ल्यू0डी0 कहते हैं कि यह मार्किट कमेटी की सडकें हैं और मार्किट कमेटी वाले कहते हैं कि यह पी0डब्ल्यू0डी0 वालों की सडकें हैं। यह मसला ऐसा गंभीर बना हुआ है कि इन सडकों की जिम्मेवारी लेने के लिये कोई तैयार नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन रोडज की जिम्मेवारी किस की है ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल अच्छा है। अगर आनरेबल मैम्बर ऐसा कोई केस हमारे नोटिस में लाएंगे तो फौरन उस पर ऐक्शन लिया जाएगा और बताएंगे कि रोडज किस की है।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत अपने पापुलर मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि अगर

कहीं पर जरूरत होगी तो क्या वहां नई मार्किट कमेटी बनाने पर विचार किया जाएगा ? जैसा कि हमारा हल्का भाहजादपुर है वहां पर नई मार्किट कमेटी बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: लाल सिंह जी, यह सवाल सडक बनाने के बारे में है, मार्किट कमेटी बनाने के बारे में नहीं है।

Decrease in State Revenue due to allotment of Liquor Vends

***1097. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there has been any decrease in the Government income during the period from 1-4-1978 to 31-12-1979 on account of allotment of liquor vendsa as compared to income accrue during such period of last year; is so, the extent of such decrease ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): पिछले वित्तीय वर्ष राजस्व की तुलना में 1-4-78 से 31-12-78 तक 36005058 रुपये की राजस्व की कमी हुई, परन्तु यह कमी केवल ठेकों की अलाटमेंट प्रणाली अपना से नहीं बल्कि 1-4-78 से मद्य निशेध के फेजड प्रोग्राम को लागू करने के कारण भी हुई है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में फरमाया कि यह सारा घाटा लाटरी सिस्टम की वजह से ही नहीं हुआ। क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह चीज है कि उन्होंने सौ के करीब ठेके बंद

कर दिये और कईलाख प्रफ लीटर भाराब की कंजपं इन घटा दी। अब जो ठेके नीलाम हुए हैं, वह पहले से चार चार और आठ आठ गुना बोली पर गये हैं। क्या अलाटमेंट पालिसी से यह घाटा नहीं हुआ ?

चौधरी भोर सिंह: यह इन्फर्मे इन मैम्बर साहेबान के पास ही होगी, मेरे पास नहीं है।

श्री जगन नाथ: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 31 दिसम्बर तक 3 करोड 60 लाख रू0 का घाटा हुआ लेकिन चार पांच दिन पहले इन्होंने बताया था कि दो करोड रुपये का घाटा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज वाला जवाब सही है या पहले वाला ?

चौधरी भोर सिंह: दोनों जवाब सही हैं। ऐसा है कि 1977-78 में 58 लाख तक लिटर भाराब का कोटा था उसे हमने घटा कर 1978-79 में 46.40 लाख पुफ लीटर कर दिया। हमारी अनुमानित आय 16500100 रू0 की थी और 9 महीने में 23750747 रू0 की आय का अनुमान था जबकि 31-12-78 तक हमारी आय हुई 7862578 रू0। इसलिये हमें 25888169 रुपये का घाटा हुआ। प्र न में इन्होंने पिछले सालों के मुकाबिले में 1977-78 का घाटा पूछा था, उसमें 3 करोड से अधिक का घाटा है। इसलिये मैंने कहा है कि दोनों जवाब ठीक हैं।

चौधरी खुर पीद अहमद: क्या वजीर साहब बताएंगे कि यह घाटा 90% अलाटमेंट सिस्टम की वजह से हुआ और

बाकी 10 प्रतिशत दूसरे कारणों की वजह से हुआ ? क्या यह बात ठीक नहीं है ?

चौधरी भोर सिंह: इसकी परसेंटेज मैंने नहीं निकाली है ।

Pipe Line for Irrigational Purposes

***1106. Chaudhri Lal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state

(a) whether it is a fact that M.I.T.C. provides a pipe line of 4000 feet for irrigation of land from the tubewells to the farmers;

(b) if reply to part(a) above be in the affirmative whether the Government/M.I.T.C. have received any representations to the effect that the pipe line of 4000 feet is inadequate and it should be increased; and

(c) if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) आमतौर पर 3000 से 4000 फुट लम्बी पाईप लाईन सीधी सिंचाई वाले नलकूप जो कि हरियाणा लघु सिंचाई नलकूप निगम द्वारा लगाये जाते हैं पर बिछाई जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) किसानों को राय दी जाती है कि वे अपने खर्च पर पाइप लाइन बढा लें।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है उससे मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिन ट्यूबवैल्ज पर चार हजार फुट तक की पाइप लाइन बिछाई जाती है वह बहुत कम है क्योंकि वहां पर इससे भी लम्बी नालियों की जरूरत है। जमींदार बेचारे गरीब होते हैं, वे तो अपने पास पैसा खर्च करके नाली लगवा नहीं सकते और सरकार उससे आगे बिछाती नहीं है। इस वजह से एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैलों का पानी नहीं बिकता और बेकार खडे रहते हैं। इसलिये क्या सरकार इन नालियों को चार हजार फुट से आगे लम्बी बिछायेगी या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, फिलहाल सरकार की पालिसी के मुताबिक तीन हजार से चार हजार फुट तक ट्यूबवैलों के जरिये इरीगे ान करने के लिये पाइप दी जाती है लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो कैनेल से इरीगे ान करते हैं, उन पर खाल पक्के करने का खर्चा भी पडता है और एक फुट की भी रियायत नहीं दी जाती। जबकि ट्यूबवैल वालों को हम चार हजार फुट तक की रियायत देते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि केवल नारायणगढ में ही किसान नहीं बसते, वे आदमपुर में भी बसते हैं और भले राम जी के हल्के में भी बसते हैं। दूसरी बात यह है कि एक ट्यूबवैल से एक साल में ज्यादा से ज्यादा तीन सौ एकड में इरीगे ान होती है और एक क्यूसिक पानी डिसचार्ज

होता है। तो तीन सौ एकड के लिये इतनी पाइप देना ही सफ़ि एंट कंसिडर किया गया है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: क्या इस तरह के ट्यूबवैल हरियाणा में और जगहों पर भी लगाने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जी हां लगाएंगे।

चौधरी गंगा राम: क्या मंत्री जी को मालूम है कि हरियाणा में जितनी भी ड्रेनें हैं, उनके अंदर पानी खडा होता है और कई दफा उनके अंदर पानी चलता भी है यानी प्लड का जो पानी होता है वह उनमें चलता रहता है। कई बार किसान नलकूपों के द्वारा अगर इन ड्रेनों से पानी लेकर सिंचाई कर लेते हैं तो सरकार उन पर वाटर रेट लगा लेती है और पैसा चार्ज करती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी तजवीज है कि वह वहां पर नलकूप खुद लगवा दे फिर बे तक किसानों के वाटर रेट चार्ज कर लें ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का मेन सवाल के साथ कोई संबंध नहीं है।

Closure of Good Year Tyre Comapny at Ballabgarh

***1114. Chaudhri Rajinder Singh :** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state

(a) whether the Government is aware of the fact that the Good Year Tyre Company at Ballabgarh has been

closed; if som since when and the reasons leading to its closure;

(b) the number of workers, both skilled and unskilled, who have been rendered jobless as a result of closure of the said factory;

(c) the estimated loss in Sales Tax suffered by the Government on account of closure of the said factory; and

(d) the remecial steps so far taken or porposed to be taken by the State Government to avoid further loss of revenue ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) मै० गुड इयर इण्डिया लि० बल्लभगढ बंद नहीं हुई परंतु प्रबंधकारियों ने दिनांक 26-1-79 को श्रमिकों के काम रोको हडताल के कारण, तालाबंदी घोशित की क्योंकि दिनांक 20-1-79 से एक श्रमिक को एक भाग से दूसरे भार पर फोरमैन द्वारा बदलने पर श्रमिक काम रोको हडताल का सहारा ले रहे थे और इससे पूर्व फैक्टरी के कई अनुभागों में काम की गति को धीमा किया गया था।

(ख) लगभग 1500 श्रमिकों पर इस तालाबंदी के कारण असर पडा।

(ग) लगभग 125000 रुपये का इस तालाबंदी के कारण नुकसान हुआ।

(घ) श्रम विभाग की समझौता मीनरी प्रबंधकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों में समझौते की बातचीत कर रही है ताकि झगड़े को निपटाया जाये और फ़ैक्टरी काम करना आरम्भ कर दे।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 26-1-79 से 1 लाख 25 हजार रुपये की हानि हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस गुड इयर फ़ैक्टरी की तालाबंदी से हमारे सारे फरीदाबाद के क्षेत्र में, सारे वर्कर्स में और उद्योग धंधों में भी बड़ी भारी असंतुष्टि फैली हुई है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस फ़ैक्टरी को जल्दी से जल्दी चालू करने का कब तक प्रबंध कर देंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए एक निश्चित समय का आवासन चाहता हूँ ?

चौधरी भजन लाल: लेबर डिपार्टमेंट ने इस बारे में चार पांच लेबर तथा मिल मालिकों के साथ की। उसके बाद मैंने दिल्ली में 23 जनवरी और 27 जनवरी को दो मिटिंगें की। 21, 22 और 23 फरवरी को भी वर्कर्स और मिल मालिकों के साथ बैठकर अधिकारियों और मैंने बातचीत की हैं। अब उम्मीद की जाती है कि फ़ैक्टरी जल्दी चालू हो जायेगी।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 1 लाख 25 हजार रुपये का घाटा बताया है लेकिन तथ्य यह है कि यह घाटा केवल सेल्ज टैक्स का नहीं, बल्कि सारे राजस्व

के एक दिन का अनुमान है। मैं जानना चाहती हूँ कि यह राशि कब तक की बतायी गई है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सेल्ज टैक्स से हमारी स्टेट को 1 लाख 20 हजार रुपये की आमदनी इस फैक्ट्री से हर माह होती है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कुल राजस्व की कितनी हानि हुई है ?

चौधरी भजन लाल: कुल राजस्व की 9 या 9.50 लाख रुपये की हानि हुई है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: जी नहीं, यह तो एक दिन की हानि है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह एक महीने की हानि बतायी गई है।

श्री मूल चन्द मंगला: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया है कि उनकी श्रमिकों से बातचीत चल रही है, भीष्म फैसला हो जायेगा। अगर यह फैसला जल्दी नहीं हुआ तो क्या सरकार द्वारा कोई दूसरा कदम उठाया जायेगा जिसके जरिए सरकार उनको मजबूर करें कि या तो फैक्ट्री जल्दी चलाई जाये या सरकार इसको टेक ओवर कर ले ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस दिनांक में सरकार पूरी कोशिश कर रही है ताकि यह फैक्ट्री जल्दी चालू हो जाये। अगर किसी वजह से ऐसा न होने की संभावना

हुई तो सरकार दूसरा कानूनी कदम उठायेगी। इस बात के लिए कोर्ट भी बनी हुई है, फिर उसमें कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

स्वामी आदित्यवे I: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गुड इयर फैक्टरी की तालाबंदी वर्कर्स के असंतोश के कारण हुई है या मालिकों की लापरवाही के कारण हुई है ?

चौधरी भजन लाल: ऐसा करने से कोई एक पार्टी दोषी नहीं होती, तालाबंदी दोनों तरफ की गलतियों के कारण होती है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, वहां आर्थिक मामले को लेकर गडबड नहीं हुई, बल्कि सिक्योरिटी आफ सर्विस को लेकर झगडा चल रहा है। 26 जनवरी से आज 19 मार्च आ गया है और आपने अभी कहा कि फैसला जल्दी हो जायेगा। आज पूरे तीन महीने होने को आ रहे हैं कोई फैसला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह फारेन कंसर्न है और यह लोग अमेरिका में इन महीनों में 32 करोड रुपया भिजवा चुके हैं। आप इसको टेक औवर क्यों नहीं कर लेते ?

चौधरी भजन लाल: असल में यह मामलाच इस प्रकार भुरू हुआ कि एक वर्कर को फोरमैन ने दूसरी जगह काम के लिए बदल दिया कि यह काम करो। वह वर्कर उस काम में नहीं लगा, इस बात पर फोरमैन से उसका झगडा हो गया। झगडै की वजह से फैक्टरी के मालिकों ने उस वर्कर को सस्पेंड कर दिया। वह फैक्टरी के बाहर नहीं गया, ऐसा होने से सारे वर्करों ने काम करना बंद कर दिया, तीन दिन एक भी टायर

नहीं बना। फिर मुझे फोन पर बुलाया गया मैंने वहां मीटिंग की और वर्कर्स को समझाया गया लेकिन फिर भी 26 जनवरी तक कोई टायर नहीं बना। अन्त में मालिकों को मजबूर होकर फैक्टरी बंद करनी पड़ी।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने 9, सवा नौ लाख का अनुमानित घाटा बताया है यह किन आंकड़ों पर आधारित है ? इसमें सेल्ज एंड एक्सपोर्ट टैक्स के रूप में कितनी हानि हुई, अलग अलग बतायें ?

श्री अध्यक्ष: इसका अलग नोटिस दें।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: इस फैक्टरी के बंद होने से कितने करोड़ की प्रोडक्शन का घाटा हुआ है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस फैक्टरी में तकरीबन 16 सौ से 22 सौ तक रोजाना टायर बनते थे। मैम्बर साहेबान स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा ? मैं विवास के साथ कहता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर इस फैक्टरी को चालू कर दिया जायेगा।

Persons registred with the Employment Exchanges in the State

***1116. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state

(a) the district wise total number of under Matriculates, Matriculantes, Graduates, Post Graduates and

Diploma holders, registered in the Employment Exchanges in the State upto 1st January, 1979, separately;

(b) the total number of person out of those referred to in part (a) above who are handicapped and disabled in each category;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to give preference or to reserve some posts for the handicapped and disabled unemployed persons in the State; and

(d) whether there is also any proposal under consideration of the Government to give unemployemnt allowance to the unemployed persons in the State ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) तथा (ख) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) तथा (घ): जी नहीं ।

सूची

(क) जिला अनुसार मैट्रिक से कम, मैट्रिकुलेटस, ग्रेजुएटस, पोस्ट ग्रेजुएटस तथा डिप्लोमा होल्डर्स की दिनांक 31-12-78 की वह संख्या जिसमें वे राज्य के रोजगार कार्यालयों में रोजगार सहायता के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे, निम्न हैं :-

जिले का नाम	मैट्रिक से कम	मैट्रिकुलेटस	ग्रेजुएटस	पोस्ट ग्रेजुएटस	डिप्लोमा होल्डर्स
अम्बाला	10147	15555	4978	560	268
कुरुक्षेत्र	2368	5357	2174	280	68
करनाल	6056	13475	3790	497	173
रोहतक	8020	11323	3031	1570	257
सोनीपत	5156	7510	2016	159	146
जीन्द	2889	5022	1507	142	69
भिवानी	4717	4619	1886	142	39
गुडगांव	14206	11389	4004	382	266
महेन्द्रगढ़	5505	5355	2051	341	29
हिसार	4245	8494	2439	335	139
सिरसा	1319	2404	915	173	65
योग	64628	90503	28791	4581	1519

नोट:- (1) मैट्रिक से कम, मैट्रिकुलेटस, ग्रेजुएटस, पोस्ट ग्रेजुएटस जिनकी संख्या ऊपर दी गई है, मे वे सभी

प्रार्थी सम्मिलित हैं जिन्होंने अपना नाम भिन्न भिन्नच व्यवसायों में दर्ज करवाया हुआ है।

(2) उपरोक्त जो आंकड़े दिये गये हैं वे 31-12-78 तक हैं न कि 1-1-79 तक क्योंकि ये आंकड़े मास की समाप्ति तक एकत्रित किये जाते हैं।

(ख) उपरोक्त के भाग (क) में जिन प्रार्थियों की संख्या दी गई है उनमें से वर्ग अनुसार विकलांग प्रार्थियों की संख्या नीचे दी जाती है :-

वर्ग	विकलांग प्रार्थियों की संख्या जो दिनांक 31-12-78 को रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे
मैट्रिक से कम	359
मैट्रिकुलेटस	463
ग्रेजुएटस	80
पोस्ट ग्रेजुएटस	34
डिप्लोम होल्डर्स	भाून्य
योग	936

राव दलीप सिंह: मंत्री महोदय ने बताया कि 64 हजार एजुकेटिड परसैंज अनएम्पलायड हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको रोजगार देने का कोई टाईम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया है ?

चौधरी भजन लाल: पढे लिखे बेरोजगार लड़कों के लिए सरकार ने बहुत तेजी से कदम उठाये हैं हम देहातों में उद्योग धन्धे खोलने जा रहे हैं पढे लिखे बेरोजगारों को 10 हजार से एक लाख रुपये तक के ऋण दिये जायेंगे जिस पर एक परसैंट सूद होगा और 15 परसैंट सबसिडी दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने 15 तारीख से 22 तारीख तक औद्योगिक सप्ताह स्टेट में मनाया है। इसके अन्तर्गत हम गांवों में जाकर लोगों को उद्योग धंधे लगाने के बारे में समझाते हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय ने 58 साल से 55 साल की रिटायरमेंट एज करके जो हर साल बेरोजगारी की समस्या बढ रही है उसको दूर करने का तरीका अपनाने की कोशिश की है ?

चौधरी भजन लाल: सरकार के सामने ऐसा कोई मसला विचारधानी नहीं है कि रिटायरमेंट एज 58 से 55 साल कर दी जाये।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया है कि स्माल स्केल फैक्टरियों का प्रबंध कर दिया गया है परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवर एज को चुके हैं क्या उनकी

ओवर एज को कंसिडर किया गया है ?

चौधरी भजन लाल: ऐसी बात नहीं है, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 27 साल की एज को बढ़ाया जाये ताकि वे ओवर एज न हों।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि पढे लिखे बेरोजगारों की बेकारी दूर करने के लिए सरकार ने रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज खोलने का प्रोग्राम बनाया है जिससे बहुत जल्दी ही बेरोजगारी दूर हो जाएगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट जींद में 45 यूनिट लगे हैं, जिसमें 135 आदमियों को काम मिला है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अगर इस रफ्तार से काम करते रहे तो कितने साल में इस प्रोग्राम को पूरा कर लेंगे ?

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने 200 यूनिट लगाए जिनमें 1200 लडकों को काम मिला है। उन लडकों का सारा खर्चा निकाल कर लगभग हजार ग्यारह सौ रुपए प्रति मास की इनकम हुई है।

चौधरी लाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो सामान गांवों में लघु उद्योग द्वारा तैयार होगा उसको सेल्ज टैक्स और औक्ट्राय ड्यूटी में छूट होगी ?

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, उनको 5 साल के लिए सैल्ज टैक्स, बिजली के सरचार्ज और औक्ट्राय ड्यूटी की पूरी छूट होंगी।

चौधरी गया लाल: उपाध्यक्ष महोदय, कई विभाग अपनी मर्जी से रिक्लूटमेंट कर लेते हैं। खासतौर से जो मंत्री जी का कोआप्रेटिव विभाग है, उसमें आम तौर से बगैर एम्पलायमेंट एक्सचेंज से भर्ती की जाती है। रोजगार विभाग में जिनके नाम दर्ज हैं उनमें अपंग लडकों भी हैं और दूसरे भी हैं जो सर्विस से वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार ऐसा कोई विचार करेगी कि इन विभागों में भी बगैर एम्पलायमेंट एक्सचेंज के न लिए जाएं ?

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ आदमी डेली वेजिज पर रख लेते हैं इन्होंने कोआप्रेटिव विभाग का नाम लिया है, यह महकमा मेरे पास है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम 50 परसेंट नाम एम्पलायमेंट से मंगाते हैं बाकी 50 परसेंट की एप्लीके इन इनवाइट करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू लेकर सिलैक्ट इन करते हैं।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासनी हुए।)

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा स्टेट में हैंडीकैप्ड लोगों में अधिकतर अंधे हैं जिनमें एम0ए0 पास भी हैं और एम0एस0, पी0एच0डी0 भी हैं। उनके लिए सर्विस में न कोई प्रैफ्रेंस है और न कोई रिजर्वे इन दी जाती है। क्या मंत्री

महोदय बतायेंगे कि उनको प्रैफ्रैंस या रिजर्वे इन देने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दिया जा चुका है कि सरकार का रिजर्वे इन देने का कोई विचार नहीं है। अगर मंत्री जी चाहें तो बता सकते हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हैंडीकैप्ड के लिये हमने आयु में बड़ी भारी छुट रखी है। दूसरे लडकों की सर्विस एज 27 साल है जबकि हैंडीकैप को हम 37 साल तक की एज तक लगाते हैं अगर वह कुआलीफाई करता हो तो सबसे पहले उनको लगाते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो आंकड़े उन्होंने सदन के पटल पर रखे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए पिछले दो साल में चाहे एजूकेटिड हों चाहे अनएजूकेटिड हों, बेरोजगारों की संख्या बढी है या घटी है ?

श्री अध्यक्ष: संख्या तो हमें 11 बढती रहती है घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट में कम से कम दो लाख 90 हजार लडकों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं। इनमें नाम हर साल बढते हैं घटते नहीं क्योंकि हर साल एक लाख लडके पढ लिख कर तैयार हो जाते हैं इनमें से हज 20 या 22 हजार को सर्विस दे पाते हैं। हर तरह हर साल बेरोजगार बढते हैं घटते नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के चुनाव घोशणा पत्र में यह वायदा है कि हम 10 साल में बेरोजगारी की समस्या को मुकम्मल तौर पर दूर कर देंगे। क्या दस साल के अर्से को मद्देनजर रखते हुए इन दो सालों में भी अनुपाती तौर से बेरोजगारी घटाने का टारगैट पूरा किया गया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और हम 10 साल की बजाये 8 साल में बेरोजगारी की समस्या दूर करना चाहते हैं।

श्री सुमेर चन्द्र भट्ट: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने एलान किया है कि हम 8 साल में बेरोजगारी की समस्या दूर कर देंगे ? क्या उस अनुपात में रूरल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आव यक पूंजी का कोई प्रबन्ध वजीर साहब ने किया है ?

चौधरी भजन लाल: उनके लिए सरकारी पूरी तरह से जागरूक है और इनके लिए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

Teachers/Teachresses belonging to Scheduled Casts and Scheduled Tribes

***1125. Swami Agnivesh :** Will the Minister for Education be pleased to state

(a) the total number of teachers/teachresses working in the Govt. Colleges and Schools in the State at present;

(b) the total number of teachers/teachresses belonging to Scheduled Castes & Scheduled Tribes out of those referred to in part (a) above; and

(c) whether the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is complete in all categories; if not, the steps taken or proposed to be taken to complete the reserved quota of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) 49326

(बी) 3553

(सी) नहीं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित कबीलों के लिए आरक्षित पदों को स्वीकृत माध्यम द्वारा भरने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी का मसला है, मोस्त इम्पोर्टेंट सवाल है इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: चार दिन बजट की डिबेट के लिए हैं और उसके बाद तीन दिन डिमांडज पर डिस्कशन के लिए हैं। 7 दिन का मौका है जो कि मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेन्टिड है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफी टाईम मिलेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अध्यक्ष महोदय, क्या आप हमें पूरा टाईम देंगे ?

श्री अध्यक्ष: जितने भी आपके मैम्बरज हैं उन सब को टाईम मिलेगा।

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारी सेवाओं में 22 परसेंट पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं लेकिन जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं। उनके मुताबिक परसेंटेज 20 बैठती है। सारे हरियाणा में इस समय 50 हजार अध्यापक हैं। 50 हजार में कम से कम 11 हजार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के होने चाहिए लेकिन उसकी जगह केवल 3500 हैं। आजादी के 32 साल बाद उनका इतना कम कोटा पूरा हुआ है। क्या शिक्षा मंत्री महोदय अनुभव करते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अध्यापक ही नहीं हैं या नौकरी के लिए उनकी कोई डिमांड ही नहीं है ? मंत्री जी कब तक 22 परसेंट कोटा पूरा करने का वि वास दिलाते हैं ?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जहां दूसरे कारण है वहां यह भी एक कारण है कि इन कैटेग्रीज के ट्रेड टीचर्ज उपलब्ध नहीं होते हैं जिसके कारण ये स्थान पूरे नहीं हो पाए हैं और 1968 के बाद कुछ टीचर्ज का सिलैवस ही प्रौपर नहीं किया गया।

श्री जगन नाथ: मंत्री महोदय ने कहा है कि ट्रेड टीचर्ज नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं 10, 20, 50 या 100 ट्रेड

टीचर्ज इनके पास लाऊं तो क्या मन्त्री महोदय उनको लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री हीरा नन्द आर्य: मैंने बताया है कि 1968 के बाद जे0बी0टी0 टीचर्ज की सिलैव न नहीं हुई। जब कोई सिलैव न होगी तो कोिाा करेंगे कि िाडयूल्ड कास्टस और िाडयूल्ड ट्राइब्ज का कोटा पूरा हो जाए।

चौधरी गया लाल: मन्त्री जी ने बताया है कि कोटा पूरा करने की कोिाा करेंगे लेकिन बहुत से टीचर्ज 1968 से बेकार बैठे हैं। क्या कोटा पूरा करने के लिए इन बेकार जे0बी0टी0 अध्यापकों को लगाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: यह तो हम जानते हैं जब तक वेकैंसी खाली नहीं होगी तब तक कैसे लगाएंगे और कैसे कोटा पूरा हो सकता है ? मन्त्री जी ने यह तो आ वासन दिया है कि पूरी कोिााा करेंगे कोटा पूरा करने की। (व्यवधान)

चौधरी गया लाल: जितनी वेकैंसीज हों, उनको तो पूरा करने की कोिााा करें (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: जैसा कि मैंने अभी सदन को बताया कि क्रमिक पद्धति चालू की गई है और इस पद्धति के अन्तर्गत विेश रूप से कोिााा करेंगे कि रिक्त पदों को भरा जाए।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार स्कूल अप ग्रेड कर रही है और दूसरी तरफ टीचर्ज की

कमी है। क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए सेंट पर सेंट हरिजन भरती करके इस कमी को पूरा करेगी ?

श्री हीरा नन्द आर्य: जब सिलैबान होगी उस वक्त क्रमिक पद्धति के अनुसार कोटा पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

श्री दीप चन्द भाटिया: स्पीकर साहब, 22 परसेंट पिछड़ी जातियों का कोटा मुकर्रर किया हुआ है। क्या सरकार हम जैसे लोगों को जो स्वर्ण जाति के लगे हुए हैं, उनको टर्मिनेट करके डिडयूल्ड कास्टस का कोटा पूरा करने की कोशिश करेगी ? (हंसी)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भले राम: मंत्री महोदय ने बताया कि स्कूलों में तकरीबन 50 हजार टीचर्ज लगे हुए हैं। क्या ये 50 हजार टीचर्ज ट्रेण्ड लगे हैं या अनट्रेण्ड हैं ?

श्री अध्यक्ष: सरकार जो टीचर लगाती है वह ट्रेण्ड ही लगाती है। (व्यवधान) यह कोई सवाल नहीं बनता।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: क्या सरकार के विचाराधीन यह बात है कि कास्ट को छोडकर के आधार पर हर महकमे में रिजर्वेशन की जाए ?

श्री अध्यक्ष: यह मूल सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या शिक्षा मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो परसेंटेज कांग्रेस भासनकाल में पूरी नहीं हुई थी, उसका कमी को पूरा करने के लिए जनता सरकार को पता चलेगी ?

श्री हीरा नन्द आर्य: इतने सालों से भी ज्यादाती होती रही है उसको क्रमिक पद्धति के अंतर्गत पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खाली रिक्तियों को कैरी फारवर्ड करके भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बार बार क्रमिक पद्धति का नाम लेकर कह रहे हैं कि क्रमिक पद्धति के द्वारा लोगों को भर्ती किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह क्रमिक पद्धति क्या चीज है, इसका क्या अर्थ है ?

श्री हीरा नन्द आर्य: इसका मतलब है रोस्टर सिस्टम।

स्वामी अग्निवेश: मैं क्रमिक पद्धति शब्द का अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ वह तो मैं जानता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सिस्टम क्या है ? (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्वामी जी मेरे दफतर में आ जाएं, मैं उनको बता दूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती भान्ति देवी: क्या शिक्षा मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने जो 14 हजार जे0बी0टी0 टीचर्स को रैगुलर

किया है, इन में अनुसूचित जातियों और जन जातियों का कोटा पूरा किया है या नहीं ?

श्री हीरा नन्द आर्य: जितने अनुसूचित जातियों और जन जातियों के व्यक्ति थे उनको रैगुलर कर दिया गया है लेकिन कोटा पूरा नहीं हुआ है।

चौधरी खुर पीद अहमद: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि रोस्टर सिस्टम जिसको मन्त्री महोदय ने क्रमिक कहा है, इस पद्धति को बनाने का क्या बेसिज है, किस तरह तैयार की जाती है और इसके तैयार करने का आधार क्या है ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

Hospital at Jhajjar

***1088. Capt. Mange Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Civil Hospital Jhajjar, is only a 25 beded Hopital;

(b) whether ther existing in dorr patient's accommodation in the hospital referred to above is sufficenet to meet the reuirement of the patients of the Jhajjara Sub Division area;

(c) if reply to part (b) above be in the negative whether thee is any proposal under consideration of the Government to vonvert this hospital into a 50 bedded hospital; and

(d) if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

कैप्टन मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय सवाल का जवाब देने में बड़ी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने (ख) पार्ट का जवाब दिया है "कोई ि िकायत प्राप्त नहीं हुई।" स्पीकर साहब, झज्जर सब डिवीजन में सिर्फ 24 बैडज का हस्पताल है। मरीज ज्यादा हैं और कई बार मरीजों को एक एक महीना हस्पताल के बाहर ठहरना पड़ता है। इन्होंने सवाल के जवाब में कह दिया "ि िकायत नहीं आई" वहां पर पूरी जनता की आबादी 25 हजार हैं (हंसी)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आदरणीय सदस्य को सवाल पूछने दीजिए।

कैप्टन मांगे राम: मेरा कहने का मतलब यह है कि भाहर की आबादी 25 हजार है और इलाके की मांग है कि 24 बैडज की बजाए 50 बैडज का हस्पताल बनाया जाए। क्या मंत्री जी बैडज की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कैप्टन मांगे राम ने प्रथम बार यह प्र न किया है और इसके अतिरिक्त आज तक कोई रैजोल्यू िन वहां से पास होकर नहीं आया और न उन्होंने स्वयं कभी कहा है कि वहां पर 50 बैडज की आव यकता है। ब्रिटि िा स्कीम के अन्तर्गत जो परिवार कल्याण का कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत 6 बैडज और बढ़ाए जाएंगे और इसके अतिरिक्त छोटा सा आप्रे िन थियेटर भी बढ़ाया

जाएगा। 50 बैडज तक बढान का प्र न सरकार के विचाराधीन नहीं है, जैसे जैसे वहां से डिमांड आती जाएगी, हम उस वक्त सोच लेंगे।

15.00 बजे।

चौधरी राम किान: अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जिस नीति का एलान किया गया है उसके अनुसार हर कांस्टिचुएँसी के एक बडे गावं में 25 बैड का हस्पताल खोला जाएगां क्या मंत्री जी सदन में यह वि वास दिलाएंगी कि ये हस्पताल कब तक खोल दिए जाएंगे ?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: धन की उपलब्धि के अनुसासर सब जगह के लिये स्कीमें बना रहे हैं।

चौधरी खुरािद अहमद: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां जहां 25 बैडज के हस्पताल बने हैं उनमें 70—70 और 100—100 इनडारे पै ंटस की तादाद को देखते हुए बैडज की कैपेसिटी बढाने के लिए वे दोबारा गौर करेंगी ?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: प्र न झञ्जर का है, आप मेरे आफिस में आ जाए, बात कर लेंगे। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया से जब भी हम कोई क्वै चन पूछते हैं तो ये गोल मोल जवाब दे देती हैं

श्री अध्यक्ष: ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, हम कई बार मंत्री महोदय के नोटिस में लाए हैं कि ऐलनाबादी की आबादी कम से कम 40 हजार है लेकिन वहां एक बैड का भी हस्तपाल नहीं है। क्या मंत्री जी बताएंगी कि ये वहां कब तक हस्पताल बनाने का विचार रखती हैं ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): नारायणगढ़ के बाद।
(हंसी)

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं आया।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ऐलनाबाद के बारे में पहले भी कहा जा चुका है। सी०एम० साहब द्वारा दिए गए आवासन और अन्य जरूरत के मुताबिक जिन पांच छः हस्पताल खोले जाने का एलान किया जा चुका है उसके बाद ही बजट के प्रोविजनल के अनुसार दूसरी जगहों पर हस्पताल बनाने की बात पर सरकार विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: अब तो आपको बड़ा स्पष्ट जवाब मिल गया है। जिन हस्पतालों के बारे में सी०एम० साहब पहले अनाउंस कर चुके हैं वहां पहले हस्पताल खोलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे हस्पताल खोले जाएंगे।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मेरे हलके में दो गांव हैं जमालपुर और बडवा। उन्होंने पिछले साल सरकार से यह प्रार्थना की थी कि हस्पताल के लिए तीन या चार लाख रुपये की जितने की भी सरकार बिल्डिंग बनवाना चाहे वे बना देंगे। उसके नक्शे नीचे से तो पास हो गए थे हैल्थ डिपार्टमेंट ने भी पास कर दिए थे लेकिन वित्त मंत्री जी के यहां से वे रिजेक्ट हो गए। तो मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि अगर लोग अपने पैसे से बिल्डिंग बना दें तो वहां हस्पताल खोलने की मंजूरी क्या हैल्थ डिपार्टमेंट देगा या फाईनैस डिपार्टमेंट देगा ?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: दोनों ही देते हैं।

श्री जगन नाथ: क्या नक्शा भी फाईनैस डिपार्टमेंट पास करता है ?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: नक्शा तो हैल्थ डिपार्टमेंट पास करता है लेकिन स्टाफ और दवाईयों आदि पर जो खर्च होना होता है वह फाईनैस डिपार्टमेंट की मंजूरी से होता है। (विधन) स्पीकर साहब, आदरणीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहती हूं कि केवल बिल्डिंग बनने से ही हस्पताल नहीं चला करता। उसके लिए स्टाफ भी चाहिए और दवाईया भी चाहिए। यह खर्च जैसा मैंने पहले कहा फाईनैस डिपार्टमेंट की मंजूरी से होता है।

***1017. Shri Jai Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state

(a) the attention, if any, being paid by the Government towards the poor quality, old and badly damaged buses or Rohtak depot; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide new buses to this depot during this current financial year; if so, the number thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह ओलला):

(क) रोहतक डिपो की बसों की दशा को सुधारने के लिए पूरा ध्याना दिया गया है। अब इस डिपो की यातायात स्थिति अच्छी है।

(ख) हां जी। 49 नई बसें अब तक रोहतक डिपो को इस वित्तीय वर्ष में दी जा चुकी हैं और 35 नई बसें मार्च 1979 तक दे दी जाएंगी।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के गांवों में जो बसें भेजी जाती हैं, वे लगभग बिना खिडकी के होती हैं, उनकी बुरी हालत होती है, और वे आधे रास्ते में रुक जाती हैं जिसकी वजह से यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि ऐसी रद्दी बसों को कंडम करके अलग कर दिया जाएगा और देहातो में अच्छी बसें भेजी जाएंगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, कुछ दिन पहले कैथल डिपो से सम्बंधित सवाल हाउस के सामने आया था। उस रोज मैंने बताया था कि भायद 5 या 7 बसें ऐसी थीं जिनके भी 10 नहीं लगे हुए हैं। और मैंने यह अडवोर्सेस दी थी कि उन बसों में भी 10 एक हफते के अंदर अंदर लग जाएंगे। (विधन) दूसरी जगहों की बसों का जहां तक संबंध है, उनकी इन्फर्मेसन तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। इस वक्त तो मेरे पास रोहतक की इन्फर्मेसन है। वहां 7 बसें ऐसी हैं जिनके भी 10 नहीं हैं और इस वक्त ये वक्त गौप में खड़ी हैं, गांवों में नहीं चल रही हैं।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, बसों की खस्ता हालत वर्क भाउपर्स में होने वाली हेराफेरी की वजह से है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वर्क भाउप्स पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कोई कडे कदम उठाए गए हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला : इसके बारे में तो माननीय सदस्य रोज अखबारों में पढते ही होंगे कि किस तरह से चेंकिंग हो रही है। स्पैसिफिकली कैथल डिपो कार जहां तक संबंध है, उसके बारे में माननीय सदस्य को मालूम ही है कि वहां पर सी0एम0 साहब ने किस प्रकार स्टोर की चेंकिंग कराई और स्टोर कीपर आदि को नहीं बल्कि जी0एम0 को भी सस्पेंड किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में पूरा ऐव नेशन लिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस तरह की चोरी बिल्कुल बंद हो जाएगी।

चौधरी खुर गीद अहमद: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ये बताएंगे कि जिस तरह कैथल डिपो की चेंकिंग कराई गई, उस तरह दूसर डिपोज की चेंकिंग कराने के बारे में भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी, अगर करेगी तो कितनी जल्दी होगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर को यह समझना चाहिए कि अगर हाउस में इस बारे में बता दिया जाए तो चेंकिंग हो नहीं सकती। इस तरह की चेंकिंग तो अचानक ही हुआ करती है।

चौधरी सरदार खां: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बतायेंगे कि गुडगांव और पलवल डिपो को कितनी नई बसें दी गई हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: गुडगांव डिपो को 76 नई बसें दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष: यह कितने अर्से में दी गई हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला : एक साल में।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी से पूछना चाहता हूँ कि नारायणगढ को कितनी नई बसें दी गई हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला : नारायणगढ को तीन बसें दी गई हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे जींद डिपो में बहुत दिनों से कोई जनरल मैनेजर जाने के लिए तैयान नहीं है, इसका क्या कारण है ? क्या जनरल मैनेजर को वहां जल्दी भेजने की कोशिश की जाएगी ?

चौधरी देवी लाल: जहां तक जीन्द का ताललुक है वह सेंट्रल प्लेस है और सरकार इस बारे में सोच रही है। सरकार तो इस हद तक सोच रही है कि जीन्द को ऐसा डिपो बनाया जाये कि सभी डिपो उससे गाईडेंस लें और वहीं से कंट्रोल भी किया जा सके।

स्वामी आदित्यवे 1: मिनिस्टर साहब ने जवाब में बताया है कि गुडगांव को 76 नई बसें दी गई हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे गुडगांव में ही चलती है या बाहर चलती हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: अगर आप सारी बसें गुडगांव में ही चलवायेंगे तो फिर कमाई कहां से होगी ?

स्वामी आदित्यवे 1: अम्बाला को छोड़ कर सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को गुडगांव जिले से होती है। यह जिला हरयाणा का सबसे बड़ा जिला भी है। आमदनी भी ज्यादा है। फिर भी गुडगांव जिले में खराब बसें क्यों चलाई जा रही हैं ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री देवी दास: मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि सोनीपत का जो सब डिपो है, क्या वहाँ पर भी नई बसें चलाई जायेंगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: हर डिपो और सब डिपो पर नई बसें दी जायेंगी। आठ साल के बाद बस रिप्लेस कर दी जाती है। सोनीपत में भी बसें गई हैं। अगर आप रोहतक के बारे में पूछना चाहते हैं तो बता देता हूँ। रोहतक में 84 नई बसें गई हैं।

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

नियम के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारंकित प्र नों के लिखित उत्तर

Quantity of Contry Liquor

***1098. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the quantity of country liquior in litres for the purchase of which permits were issued to t he country liquor vendors by the Government during the period from 1-4-76 to 31-3-77, 1-4-77 to 31-3-78 and 1-4-78 to 31-1-79 separately in the State ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

1-4-1976 से 31-3-1977	5995959.600 पूफ लिटर
-----------------------	----------------------

1-4-1977 से 31-3-1978	5685378.500 प्रूफ लिटर
1-4-1978 से 31-1-1979	3233125.00 प्रूफ लिटर

**Rendering of Agricultural Land unproductive by
Factories in Faridabad Complex**

***1115. Ch. Rajender Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether the State Government is aware of the fact that hundreds of acres of agricultural land in the neighbourhood of various factories set up at Faridabad Complex have been rendered unproductive as a result of the flow from there of waste matter i.e. used chemicals in these lands; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, the steps so far taken or proposed to be taken to check further loss to the farmers on this account ?

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) Since the matter has come to the notice of the Government in the Agriculture Department very recently, detailed survey of the area will be made to consider what steps be taken in the matter. The Agriculture Department would render suitable technical advice to the farmers concerned and assist them in securing loans for reclaiming the land rendered unproductive.

Further, the Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution proposed to launch prosecution proceedings under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 as amended in 1978 against those 4 industries in the Fariabad complex which before the discharge of their waste matter do not treat it in accordance with the standards laid down by the said State Board within the fixed period permitted to them for the purpose.

Strengthening of Audit in Cooperative Societies

***1117. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state

(a) the total number of Cooperative Societies audited during the year 1978-79 in the State;

(b) the number of cases and the amount involved in the embezzlement cases detected during the year 1978-79; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to increase the strength of audit staff to check the cases of embezzlement in the Cooperative Societies ?

**Cooperation and Dairy Development Minister
(Ch. Bhajan Lal):**

(a) 4368 (1-7-78 to 31-1-1979).

(b) 156 cases involving amount of Rs. 19.43 lakhs (1-7-78 to 31-1-1979).

(c) Yes.

Enhancement of Daily Wages of the Labourers

***1126. Swami Agnivesh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to fix Rs. 12 per day as daily wages to the labourers working in P.W.D. in the State ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी नहीं ।

Disparity in the pay and other amenities amongst the Drivers in the State

***1144. Ch. Khurshid Ahmed:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that there is a difference in the pay-scales; special pay, uniform allowance etc. of the Civil Secretariat Drivers and the Drivers working in the other Departments; if so, the reasons therefor ?

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): हां। यह अन्तर इस कारण है कि हरियाणा सिविल सचिवालय के ड्राइवरज की कार्य प्रकृति कठिन प्रकार की है क्योंकि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवत्र मंत्रियों के साथ कार्य करना पडता है।

Provision of water for irrigation puposes

***1146. Shri Raghu Nath Goyal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that only one side of the land of villages Mansa, Pharanswal, Mange-Majri in the Kaithal Constituency is irrigated and other side remains unirrigated; and

(b) whether there is any scheme under consideration of the Government to provide water for the other side of villages as referred to in part (a) above; if so, the time by which the water is likely to be provided there ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) नहीं जी।

गांव मानव, फरांस वाला तथा मांगे माजरी कैथल हलके की भूमि की सिंचाई दोनों ओर से होती है।

(बी) सरकार के पास को ऐसी स्कीम विचाराधीन नहीं है, जो कि इन गांवों की जमीन को दोनों ओर से सिंचाई कर सकें, क्योंकि इनमें पहली ही दोनों ओर से सिंचाई हो रही है।

**Scholarships to the students belonging to Scheduled
Castes and Backward Classes**

***1148. Ch. Bhagmal:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the monthly rate of scholarships being paid to the students studying in the High Schools belonging to the Scheduled Castes and the Backward Classes, respectively;

(b) the date from which the said rate is being paid to them;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to raise the amount of scholarships being paid to the students belonging to the Schedule Castes and Backward Classes in the State; and

(d) if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) 8 रु० प्रतिमास ।

(ख) 1-4-1970

(ग) तथा (घ) हां। दिनांक 1-4-1979 से स्टार्डिपेंड की दर 8/-रु० प्रतिमास से 16/-रु० प्रति मास बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

Regularisaion of services of workcharged employees

***1159. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to regularise the services of workcharged employees working in the Irrigation Department; and

(b) if so, the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) जिस वर्कचार्ज्ड अमले की सेवा अवधि 31-12-78 को 5 वर्ष या इससे अधिक है उसे रैगुलर स्थापना पर लाने हेतु मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

Appreciation letters to the employees

***983. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the number of employees who has been given appreciation letters since inception of the Printing and Stationery Department;

(b) the basis on which the appreciation letters are issued ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(क) एक।

(ख) वर्ष के दौरान अधिकारी के समस्त कार्य के समूचे मूल्यांकन के आधार पर, बहुत ही अच्छे कार्य के लिये प्र संसा पत्र जारी किये जाते हैं।

Ad Hoc employees

***1158. Sh. Mange Ram Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the President of India had issued a notification dated 10th June, 1977 vide which the services of about 15000 ad hoc employees of Haryana who had completed one year's service on 31st March 1977 were to be regularised;

(b) whether it is also a fact that the said notification by the President of India was later on withdrawn by the Janata Government even after the Chief Secretary to Government Haryana, has issued the circular to all the Heads of Departments for immediate necessary action and even in some cases orders were issued to the employees regularising their services; and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative the reasons for withdrawing the said notification and the circumstances under which it was withdrawn ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) जी हां।

(ख) जी हां। इस अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा मंसूख किया गया था, वापिस नहीं लिया गया था।

(ग) इस अधिसूचना को मंसूख करने के लिए मुख्य औचित्य यह था कि सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए और तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

Loans or grant for the development of panchayats

***915. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) the amount of loan or grant advanced by the Government for the development of each Panchayat during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the State;

(b) the amount of the loan or grant advanced to each Panchayat for making them resourceful and for setting up Industries togetherwith the detail of each such Panchayat which received the loan or grant during the period as referred to in part (a) above; and

(c) the nature of the Industries for which the loan was advanced ?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) हरियाणा राज्य में 5260 ग्राम पंचायतें हैं यद्यपि पंचायत बार सूचना उपलब्ध है, यह बहुत लम्बी हैं फिर भी, यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष पंचायत के बारे में यह सूचना देखना चाहता है तो वह उसको उपलब्ध कर दी जाएगी।

तथापि सदन की सूचना के लिए अनुदानों / ऋणों की खण्डवार सूची जो कि सरीकार ने राज्य में 4-7-77 से 30-6-78 तक पंचायतों के विकास के लिए दी है, सदन के पटल पर रखी है।

(ख) सरकार ने जिन पंचायतों को राजस्व आय योजनाएं चलाने के लिए सीधे ऋण दिये हैं, उसकी भी एक सूची सदन के पटल पर रखी जाती है। पंचायतों को उद्योग लगाने के लिए कोई अनुदान/ऋण नहीं दिया गया।

(ग) उपरोक्त उत्तर के अनुसार भाग (सी) का प्र न
ही नहीं उठता।

सूची (क)

हरियाणा राज्य में 4-7-77 से 30-6-78 तक पंचायतों को [अनुदान/ऋण](#) दिए जाने की खंडवार सूची।

क्रमांक	खंड का नाम	पंचायत समितियों द्वारा पंचायतों को विकास के कार्यों के लिये दिए गए अनुदान			पंचायत विभाग द्वारा पंचायतों को सीधे दिए गए अनुदान/ऋण	
		पंचायतों की संख्या	राशि	पंचायतों की संख्या	ग्रान्ट	राजस्व आय योजना के अन्तर्गत ऋण
जिला रोहतक						
1	रोहतक	12	49418.00	30	13318.85	20000 / -
2	साम्पला	37	190153.00	29	9654.40	

3	महम	2	9600.00	23	16834.85	
4	बेरी	20	77600.00	32	10178.01	
5	चिडी	8	25700.00	24	11595.77	
6	बहादुरगढ	6	25700.00	54	13469.82	
7	नाहड	8	29500.00	72	11543.40	
8	साहलावास	21	77127.00	72	11399.05	
9	कलानौर	24	89229.02	38	16501.57	
10	झज्जर	28	68539.00	56	13685.95	
		166	648024.70	430	127182.95	20000 / -
जिला कुरुक्षेत्र						
1	थानेसर	40	63850.00	82	24127.00	

2	कैथल	41	81089.81	74	32275.65	
3	लाडवा	56	43430.00	125	24289.25	
4	भाहबाद	18	39700.00	91	19076.25	20000 / -
5	गुहला			87	35426.50	
6	पुंडरी	2	20000.00	65	25735.70	
		157	648069.81	524	160930.35	20000 / -
जिला सिरसा						
1	डबवाली	14	36000.00	71	47290.72	10000 / -
2	सिरसा	11	2600.00	95	45355.78	10000 / -
3	बडागढा	10	26250.00	61	37639.83	
4	रानियां	15	30000.00	45	49064.27	

		50	118250.00	272	179350.60	20000 / -
जिला अम्बाला						
1	अम्बाला	32	59000.00	112	15629.18	20000 / -
2	जगाधरी	26	34720.00	78	14892.16	
3	रायपुर रानी	30	77335.00	78	10515.76	
4	नारायणगढ	53	47450.00	88	12553.26	
5	पिंजौर	16	65620.00	31	3364.38	
6	बराडा			84	15323.50	
7	बिलासपुर			54	8494.56	
8	छछरौली			172	11469.50	
		157	284125.00	697	92242.30	20000 / -

जिला जीन्द						
1	जीन्द	7	25500.00	57	20418.33	
2	कलायत	23	43100.00	51	28838.77	10000 / -
3	जुलाना	42	64150.00	43	19630.20	
4	नरवाना	36	131816.00	40	19628.53	
5	राजौंद	60	70525.00	39	23357.65	
6	उचाना			50	27726.95	10000 / -
7	सफीदों			64	22242.27	
		168	335091.00	344	161842.70	20000 / -
जिला गुड़गांव						
1	नूंह	28	52500.00	87	13122.27	10000 / -

2	बल्लभगढ़	37	60650.00	57	10536.02	
3	फरीदाबाद	80	79353.00	32	5543.25	
4	हथीन	4	9512.62	66	9512.62	
5	पलवल	70	75516.00	85	15447.55	
6	गुड़गांवा	34	63133.00	62	11999.91	10000 / -
7	पुनहाना	3	7390.00	59	4398.21	
8	सोहना	22	55636.00	101	8946.63	
9	पटौदी	43	60140.00	62	11673.48	
10	फिराजपुर झिरका	53	56040.00	83	8163.52	
11	होडल	6	14000.00	58	16238.54	
		380	533870.62	752	115582.00	20000 / -

जिला सोनीपत						
1	खरखौदा	26	41000.00	39	10730.81	10000 / -
2	राई	10	14750.00	63	10328.39	
3	कथूरा	18	92000.00	20	8923.39	
4	गन्नौर	17	24265.00	78	14600.50	
5	गोहाना	21	47700.00	35	11500.50	10000 / -
6	मुंडलाना	16	65500.00	34	12884.45	
7	सोनीपत			209	15309.21	
		108	285215.00	478	84277.34	20000 / -
जिला हिसार						
1	हांसी-2	23	43700.00	33	19089.92	

2	रतिया	15	24800.00	44	33140.50	10000 / -
3	हिसार-1	26	37366.79	26	16461.70	
4	हिसार-2	18	73414.80	58	26085.77	
5	नारनौंद	14	76216.00	33	15918.30	
6	हांसी-2	10	25210.00	35	20813.60	
7	बरवाला	22	87203.00	19	31827.73	
8	भूना	15	58500.00	49	36405.15	
9	टोहाना	29	83000.00	57	21836.20	10000 / -
10	फतेहाबाद	15	39000.00	55	34398.63	
		187	548410.59	409	255977.50	20000 / -
जिला करनाल						

1	करनाल	40	50380.00	90	18653.30	
2	निसिंग	50	44220.00	41	11716.00	10000 / -
3	नीलोखेड़ी	34	27720.00	97	22894.60	
4	घरौंडा	31	38020.00	55	18349.50	
5	असन्ध	38	28070.00	31	10692.52	
6	पानीपत	12	17600.00	66	14654.38	
7	संभालखा	6	30440.00	37	10887.00	10000 / -
8	मडलौडा	25	30554.00	42	17714.45	
		236	267004.00	459	125561.65	20000 / -
जिला भिवानी						
1	बाढड़ा	14	37000.00	50	25157.50	10000 / -

2	लोहारू	35	43000.00	16	8061.00	10000 / -
3	तो ाम	1	1880.00	45	22243.20	
4	भिवानी	1	5000.00	80	37770.60	
5	दादरी-1			57	28266.65	
6	दादरी-2			53	21173.45	
7	बवानी खेड़ा	30	98700.00	59	45080.65	
		81	185580.00	360	187753.05	20000 / -
जिला महिन्द्रगढ़						
1	कनीना	24	59000.00	60	9896.30	
2	खोल एट रिवाड़ी	17	33500.00	43	4994.20	
3	अटेली नंगल	42	114287.00	68	6643.05	

4	नारनौल	26	50500.00	53	5086.89	
5	महिन्द्रगढ़	36	103640.00	59	9277.89	
6	रिवाड़ी	18	50000.00	59	8896.79	79
7	जाटुसाना			53	8966.73	
8	नंगल चौधरी	37	92015.00	60	6657.90	
9	बावल			61	7714.10	10
	जोड़	200	502942.00	516	65133.85	
	कुल जोड़	1890	3956582.72	5241	1555834.01	20000 / -

सूची (ख)

पंचायतों को 4-7-77 से 30-6-78 तक दिए गए ऋण की सूची।

क्रमांक	पंचायत का ना	खंड का नाम	राशि	उद्देश्य
जिला सिरसा				
1	चुटाला	डबवाली	10000 / -	दुकानें बनाने के लिये
2.	बैदवाला	सिरसा	10000 / -	ट्यूबवैल लगाने के लिये
जिला हिसार				
3	सहनात	रतिया	10000 / -	ट्यूबवैल लगाने के लिये
4	भरसूल खुर्द	टोहाना	10000 / -	ट्यूबवैल लगाने के लिये

				लिये
जिला सोनीपत				
5	रोहट	खरखौदा	10000 / -	दुकानें बनाने के लिये
6	कसन्डी	गोहाना	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिये
जिला करनाल				
7	चिड़ाओ	निसिंग	10000 / -	दुकाने बनाने के लिए
8	भाहर मालपुर	संभालखा	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए
जिला अम्बाला				
9	बरनाला	अम्बाला	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए

				लिए
10	जन्डहेडी	अम्बाला	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए
जिला भिवानी				
11	बिलावल	बाडड़ा	10000 / -	पम्पिंग सैट लगाने के लिए
12	दीघवांजटां	लोहारू	10000 / -	पम्पिंग सैट लगाने के लिए
जिला जीन्द				
13	दूमडा	कलायत	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए
14	खटकड़	उचाना	10000 / -	दुकानें बनाने के लिए

जिला रोहतक				
15	बसन्तपुर	रोहतक	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए
16	बलियाला	रोहतक	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए
जिला गुड़गांव				
17	उजीना	नूंह	10000 / -	दुकानें बनाने के लिए
18	डन्डाहेड़	गुड़गांव	10000 / -	दुकानें बनाने के लिए
जिला कुरुक्षेत्र				
19	मोहड़ी	भाहाबाद	10000 / -	दुकानें बनाने के लिए
20	छपरा	भाहाबाद	10000 / -	टयूबवैल लगाने के लिए

				लिए
		कुल जोड़	200000 / -	

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Shifting of Haryana State Electricity Board Offices from Chandigarh to Hissar

***264. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the expenditure incurred on shifting Haryana State Electricity Board to Hissar together with the amount of T.a. given to the employees;

(b) the total number of employees transferred from Chandigarh to Hissar togetherwith the arrangement made for their accommodation; and

(c) whether adequate accommodation has been provided for the office on shifting from Chandigarh to Hissar; if not, the name of the place where the work is being done at Hissar ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)	(1)	स्थानान्तरण पर हुआ खर्चा (केवल अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का कार्यालय अभी तक हिसार ले जाया गया है।)	64955 रुपए
	(2)	कर्मचारियों को दिया गया भत्ता	70133 रुपए

(ख)	(1)	स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों की संख्या	161
	(2)	प्रारम्भ में कर्मचारियों को अकेले ठहरने की जगह दी गई। कुछ कर्मचारियों ने अपनी हकदारी के अनुसार जगह प्राप्त कर ली है। उनसे उनके वेतन का 10 प्रति शत मकान किराये के रूप में वसूल किया जा रहा है और उनको अनुमोदित निर्धारित किराये की अदायगी की जा रही है।	
(ग)		जी हां। मिनी सैक्रिटेरियेट भवन में पर्याप्त स्थान उपलब्ध कर दिया गया है।	

Murthan Water Supply Scheme

***272. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether the work on Murthal Water Supply Scheme for the supply of water to the Municipal Committee, Sonapat, has been started; if so, the time by which it is likely to be completed; and

(b) the time by which the work on the Naggal Lift Scheme for the supply of drinking water to Ambala City is likely to be started ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) हां, इसके 30-6-1979 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ख) नग्गल लिफ्ट सिंचाई योजना के दो चरण हैं। पहले चरण का कार्य दिसम्बर 1975 में आरम्भ किया गया था और जिसके जुलाई 1979 तक सम्पन्न होने की सम्भावना है। जहां तक इस योजना के दूसरे चरण यानि पंजोकड़ा माईनर का सम्बन्ध है, इस चरण का अभी तक प्रारम्भिक अनुमोदन नहीं हुआ है। नग्गल लिफ्ट सिंचाई योजना के दोनों चरण सतलुज यमुना लिंक परियोजना से पानी का सप्लाई पर आधारित हैं जो कि पंजाब में बनाये जाने वाले फीडर सिस्टम से पानी प्राप्त करेंगे। अतः इस समय नग्गल लिफ्ट सिंचाई स्कीम के पूर्ण होने की कोई निश्चित तिथि का आवाहन नहीं दिया जा सकता।

इस समय अम्बाला भाहर की जनसंख्या लगभग 102000 हैं अब 14.00 लाख गैलन पानी नगर को प्रतिदिन सप्लाई किया जाता है जो कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 14 गैलन बनता है। इस समय 23.37 लाख रुपए के अनुमान के अधीन कार्य किया जा रहा है और इस अनुमान का कार्य पूर्ण होने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की सप्लाई 20 गैलन हो जायेगी। इसके अतिरिक्त

नगल लिफट योजना पर आधारित जल वितरण योजना के सम्पन्न होने के पचात प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सप्लाई 40 गैलन हो जायेगी।

Standard prescribed for H.C.S. (Judicial) examination

***273. Ch. Peer Chand:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the standard prescribed for passing the H.C.S. (Judicial) examination at present and the standard prescribed for passing the said examination at the time when the State of Haryana came into being;

(b) the number of persons who have been declared pass in the said examination held since 1971 to date; and

(c) whether all the persons as referred to in part(a) above have been appointed; if so, the percentage of the persons belonging to Scheduled Castes amongst them ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) दिनांक 6-6-1974 से वर्तमान स्थिति यह है कि एच0सी0एस0 (न्यायिक भाखा) की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी पेपरों के कुल अंकों में से जिसमें मौखिक परीक्षा के अंक भी शामिल हैं, निर्धारित अंक 55 प्रति त प्राप्त करने होते हैं किसी भी उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा के लिये नहीं बुलाया

जाता जब तक कि वह सभी लिखित पेपरों में कुल 45 प्रति 10 अंक तथा हिन्दी भाषा (देवनागरी लिपि) के पेपर में 33 प्रति 10 अंक प्राप्त नहीं करता। हरियाणा राज्य बनने से लेकर 5-6-1974 तक जब इन नियमों को संशोधित किया गया था। एच0सी0एस0 (न्यायिक भाखा) की परीक्षा पास करने के लिये भाषा अर्थात् हिन्दी भाषा (देवनागरी लिपि) के पेपर में 33 प्रति 10 अंक तथा सरे पेपरों के कुल अंकों का जोड़ 45 प्रति 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। किसी भी उम्मीदवार को किसी पेपर में 33 प्रति 10 से कम अंक प्राप्त करने का लाभ नहीं दिया जाता था।

(बी)	1974	1976	1978
	12	22	परिणाम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(सी) वर्ष 1974 और 1976 में एच0सी0एस0 (न्यायिक भाखा) की परीक्षा के परिणामरूप 34 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए सफल घोषित किया गया था इनमें से 30 उम्मीदवारों को एच0सी0एस0 (न्यायिक भाखा) में नियुक्त किया गया था। अनुसूचित जाति से सम्बंधित केवल एक ही उम्मीदवार को 1976 की परीक्षा में नियुक्ति के लिये चुना गया परन्तु उसने कार्यभार नहीं सम्भाला।

Trade Unions in the State

***275. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) the names of the registered Trade Unions in the State as on 31-12-1978; and

(b) the number of members of the said Trade Unions separately, together with the names of the Federation on All India level to which those are affiliated ?

Co-operation and Dairy Development Minister

(Ch. Bhajan Lal):

(a) and (b) The statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name of Trade Union	Member ship	Affiliation
1	Kendriya Rajya Farm Workers Union, Hissar	106	INTUC
2	Military Farm Employees Union, Ambala Cantt.	24	AIDEF
3	Equine Breeding & Civilian Workders, Union, Hissar	120	AIDEF
4	N.M.D.C. Employees Union III/20 M.L.N.	Not available	

	Colony, N.I.T. (National Mineral Development Corporation Faridabad.		
5	Govt. of India Press Workeres Union, Faridaba (Bharat Sarkar Mudralaya Karamchari Sangh, Faridabad)	515	BMS
6	Govt. of India Press Workers Union, Nilokheri.	364	INTUC
7	Govt. of India Press Employees Union, Nilokheri	311	BMS
8	H.M.T. Karmik Sangh, Pinjore	3611	
9	Railway Venders Union, Rly. Road, Gurgaon	Not available	
10	Indian Oil (R&D) Employees Association C/o Indian Oil Corpn. Ltd., R&D Centre, Sector 13, Faridabad	Do	
11	Postal & RM.S. Bank Employees Association, Ambala Cantt	Do	

12	The Employees Association of Postal and R.M.S. Employees Coop. Bank, Ambala Cantt.	Do	
13	Central Bank of India Employees Association, Ambala Cantt.	Do	
14	Central Bank of India Employees Union, Ambala Cantt.	826	AIBEA
15	Punjab National Bank Employees Union, Dass Market, Rly. Road, Rohtak	1079	AIBEA
16	Defence Civilian Employees Union, 3484, Opp. Police Station, Ambala Cantt.	25	AIDEF
17	Cantt. Board Workers Union, 3498 Timber Market, Ambala Cantt.	Not available	
18	Cantt. Fund Employees Association, 2744, Sardar Bazar, Ambala Cantt.	31	
19	M.E.S. Workers Union, 3484, Sadar Bazar,	Not available	

	Ambala Cantt.		
20	Air Force Civilian Karamchari Union, Rly. Road, Gurgaon	210	BMS
21	The Luxmi Commercial Bank Employees Union, Ram Niwas, Sri Nagar Colony, Jagadhari	Not available	
22	Land Mortgage Bank Employees Union c/o Haryana State Land Mortgage Bank Ltd., Ambala City.	Do	
23	The Central Coop. Bank Employees Association, H.No. 2018, Rori Bazar, Sirsa.	Do	
24	Central Coop. Bank Employees Union, Jail Road, Gurgaon	98	
25	Central Coop. Bank Employees Union, Jhajjar Road, Rohtak	Not available	
26	The Central Coop. Bank Employees Association	51	

	Karnal		
27	Haryana Agro Farm Employees Union, H.No. 17, Mohalla Ahira, Near Livestock Farm, Hissar	300	CITU
28	Govt. Livestock Farm Employees Union, Mill Road, Near Tempo Stand, Hissar.	Not available	
29	N.D.R.I. Employees & Workmen Union Mazdoor Manzil, Karnal	Do	
30	Progency Testing Farm Workers Union, Hissar	110	
31	Equine Breeding & Civilian Workers Union Nagori Gate, Hissar	Not available	
32	I.A.R.I. Employees & Workmen Union, Karnal	39	INTUC
33	H.D.D.C. (Milk Plant) Workers Union, 214 Durga Nagar, Ambala City.	Not available	
34	Haryana Brewaries Workers Union, Opp.	Do	

	Aggarwal Dharamsala, Sonepat.,		
35	Haryana Tenneries Employees Union, Hansi Raod, JInd	Do	
36	Haryana Poly Steel Workers Union, B-19, Power House Colony, N.I.T., Faridabad	313	CITU
37	Faridabad Power House Workers Union, B-19, Power House Colony, N.I.T., Faridabad	Not available	
38	Haryana Bijli Board Karamchari Parishad C/o B.M.S. Mahabir Road, Faridabad	1990	BMS
39	HMITE Workers Union 214, Durga Nagar, Hissar Road, Amabala City.	Not available	
40	The HSEB Diploma Holder Association, Subhash Gate, House No. B-10, Karnal	Do	
41	Haryana Rajya Bijli Board Karamchari Sangh, Ram		

	NIwas Building, Sadar Bazar, Karnal		
42	HSEB Workers Union, Nagori Gate Hissar		
43	Municipal Committee Water Supply Workers Union, Faridabad	Not available	
44	Fourth Class Canal Employees Union, Near Bharat Cinema, Jind	664	HMS
45	Haryana Tubewell Operator Union, H.No. D-K25, Mohalla Patwar, Karnal	Do	
46	Haryana MITC Engg. Staff Association D.K. 25, Mohallat Patwar, Karnal	Do	
47	Municipal Water Supply Employees Union, Sharam Shivar Workshop Road, Yamunanagar	Do	
48	Water Works Workers Union, Municipal Committe, H.No. 4573/3, Near Hari Mandir, Ambala	Not available	

	City.		
49	Teh Employees and Workers Union of the Ambala Central Coop. Consumer Store, Ltd. H.NO. 245, Lal Kurti, Ambala City.	Do	
50	Haryana Roadways Workers Union, Rohtak.	Do	
51	Haryana Warehousing Coop. Employees Association, Panipat.	373	
52	Sonepat Central Coop. Bank Employees Union, 2/216, Kath Mandi, Sonepat	132	CITU
53	Coop. Bank Employees Association, Near Rly. Station, Hissar	Not available	
54	Haryana State Coop. Marketing Federation Employees Union, Ambala Cantt.	125	HMP
55	Municipal Employees Union, Jagadhri.	19	

56	Municipal Subordinate Union, Yamunanagar	60	BMS
57	Municipal Subordinate Federation, Ambala City.	Not available	
58	Nagarpalika Karamchari Sangh, Jagadhri.	250	BMS
59	Ambala City. Cantt. Board Karamchari Sangthan, Ambala Cantt	Not available	
60	Municipal Employees Union, C/o Gurucharan Dass, Kalka	Do	
61	Municipal Subordinate Union, C/o Kundan Lal Sharma, Islamia School, Sadhora	25	BMS
62	Amabal Nagarpalika, Karamchari Union, Kalibari Sadar Bazar, Ambala Cantt.	Not available	
63	Faridabad Development Board Clerk Association, Faridabad	Do	
64	Municipal Subordinate Service Federation	Do	

	Khatanwara, Faridabad		
65	Nagarpalika, Karamchari Sangh, Faridabad	508	BMS
66	Municipal Committee Workers Union, IA 90, Faridabad	Not available	
67	Nagarpalika, Karamchari Sangh, Sohna	Do	
68	Nagarpalika, Karamchari Sangh C/o Jagdish Chander Goyal, Mohalla Jatwara, Sonapat	Do	
69	Govt. Medical Store Depot. Workers Union, C/o11, Civil Line, Karnal	Do	
70	Govt. Medical Store Depot Employees Union, Mazdoor Manzil, Sant Nagar, Karnal	150	INTUC
71	Haryana Govt. PWD Mechanical Workers Union, Charkhi Dadri.	2967	
72	All Haryana PWD Workers Union, H.No. 4520, Sabzi Mandi, Ambala Cantt.	Not available	

73	Janata Haryana PWD Workers Union, H.No. 881, Purani Mandi, Karnal	Do	
74	Municipal Employees Union, Mohindergarh.	12	
75	Municipal Employees Union, Bus Stand, Narnaul.	Not available	
76	Nagarpalika, Karamchari Sangh, H.No. 6053, Mohalla Khasapur, Rewari.	Not available	
77	Municipal Karamchari Sangh, Mohalla Tejpura, Gokal Gate, Rewari.	54	
78	Municipal Karamchari Sangh, Bhiwani.	83	NLO
79	Municipal Employees Union, INTUC, 3217, Charkhi Dadri.	Not available	
80	Municipal Employees Lower Grade Staff Union, Hansi.	73	
81	Municipal Employees	77	

	Union, Nagori Gate, Hissar		
82	Nagarpalika, Karamchari Sangh, 351-B, Hissar	Not availabl	
83	Municipal Employees Union, Sirsa.	Do	
84	Palika Karamchari Sangh, Sirsa.	Do	
85	Municipal Karamchari Sangh Association, C/o Jai Kumar Driver, Engg. College, Kurukshetra, Thanesar.	Do	
86	Municipal Employees Workers Union, C/o Dev Raj, Octroi Supdt. Pehowa.	120	BMS
87	Municipal Subordinate Union, Radaur.	23	
88	Municipal Karamchari Union, C/o Goyal Boot House, Main Bazar, Kaithal.	118	BMS
89	Distt. Municipal Subordinate Union,	NA	

	Shyam Nagar, Karnal		
90	Municipal Karamchari Union, C/o Nathu Ram, Advocate, Karnal	318	BMS
91	Adarsh Union, Municipal Karamchari c/o BMS Office, G.T. Road, Panipat.	215	BMS
92	Nagarpalika, Karamchari Union, Main Bazar, Jind.	77	BMS
93	Faridabad Fire Service Employees Union, Fire Station, NIT, Faridabad	10	
94	Municipal Safai Karamchari Sangh Workshop Road, Yamunanagar	140	INTUC
95	Cantt. Board Sweeper Union, 328/2 Sadar Bazar Ambala Cantt.	Not available	
96	Ambala Municipal Safai Mazdoor Ekta Union, Double Storey, Ram Nagar, Ambala City.	Do	
97	Nagarpalika, Safai	Do	

	Mazdoor Union, H.No. 142 Model Colony, Yamunanagar		
98	Municipal Safai Mazdoor Union, H.No. 130 Mahabari, Thanesar.	Do	
99	Municipal Employees Union, and Sweeper Union, Meham	32	
100	Khetihar Mazdoor va Kissan Sangh, Bhiwani.	4255	NLO
101	Haryana Khet Mazdoor Union, G.T. Road, Panipat.	2700	All India Agricultural Workers Union
102	Haryana Kheta Mazdoor Federation, W-III, No. 506, Rohtak.	32839	UTUC
103	Haryana Khetihar Congress Sharm Shivar Workshop road, Yamunanagar	Not available	
104	Haryana Krishi Workers Union, 214 Durga Nagar, Ambala City.	Do	

105	Khan Mazdoor Sangh, Vill. Khativas P.O. Charkhi Dadri, Bhiwani.	Do	
106	The Akhil Bhartiya Mazdoor Shora Association, Rewari	Do	
107	Haryana Milk Food Employees Union, Foji Ward No. 5, Madan Shali Gurudwara, Pehowa.	106	AITUC
108	Karnal Rice, Oil, Cotton & Flour Mills Workers Union, Karnal	10	
109	Kaithal Mazdoor Union, Amargarh, Kaithal.	Not available	
110	Saraswati Sugar Mills, Mazdoor Union, Yamunanagar	440	INTUC
111	Saraswati Industrial Syndicate Workers Union, C/o Pt. Madhusudan, Jagadhri.	120	
112	Sugar Mill Labour Union, Yamunanagar	169	BMS
113	Sugar Mill Karamchari	200	INTUC

	Union, B-16, Dharamvir Colony, Sugar Mills, Panipat.		
114	The Panipat. Sugar Mills Mazdoor Sabha H.No. 24, W. NO. 12, Kishanpura, Panipat.	Not available	
115	Sugar Mills Mazdoor Sangh C/o BMS Office Pachranga Bazar, W.No. 9, H.NO. 923, Panipat.	602	BMS
116	Haryana Coop. Sugar Mill Mazdoor Union, Circular Road, Rohtak.	Not available	
117	Radaur Cane Growers Coop. Society Karamchari Union, Radaur.	24	
118	Oil & Flour Mills Labour Union, Gali Dakhanwali, Rohtak.	Not available	
119	B.D. Ice Factory Labour Union, Ambala	7	
120	Bharat Starch Mills Labour Union, Starch Mill Colony, Yamunanagar	100	INTUC

121	Bharat Starch and Chemical Workers Union, Yamunanagar	140	BMS
122	Haryana Distillery Employees Union, C/o 21 M.Modi Mill, Yamunanagar	40	INTUC
123	Modi Mill Workers Union, Yamunanagar	Not available	
124	Panipat Sugar Mills & Distillery Janata Mazdoor Sangh, Panipat.	Do	
125	Bidi Cigarette Salesman Union, Ambala Cantt.	Do	
126	Textile Mazdoor Union, 18/64 NIT, Faridabad	Do	
127	Usha Spinning and Weaving Mills, Mazdoor Union, Mathura Road, Faridabad	Do	
128	Kapra Mill Mazdoor Union, NIT, Faridabad	Do	
129	Textile Labour Union, Association, Industrial Area-90, NIT, Faridabad	Do	

130	Textile Workers Union, Gurgaon.	100	INTUC
131	Textile Mazdoor Sangh, Faridabad	4460	BMS
132	Textile Mill Mazdoor Union, H.No. 214, 4 Marla Colony, Gurgaon.	300	AITUC
133	Elson Cotton Mill Mazdoor Union, Ballabgarh.	Not available	
134	Suti Mill Mazdoor Union, 2/21 Gopi Colony, Faridabad	426	CITU
135	The Bengal National Textile Karamchari Union, I.A. 54, NIT, Faridabad	Not available	
136	Jawala Textile Mills Mazdoor Sangh, Sadar Bazar, Gurgaon.	500	BMS
137	Distt. General Textile Union, NIT, Faridabad	Not available	
138	Delhi Faridabad Textile Mazdoor Union, 97 Ahirawara, Ballabgarh.	Not available	

139	Textile Mazdoor Sangh, Panipat.	700	BMS
140	Khadi Karamchari Sangh, W.No. 1, Kishanpura, Panipat.	110	BMS
141	TIT Karamchari Sangh, Lohar Bazar, Bhiwani.	2222	NLO
142	Textile Mazdoor Sangh, Bhiwani.	1692	NLO
143	Mazdoor Sabha, Bhiwani.	Not available	
144	Vaster Udyog Mazdoor Sangh, 116 Labour Colony, Bhiwani.	657	BMS
145	Kapra Mill Mazdoor Sangh, 116 Labour Colony, Bhiwani.	1702	BMS
146	BTM Staff Union, 116 Labour Colony, Bhiwani.	40	BMS
147	Textile Karamchari Sangh Bhiwani.	Not available	
148	HTM Workers Union, 91 HTM Colony, Hissar,	Do	
149	Hissar Textile Mazdoor	Do	

	Sangh, Q.No. G-94, HTM Colony, Hissar		
150	Distt. Textile Workers Union, Hissar.	Do	
151	Mazdoor Hitkari Mandal Mill Colony, Hissar	461	AITUC
152	Lal Jhanda Kapra Mazdoor Union, inside Nagori Gate, Hissar	650	CITU
153	HTM Mazdoor Union, Q.No. 54-C, HTM Workers Colony, Hissar	Not available	
154	Gopi Chand Textile Mazdoor Sangh, Sirsa.	400	
155	Mohan Spinning Mill, Mazdoor Sabha, Sugar Colony, Rohtak.	300	
156	Mohan Spinning Mills, Mazdoor Sabha, Rohtak.	200	AITUC
157	Janta Textile Mazdoor Sangh C/o Shri Gurdial Singh Ratana, H.No. 19, Behind Vesh College, Rohtak.	393	BMS

158	Modi Textile Corpn. Mazdoor Union, Village & P.O. Rai, Sonapat	Not available	
159	Textile Workers Union, 2/216 Kath Mandi, Sonapat	130	
160	Kapra Udyog Karamchari Union, Sonapat	Not available	
161	Engg. & Textile Workers Union, Panipat.	950	AITUC
162	The Wool Khadi Workers Union & Labour Colony, IA Panipat.	310	AITUC
163	Endee Woolen & Silk Mills Mazdoor Union, Faridabad	Not available	
164	Bharat Carpet Workers Union, Faridabad	Do	
165	Bharat Carpet Karamchari Union, IA 119 NIT Faridabad	Do	
166	Minica-India Employees Union, D.B. 97, Ahirwara W.No. 2, Ballabgarh.	Do	

167	Ara Mazdoor Sangh C/o INder Sein, Devi Bazar, Yamunanagar	280	BMS
168	Gurgaon Distt. Wood Workers Union, Badri Niwas,Rly. Road, Gurgaon.	Do	
169	Saw Mills and Wood Workers Union, Ekta Bhawan, NIT, Faridabad	220	AITUC
170	The Punjab Business Supply Co. Workers Union, Sharam Shivar Workshop Road, Yamunanagar	132	HMS
171	Shri Gopal Paper Mills Labour Union, Yamunanagar	1462	INTUC
172	Shri Gopal Karamchari Union, C/o Inder Sein. Devi Bazar Jagadhri Road, Yamunanagar	120	BMS
173	Faridabad Paper & Stationery Workers Union, IF 25, NIT, Faridabad	125	AITUC

174	Bharat Carbon Ribbon and Murari Paper Mills Workers Union, Faridabad	315	BMS
175	Bharat Carbon Ribbon Workers Union, Faridabad	Not available	
176	Indo-Box and Closures Workers Union, H-55, Press Colony, Faridabad	Do	
177	Press Karamchari Union, Anaj Mandi, Ambala Cantt.	21	
178	Panchkula Printing Press Workers Union, Panchkula	Not available	
179	Thomson Press Sharamik Sangh, Faridabad	Do	
180	Thomson Press Workers Union, Faridabad	Do	
181	Printers House Mazdoor Union, Ballabgarh.	Do	
182	Press Workers Union, Rohtak.	75	BMS

183	Karnal Leather Workers Union, Karnal	Not available	
184	Bata Shoe Workers Union, Shop No. 148-49 Tikona Park, Faridabad	700	AITUC
185	Bata Karamchari Sangh near Adarsh Dharam Kanta, NIT, Faridabad	670	BMS
186	General Rubber Co. Mazdoor union, IA 90, Faridabad	Not available	
187	Superseals Employees Union, IA 16, Mathura Road, Faridabad	265	INTUC
188	Rubber Industries, Mazdoor Sangh, Faridabad	775	BMS
189	Rubber Workers Union, Rly. Road, Gurgaon.	Not available	
190	Good Year Employees Union, Ballabgarh.	1005	INTUC
191	Radhika Rubber Karamchari Union, 2H-116, Faridabad	Not available	

192	Dabur Employees Union, IE 61 NIT, Faridabad	Do	
193	Consolidated Plastic Mazdoor Union, Ahirwara, B-57, Ballabgarh.	12	
194	Neuchem Employees Union, 54 NIT, Faridabad	256	BMS
195	Chemical construction Co. Workers Union, Faridabad	Not available	
196	Chemical Workers Union, 2/216, Kath Mandi, Sonapat	500	
197	Chemical Industries Employees Union, C/o Shri Amar Singh Sharma in front of Govt. Girls Middle School No. 1, NIT, Faridabad	461	NLO
198	Bhandari Chemical Karamchari Sangh Faridabad C/o BMS near Adarsh Dharam Kanta, Faridabad	30	BMS
199	Hindustan Gum and Chemical Mazdoor Union,	80	BMS

	Sangh, 116 Labour Union, Bhiwani.		
200	Bhatta Mazdoor Union, Yamunanagar	242	CITU
201	Bhatta Mazdoor Union, near Rly. Workshop, Jagadhri.	265	CITU
202	Bhatta Workers Union, Rly. Road, Gurgaon.	Not available	
203	Hindustan Vaccum Glass Workers Union, IA 22, NIT, Faridabad	Do	
204	Glass and Ceramics Workers Union, Faridabad	150	AITUC
205	Hindustan National Glass Karamchari Sangh, Bahadurgarh.	133	BMS
206	HNG Mazdoor Union, Rohtak Road, Bahadurgarh.	305	INTUC
207	Hitkari Brothers Mazdoor Union, Faridabad	458	NLO
208	Potteries Workers Union,	Not	

	Rly. Road, Gurgaon.	available	
209	Potteries Mazdoor Union, Sangh C/o BMS Sadar Bazar, Gurgaon.	Not available	
210	Bahadurgarh. Potteries General Labour Union, Bahadurgarh.	611	NLO
211	Bahadurgarh Potteries Workers Union, Nihal Bhawan, Jhannar Road, Bahadurgarh.	Not available	
212	Hindustan Tyford Workers Union, Plot No. 43, Lal Chand Colony, Bahadurgarh.	556	INTUC
213	Somani Pilkington (P) Ltd. Workers Union, Kassar (Bahadurgarh)	256	NLO
214	Somani Pilkington Mazdoor Union, Sangh, Kassar	Not available	
215	BC Workers Union, Surajpur	480	AITUC
216	BC Karamchari Union, P.O. BCW, Surajpur	610	INTUC

217	Mahila Quarry Workers Union, Malla, Pinjor	610	INTUC
218	Chandi Mandir Workers Union, Q-A-3-F-10 BCW, Surajpur.	Not Available	
219	Bhupindra Cement Mazdoor Ekta Union, C/o Shri Gurbaksh Singh I Type Quarter No. B-42, Surajpur	250	
220	Dalmia Dadri Cement Factory Men's Union, Charkhi Dadri.	1650	INTUC & INCCWE
221	Cement Workers Union, Charkhi Dadri.	118	INTUC
222	Cement Udyog Kagar Sanh, C/o Pt. Nandya Pakkar Dutt Charkhi Dadri.	978	BMS
223	Hyderabad Asbestos Cement Products Employees Union, Ballabgarh.	620	INTUC
224	Spun Pipe Workers Union, 29-IA, Faridabad	Not Available	

225	Hyderabad Asbestos Karamchari Sanhg Shop 9, Mohna Road, Ballabgarh.	Do	
226	Bhushan Industries Corpn. & Spun Pipe Workers Union, Chandimandrir (Ambala)	Do	
227	Pipe Construction Workers Union, House of Unity, PO, BCW Surajpur	Do	
228	Haryana Spun Pipe Factory Workers Union, D.K. Mohalla Patwar, Karnal	Do	
229	Kay Iron Workers Union, Yamunanagar	80	
230	Distt. Iron and Steel Workers Union, 214, Durga Nagar, Ambala Cantt.	Not Available	
231	Ashoka Alloys Steel Workers Union, Baldev Nagar, Ambala Cantt.	Do	
232	Orient Steel Workers Union, INTUC, Market	Do	

	No. 2, Faridabad		
233	Avon Service Employees Union, Ballabgarh.	56	BMS
234	Northern India Employees Union, W.No. 2, Ballabgarh.	Not Available	
235	Partap Workers Union, Chawla Colony, Ballabgarh.	Do	
236	Partap Steel Employees Union, DB No. 97, Ahirwaraa, Ballabgarh.	30	
237	Usha Rectifier Workers Union, C/o Usha rectifier Corpn. India, Faridabad	Not Available	
238	Oswal Steel Employees Union, C/o Sh. Chattar Singh, near Mahadev Madnir, Chawla Colony, Ballabgarh.	Do	
239	Dabriwala Steel Employees Union, C/o Tarlok Chand Gupta, Chawla Colony, Ballabgarh.	Do	

240	Orient Steel and Industries Employees Union, 2 No. Pakki Market C/o Shri Gajinderpal Ex. M.C. Faridabad	Do	
241	H.S.A. Mazdoor Union, Murthal C/o No.. 118, Industrial Colony, Sonapat	Do	
242	Loh Udyog Karamchari Sangh, Bahadurgarh.	340	BMS
243	The Sampla Iron and Foundry General Labour Union, Sampla	Not Available	
244	Sampla Industire3s Workeers Union, B Shivaji Colony, Rohtak	Do	
245	The Jindal Tube Factory Worker Union, Hissar	74	
246	Jindal Strips Factory Workers Union, Satroad Road, Hissar	234	
247	Metal Karamachari Sangh Jagadhri	250	BMS

248	Jagadhri Metal Mazdoor Sabhad Jagadhari	450	
249	Metal Worker Union Rly. Road, Jagadhri	Not Available	
250	Hindustan Ko-Ko-Ku Wires Workers Union, Faridabad	Do	
251	Bhaskar Workers Union Faridabad	Do	
252	Metal Box Employees Union, Faridabad	499	INTUC
253	Metal Box Monthly rated Staff Association, Faridabad	Not Available	
254	Elofic Industries Mazdoor Union, Faridabad	Not Available	
255	Mottern Industries Worker Union, Shati Bhawan, Faridabad	41	INTUC
256	Industrial Workers Union, Faridabad	405	AITUC
257	Bhai Sunder Dass Employees Union Faridabad	105	

258	Goel Industrial Corporation Mazdoor Union, N.I.T. Faridabad	Not Available	
259	Excelsior Plant Corpn. Employees Union, 90 Gajinder Pal Ex-MC Market Colony, Faridabad	Do	
260	Jotindra Steel & Tubes Employees Union, NIT Faridabad	Do	
261	Auto Metal and Agro Workders Union 5-B/37 NIT Faridabad	Do	
262	J.M.A. Industries Employess Union, 14/6 Mathura Road, Faridabad	Do	
263	Indusrial Workers Union, G.T. Road, Panipat	226	CITU
264	Indusrial Workers Union, Lohar Bazar, Bhiwani	333	NLO
265	Indusrial Workers Union, 238/8 Shivaji Colony, Rohtak	Not Available	
266	Bahadurgarh Engg. Mazdoor Sangh, C/o Shri	Do	

	Om Parkash Gupta, Gandhi chowk, Mandhoti Darwaza Bahadurgar		
267	B.S.T. Mazdoor Sangh, Ganaur	300	INTUC
268	B.S.T. Karamchari Union, Ganaur	Not Available	
269	Gedore Tools Workder Union, Opp. Agarwqal Dharamshala, Sonapat	Do	
270	General Engg. Workers Union, Sonapat	Do	
271	Agarwal Metal Karamchari Union, Rewari	308	
272	Kirloskar Oil Engine Union NIT, Faridabad	Not Available	
273	Chanderpur Works Workers Union C/o Mohan Lal Chanderpur Works, Yamunanagar	Do	
274	Frick India Workers Union, Faridabad	Do	
275	Frick India Employees Union, 9-H-54 NIT	Do	

	Faridabad		
276	Kelvinator of India Employees Union C/o INTUC Office Govt. Middle Girsls Sec. School, NIT Faridabad	Do	
277	Amiteep Workers Union C/o INTUC Shanti Bhawan, Faridabad	130	AITUC
278	General Engg. Mazdoor Union, I.A. C/o NIT Faridabad	200	INTUC
279	Hardware Mazdoor Sangh, Faridabad	102	BMS
280	Gedore Mazdoor Sangh, Faridabad	1950	BMS
281	Factory Workers Union C/o BMS Office H. No. 214, 4 Malra Colony, Gurgaon	250	AITUC
282	Eicher Tractors Employees Union, Faridabad	Not available	
283	Usha Telehoist Employees Union, Faridabad	Do	

284	Engg. Mazdoor Unio, H.No. 2, BMS Office Faridabad	2710	BMS
285	Dhanda Engg. Workers Union Plant-2, Faridabad	201	
286	Faridabad Engg. Workers Union nerar Syndicate Bank Faridabad	1700	AITUC
287	Engg. Mazdoor Union, Badri Niwas, Rly. Road, Gurgaon	Not available	
288	Escorts Employees Union, Mathura Road, Faridabad	300	AITUC
289	All Escorts employees Union, NIT, Faridabad	610	AITUC
290	Engineering Mazdoor Sangh, Char Marla Colony, Gurgaon	Not available	
291	Federation of Escorts Employees, E-41, Jawahar Colony, Faridabad	Do	
292	K.g. Khosla Workers Union, Aurangapur, Faridabad	200	NLO

293	Gedore Workers Union, NIT, Faridabad	2001	
294	Gurgaon Engineering Workders Union, H.NO. 214, Char Marla Colony, Gurgaon	200	AITUC
295	Gedore Tools Emplooyees Unions, Mathura Road, IA Faridabad	Not available	
296	Bico Engineering Employees Union, INTUC Faridabad	Do	
297	District General Engg. Employees Union, I.A. N.I.T. Faridabad	Do	
298	United Oils Mills Machinery Workers Union, M.r. Faridabad	Do	
299	Taylor Instrument Co. Employees Union, N.I.T. Faridabad	172	INTUC
300	Ply Cast Workeres Union, B-97, Phir Wara, Faridabad	Not available	
301	Bulbs Workers Union,	60	CITU

	Faridabad		
302	Ballabgarh Eeneral Employees Union, Ballabgarh.	Not available	
303	Olympus Employees Union, Saraikhawaja 124 M. Raoad P.O. Amar Nagar, Faridabad	Do	
304	Print pak Employees Union, Link Road, Faridabad	52	CITU
305	D.G.I. Employees Union, N.I.T., Faridabad	23	INTUC
306	Glob Steel Employees Union, Ballabgarh	Not available	
307	Ph. Inudustrial mazdoor Union, G.B. 97 W.No. 2, Ahirwara, Ballabgarh	Do	
308	General Engg. Employees Union, C/o Shri Amar Singh Sharma Opp. Girls Middle School No. 1, N.I.T., Faridabad	947	NLOI
309	Luxmi Rattan Engineering Workers Union, C/o	Not available	

	INTUC 179-A, Tikona Park, H.No. 1, Faridabd		
310	Gedore Staff Association C/o Gedore Tools India (P) Ltd. N.I.T., Faridabad	Do	
311	Engineering Workers Union, Gali Dakhana, Basant Bhawan, Rohtak	Do	
312	Adarsh Udyogic Karamchari, Rohtak	350	BMS
313	Hindustan Devidutt Workers Union, Jatheri	Not available	
314	Hindustan Devidutt Mazdoor Union, Jatheri	65	BMS
315	Engineering Mazdoor Union, Gita Bhawan, Sonapat	448	BMS
316	Beas Mazdoor Union, INTUC Bhawan, Bus Stand, Sonapat	Not available	
317	Hindustan Everest Tools, Yuva Kamgar Congress, Near Hindustan Everest Tools, Jatheri P.O. Rai	Do	

318	Mazdoor Ekta Union, Nagori Gate, Hissar	630	AITUC
319	Saraswati Engineering Works Workers Union, Yamunanagar	340	INTUC
320	Indo Workers Union 3671/1 Kalibari, Ambala Cantt.	Not available	
321	Jai Forgings Labour Union, C/o Jai Gorgingss, B-41, I.A. Yamunanagar	Do	
322	Karnal Mechanical & General Labour Union, Jullan Mohalla Karna,	450	BMS
323	Avery Factory Workers Union, Housing Board Colony, Faridabad	Not available	
324	Cutler Hammer Employees Union, Ballabgarh	Do	
325	Cutler Hammer Mazdoor Union, Ballabarh	Do	
326	Orient General Industries Workers Union, Faridabad	Do	

327	Dujodwala Industries Workeres Union, M.R., Faridabad	Do	
328	Delton Cable Employees Union, 2/21 Gopi Colony Faridabad	Not available	
329	Indian Aluminium Cable Employees Union, C/o Vaidji Ka Makan P.O. Amar Nagar	Do	
330	Hindustan Wires Employees Union, C/o Sh. Gainer Paul Ex-M.C., No. 2, Pakii Market Faridabad N.I.T.	Do	
331	Skytone Worker Union, 2- H/13, N.I.T., Faridabad	Do	
332	Industrial Cables (P) Ltd. Wrokers Union C/o Inder Singh V.P.O. Kila Naffargarh (Jind)	Do	
333	Auto Lamps Workers Union, Faridabad	Do	
334	Electronics Employees Union, DB 97, Ahirwara	Do	

	W. No. 2, Ballabgarh		
335	Universal Electrical Employees Union, Faridabad	Do	
336	Havell's Workers Union, Faridabad	Do	
337	Hindustan Electric Workers Union, A.I. 319, Faridabad	AITUC	
338	Prestolite Workers Union M.R. Faridabad	Not available	
339	Khosla Mazdoor Union, Faridabad	Do	
340	Devis & White Workers Union, Faridabad	Do	
341	Auto Pins Workers Union, N.E.T.I.A. Faridabad	Do	
342	Orient Electrical Workers Union, INTUC, Opp. Govt., Middle School (Girls) Faridabad	Do	
343	American Universal Electric Employees Union, 1341, Sector 15,	Do	

	Faridabad		
344	E.C.E. Workers Union, Sonapat	Do	
345	Telefunkan Workers Mazdoor Union, Ballabgarh	80	BMS
346	Payan Talbors Employees Union	Not available	
347	Escorts Karamchari Sangh, Faridabad	1250	BMS
348	Auto Meter Employees Union, INTGUC Nahar Singh Market, Ballabgarh	Not available	
349	Maruti Workers Union, H.No. 239/12 Lajpat Nagar Near Rly. Road, Gurgaon	Not available	
350	Janta Auto Workers Union, I.A., Yamuna Nagar	Do	
351	Yamuna Auto Indus. Employees, Chothi Line Radaur Raod, Yamuna Nagar	150	INTUC

352	Elofic Inds. Employees Union, Kothi No. 92, Sector 10, Faridabad	Not available	
353	Atlas Mazdoor Union, Sonapat	Not available	
354	Atlas Mazdoor Sangh, Sonapat	2840	BMS
355	Atlas Janta Workers Union, Near Atlas Shree Ram Mandi, Sonapat	Not available	
356	Pearl Cycle Workers Union, Ballabgar	Do	
357	Scientific Karamchari Union, Amabala Cantt.	Do	
358	Bijli Karamchari Union, H. No. 850 Mohalla, Bhaliam, Sirsa	36	ABTU
359	N.A.P. Employees Union, M.R. Faridabad	Not available	
360	Boaring Workers Union, Pehowa	Do	
361	Haryana Tubewell (EB) Mechanical Workers Union, Karnal	Do	

362	Haryana Tubewell Labour Workers Union, D.K. 25 Mohalla Patwar, Karnal	Do	
363	New Vishkarma Workers Union, R.B. Jagadhri	Do	
364	Trade ulazimin Union 5733/3 Chhota Bazar, Amabala City	121	
365	Muneem Union Usha Bazar, Jagadhri	130BMS	
366	Ambala Distt. Cycle Dealers Employees Union, Ambala Cantt.	Not available	
367	Zila Hissar Mandi Mazdoor Union, H.No. 322, a Block Sirsa	Do	
368	Rohtak Wholesale Merchant Association short Cloth Market, Rohtak	194	
369	Halwai Workers Union, Charikhi Dadri	Not available	
370	Rehri Mazdoor Union, C/o Fateh Chand Gulati, Rewari	Do	

371	Stores and Commercial Employees Union, Labour Bazar, Bhiwani	178	
372	Rehri Union Aggarwal Market, Rohtak	105	
373	Bhar Bhuja Workers Union, R.D. Ashok Gali, Rohtak	42	
374	Khokha Association N.I.T., Faridabad	Not available	
375	Gurgaon Khokha Union, Gurgaon	Do	
376	Chabba Khoncha Rehri Union, Near General Bus Stand, Sonapat	Do	
377	Haryana Medical Representative Association, Rohtak 213/19	Do	
378	Hissar Distt. Transport Workers Union, Nagori Gali, Hissar	Do	
379	The Gurgaon Transport Employees Union, 286, New Colony, Gurgaon	Not available	

380	Distt. Motor Transport Workers Union, Karnal	Do	
381	The Karnal General Transport Workers Union, Karnal	25	MTWF
382	Haryana Drivers Union, Panipat	Not available	
383	Haryana Transport Workers Union, Gali Dekkhama, Rohtak	Do	
384	Rohtak Delhi Transport Mazdoor Sangh B-VI 1314, Kala Stall, Rohtak	Do	
385	Tanga Union H.NO. 287, W.No. 5, Layalpur Baasti Kurukshetra	Do	
386	Distt. Goods Transport Workers Union, Karnal	Do	
387	Gainda mal Chiranji Lal Workers Union, Kalka	Do	
388	The Petroleum Carriers Workers Union, 124, Grand Hotel, Ambala Cantt.	40	

389	New Azad Truck Union, near Oil Pump, Faridabd	7	
390	Rickshaw Workers Union, Ambala Cantt.	986	
391	Janta Rickshaw Workers Union, Moh. Kajiwala, Ambala City	320	
392	Yamuna Nagar Rickshaw Pullars Union, Yamuna Nagar	Not available	
393	Yamuna Rickshwa Pullar Union, Y. Nagar	Do	
394	Azad Rickshaw Workers Union, 51, Prem Nagar, Ambala City	60	
395	Y. Nagar Jagadhir Paledar Union, Chhoti Line, Rador Road, Yamuna Nagar	Not available	
396	Faridabad Kamgar Unioin, 2/21 Gopi colony Parana, Faridabad	Not available	
397	Rickshaw Chalak Association, Faridabad	Do	
398	Rickshaw Pullars Union,	556	NMP

	Near Bharat Cinema, Jind		
399	Rickshaw Chalak Union, Bhiwani	Not available	
400	Bhiwani Thela Mazdoor Sangh, Bhiwani	96	NLO
401	Panppat Rickshaw Pullars & Workers Union, Panipat	Not available	
402	Distt. Rickshaw Pullars Union c/o Ram Parkash Chopra gohana Road, Tea stall, Rohtak	Do	
403	Sweepers Union Balmiki Nagar, Ambala City	Not available	
404	Sweepers Union Jagadhri	Do	
405	Safai Mazdoor Union Argali, Rewari		Do
406	Sweepers Union Balmiki Mandir, Hissar		Do
407	Safai Karamchari Sangh Balmiki Mohalla, Hansi	Do	
408	Safai Mazdoor Union Mohalla, Lakhi Talab, Sirsa		Do

409	Sweepers Union E-268, Moh. Ghasian, Karnal		Do
410	Sweepers Union Charkhi Dadri	58	INTUC
411	Safai Karamchari Union Balmiki Mohalla, Jind	11	Mazdoor Panchayat
412	Schedule Caste Workeres Employees Union Karnal	Not available	
413	Distt. Cinema Workeres Union, Hissar	14	
414	Haryana Cinema Employees Union 2022/2 Guru Nanak Pura, Ambala City	Not available	
415	All Haryana cinema Karamchari Union, Karnal		Do
416	Tailor Workers Union Gali Dakkhana Wali Rohtak		Do
417	Haryana Union & Working Jounalists, Partap Nagar, Rohtak		Do
418	Kabar Dealers Ass. Bata Chowk, Faridabad		Do
419	Tailor Workeres Union		Do

	Moh. Biko Wala, Hissar		
420	Mazdoor Union Rajgur Market, Hissar	Not available	
421	Handmade Utencils Mfg. Asso. Jagadhri		Do
422	The Ththera Union, Jagadhri		Do
423	Swatantara Thathera Cinema Devi Bhawan Jagadhri		Do
424	Haryana Employees & Industrial Organisation Station, Gurgaon		Do
425	The New Asso. of Indl. Employees Jaeob Pura, Gurgaon		Do
426	Commerce & Industrial Organisation, Faridabad	33	
427	Scrap Merchants Association Bata Chowk, Plot No. 8, N.I.T. Faridabad	Not available	
428	The Indian Watch Dealer & Repairs Asso. Karnal		Do

429	All India Cantt. Board Employees Fed. Ambala Cantt.	Not available	
430	Barbars Union, Jind	Do	
431	Frick India Karamchari Union, Faridabad	Do	
432	Workers Union, of the Haryana Minerals Limited, Narnaul	Do	
433	Government of India Photolitho Press Karamchari Sangh, Faridabad	Do	
434	Hath Rehri Workers Union, Karnal	300	
435	Haryana Tourism Karamchari Sangh, Karnal	Not available	
436	Hein Lehman Employees Union, Faridabad	50	NLO
437	Rickshaw Workers Union, Karnal	Not available	
438	Dabriwala Rolling Mills Workers Union, Faridabad	Do	

439	Perfect Pac Workers Union, Faridabad	Do	
440	Anand Synthetics Employees Union, Faridabad	Do	
441	J.M.A. Workers Union, Faridabad	Do	
442	Precision Stamping Employees Union, Faridabad	Do	
443	Auto Pins Employees Union, Plant I&II, Faridabad	Do	
444	Cultch Auto Employees Uion, Faridabad	Do	
445	Punjab Business & Supply Mazdoor Sangh, Yamuna Nagar	Do	
446	Kamal (Haryana) PR Centres Labour Union, Karnal	51	CITU
447	Rehri Chhaba Workers Union, Tohana	Not available	
448	Snowtemp Workers Union,	Do	

	Faridabad		
449	Haryana Udyog Sangh, Bhiwani	Do	
450	Barlur Mazdoor Sangh, Yamuna Nagar	Do	
451	Khet Mazdoor Panchayat, Jind	490	H.M. Panchayat
452	Sikand Employees Union, Faridabad	Not available	
453	Amar Foundry Workers Union, Ballabgarh	Do	
454	East India Cotton Employees Union, Faridabad	Do	
455	Faridabad Rubber Employees Union, Faridabad	Do	
456	Sugar Mills Workers Union, Karnal	Do	
457	Micro Precision Employees Union, Faridabad	Not available	
458	Flovel Workers Union, Faridabad	Do	

459	Northern Railway fourth Class Employees Union, Jind	Do	
460	Rentington Employees Union, Faridabad	Do	
461	Sugar Mills Employees Welfare Union, Karnal	Do	
462	Central Coop. Bank Employees Association, Ambala City	Do	
463	American Universal Electric (I) Ltd. Karamchari Union, Faridabad	Do	
464	Precision Steel Employees Union, Faridabad	Do	
465	Bhartiya Electric Steel Employees Union, Faridabad	Do	
466	Thomson Press Employees Union, Faridabad	Do	
467	Rubber Workers Union, Sonapat	Do	
468	Kurukshetra Central Coop. Bank Employees	Do	

	Association, Kurukshetra		
469	Chemical Mazdoor Union, Shahbad	98	AITUC
470	Central Coop. Bank Employees Union, Bhiwani	426	
471	Foundry & Mechanical Workers Union, Ambala City	Not available	
472	Holiday Inn & Faridabad Hotels Employees Union, Faridabad	Do	
473	National Fertilizers Employees Union, Panipat	500	Fertilizere Workers Federation of India
474	Goodyear Factory Staff & Employees Union, Ballabgarh	Not available	
475	Faridabad Complex Administration Employees Union, Faridabad	Do	
476	Sahni Suiting Kamgar Union, Faridabad	Do	

477	H.T.M. Mistry Union, Hissar	120	
478	Janta Orgno. Chemical Workers Union, Sonapat	Not available	
479	Forging Employees Union, Faridabad	Do	
480	H.T.M. Cleaks Association, Hissar	Do	
481	Top Style Employees Union, Faridabad	Do	
482	Haryana Refrectoris Employees Union, Ballabgarh	Do	
483	Freewheels India Employees Union, Faridabad	Not available	
484	H.S.E.B. Scheduled Castes/Tribes Association Panipat	1006	
485	Nagar Palika Sharmik Sangh, Pehowa	Not available	
486	Textile Mazdoor Sangh, Sonapat	Do	
487	Remington and	Do	

	Karamachari Union, Faridabad		
488	Hindustan Syringes Employees Union, Faridabad	Do	
489	Janta Labour Union, Kurukshetra	91	
490	Kapra Udyog Karamachari Union, Faridabad	Not available	
491	United Steel Workers Union, Yamunana Nagar	Do	
492	Multan Cycle Mazdoor Sangarsh Samiti, Sonapat	Do	
493	Municipal Employees Union, Yamuna Nagar	70	
494	All Haryana M.I.T.C. Employees Association, Karnal	Not available	
495	Polyfab Workers Union, Faridabad	Do	
496	G.M. Wrested Soinning Mills Employees Union, Faridabad	Do	
497	Marval Engineers &	Not	

	Traders Employees Union, Faridabad	available	
498	Hyderabad Asbestos Workers Union, Ballabgarh	Do	
499	Sonepat Sehkari Chini Mills Workers Union, Sonepat	Do	
500	Nibras Employees Association, Gurgaon	Do	
501	Sangarsh Samiti Udyogic Karamchari Sangh, Bhiwani	Do	
502	Good Year Factory Non Managerial Staff Employees Union, Ballabgarh	Do	
503	Loh Udyog Mazdoor Sangh, Bhiwani	136	BMS
504	Usha Electronics Employees Union, Ballabgarh	67	
505	Steel Authority of India Limited Employees Union, Faridabad	Not available	

506	Northern Indan and Steel Employees Union, Faridabad	Do	
Note:-	1. Please take Sr. No. 31 as delted 2. - denotes Independenat Unions. 3. N.A. Denotes not avaiבלable.		

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, आबकारी तथा कराधान मंत्री जी ने यहां हाउस में आ वासन दिया था कि बाद गहपुर गांव का ठेका उठा देंगे लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पडा रहा है कि पिछले दिनों दो लाख रुपए में फिर नीलाम कर दिया गया है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र जिले में उमरी गांव है। उस गांव के लोग पिछले तीन साल से रेजोल्यु इन भेज रहे हैं कि लेकिन फिर भी कोई गौर नहीं किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाराब बंदी कर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार ठेके नीलाम कर रही है। इसलिये मैं आपको ध्यान सरकार की भाराबबन्दी की नीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से उस पर अमल कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आप लिखित रूप से भेज दीजिए। हम उसको फारवर्ड कर देंगे।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):
स्पीकर साहब, स्वामी जी इस पर काल अटैन् इन मो इन भेज चुके
हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अगर आपकी काल अटैन् इन मो इन आई
हुई है तो वह एग्जामिन हो रही है। (विघ्न)

स्वामी आदित्यवे I: काल अटैन् इन मो इन तो मैंने
भेजी है।

श्री अध्यक्ष: फिर स्वामी जी आप भान्तिपूर्वक इन्तजार
कीजिए। आपकी काल अटैन् इन मो इन पर अब य कार्यवाही
होगी। (विघ्न)

स्वामी आदित्यवे I: भान्तिपूर्वक तो इन्तजार करूंगा।
(विघ्न)

ध्यानाकर्षण सूचना

राष्ट्रीय राजमाग्न नं० 1 तथा 10 पर यातायात बढ़ जाने के कारण

गम्भीर दुर्घटनायें बढ़ने के संबंध में

श्री अध्यक्ष: मुझे श्री कंवल सिंह एम०एल०ए० की तरफ
से ने इनल हाई वे नम्बर एक और नम्बर दस के ऊपर होने वाले
सीरियस एक्सीडेंटस के बारे में एक ध्यान दिलाऊ प्रस्ताव का

नोटिस मिला है। प्रस्ताव मंजूर किया जाता है अब आनरेबल मैम्बर अपने प्रस्ताव को पढ़ दें और मंत्री महोदय ध्यान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं या टाईम मांग सकते हैं।

श्री कंवल सिंह(धिराय): अत्यावश्यक लोक महत्त्व के इस विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अर्थात् नं01 तथा नं0 10 जो दिल्ली से पंजाब के लिये पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक जाते हैं, हरियाणा के बीच में से गुजरते हैं इन क्षेत्रों के समूचे विकास तथा इन सड़कों की सबसे अधिक आवश्यकता के कारण पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों राजमार्गों पर यातायात इतना अधिक आवश्यकता के कारण पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों राजमार्गों पर यातायात इतना अधिक बढ़ गया है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है कि जब इन मार्गों पर गम्भीर दुर्घटनाएं न होती हों। निःसंदेह इन राजमार्गों को चार सड़कों वाला दुहरा वाहन मार्ग बनाने के लिए योजनाएं सक्रिय हैं। परन्तु इनके कार्यान्वयन में समय लेगगा, जबकि इस समय वर्तमान परिस्थितियां इस बात की मांग करती हैं कि राज्य सरकार इस गम्भीर अवस्था का समाधान करने के लिये तुरंत आवश्यक पग उठाये। यद्यपि इन सड़कों पर नगरों और कस्बों में से गुजरते समय वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित हैं, परन्तु फिर भी खुले क्षेत्रों में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है इसके साथ साथ यातायात सम्बंधी विद्यमान नियमों तथा विनियमों को भी लागू करने के लिये प्रयत्न किये गये दिखाई नहीं देते हैं जिसके

परिणामस्वरूप ड्राइवर सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिये पुलिस की गति को बढ़ाने और विशेषतया इन राजमार्गों पर अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने के लिये सरकार को पग उठाने चाहिए। इन राजमार्गों पर स्थायी तथा अस्थायी ढांचों के अतिक्रमण को खाली कराने के लिये तथा मन्द गति से चलने वाले वाहनों अर्थात् बाईसिक्लों, रिक्शा, पेट्रोलियों द्वारा खींचे जाने वाले रहेड़ों, ट्रैक्टरों आदि का प्रयोग करने वाले लोगों को रात के समय रोशनी तथा रिफ्लैक्टर आदि का प्रयोग करने के लिये शिक्षा देने के लिये भी पग उठाये जाने चाहिए ताकि वह दुर्घटनाएं जो हाल ही में बड़े पैमाने पर हुई हैं, कम हो जायें क्योंकि यह एक अत्यावश्यक और गम्भीर समस्या बन गई है। इसलिए मैं सरकार और सदन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस काल अटैन्शन मोड में ट्रान्सलेटन में एक अतिवृद्धि मालूम होती है। इसमें नेशनल हाईवे की ट्रान्सलेटन राष्ट्रीय राजमार्ग की गई है जबकि राष्ट्रीय मार्ग होनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: यह कलैरिकल मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर दिया जायेगा।

स्वामी अग्निवेश: यह कोई अतिवृद्धि नहीं है। नेशनल हाईवे का अर्थ राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नै इनल हाई वे का सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जरूर ट्रांसले इन किया हुआ होगा। जो भी सही ट्रांसले इन हैं वह इसके अंदर लिखा जायेगा। अगर कोई गलती होगी तो इसको ठीक कर दिया जायेगा। आप टाईम ठीक इस्तेमाल करें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): इस काल अटैन् इन मो इन का 23 तारीख को जवाब दूंगा।

प्रिविलेजिज कमेटी की दूसरी प्रारम्भिक रिपोर्ट (चौधरी सुरेन्द्र सिंह एम0एल0ए0 के सम्बंध में) पे ा करना तथा मामले का झौप होना

Mr. Speaker: Now the Chairman of the Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges and also move his motion.

Ch. Partap Singh Thakran (Chairman Committee of Privileges): Sir, I beg tot present the Second Prliminary Report of the committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to t6he quuestion of alleged contempt of the House against Ch. Surinder Singh, M.L.A. for making a misleading statement in the House.

Sir, I also move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th September 1979.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, before I move this motion before the House, I would like to make an observation.

It is an established principle and convention that the Speaker of the House maintains absolute impartiality in the performance of his duties. This practice and convention I have endeavoured to follow in the strictest sense of the word and to the best of my ability. How far I have succeeded in this objective is not for me to say but for the Hon'ble Members, of the House to Judge.

This particular privilege motion was referred to the Privileges Committee when I was holding the portfolio of Education. Since now I am occupying the Chair of Speaker, it is my considered opinion that whilst occupying this Chair I should not be associated or be a party to any privilege motion. In the consideration of this question the House, of course, is the final authority.

I have also received an amendment to this motion from Shri Shamsheer Singh Surjewala, M.L.A. However, before I put this matter before the House I would request the Hon'ble leader of the House to express his opinion on the subject.

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि आप जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब यह मामला रैफर हुआ था अब चूँकि आप कुर्सी संभाले हुए हैं इसलिये यह मुनासिब नहीं होगा कि आप इस मामले में इन्वाल्वड हों। इसलिये

में यह समझता हूँ कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति हाउस को प्रिजाईड करे और इस बारे में हाउस का फैसला ले ले।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासनी हुए।)

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th September 1979.

The amendment received from Shri Shamsheer Singh Surjewala, M.L.A. will be deemed to have been read and moved.

That this House recommends that the question of alleged breach of privilege against Ch. Surrinder Singh M.L.A. may be dropped in view of the fact that one of the persons concerned in the controversy is now occupying the August office of the Speaker of this House. In view of this, no extension of time is granted and the matter is deemed as closed.

श्री कन्हैया लाल पोसवाल (छछरौली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने आपसे यह अर्ज करना है कि स्पीकर साहब, ने जो आब्जर्वेसन की हैं, मैं समझता हूँ कि वह उचित है। तो मैं लीडर आफ दि हाउस से और सारे मैम्बर्स से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अब इसमें स्पीकर साहब, इन्वाल्व्ड हैं इसलिये उनकी कमेटी में बडी इम्पैरेसिंग पोजीशन होगी यदि वह उसी कमेटी में तारीफ लायेंगे जिसको वे नौमिनेट करते हैं और वहां पर आक

एवीडैंन्स दें तो ठीक नहीं होगा। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि लीडर आफ दि हाउस और सारे मैम्बर साहेबान इस बात को कंसीडर कर लें। स्पीकर साहब, ने चूंकि यह आबजरर्वे इन की है। इसलिये इसको विदद्दा करना ही मुनासिब होगा।

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमि इन यह है कि यह बात तो वाजिब है कि आज सिचुए इन बदल गयी है। पहले एजुके इन मिनिस्टर अब स्पीकर बन गये हैं लेकिन जिस आनरेबल मैम्बर ने प्रिविलिज को ब्रीच किया था, मैं समझता हूं कि उसके बारे में जरूर विचार होना चाहिए क्योंकि अन्यथा यह गलत रिवायत डल जायेगबी, यही मेरी राय है।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है। इसमें स्पीकर साहब, का नाम भी जुडा हुआ है। आपको पता ही है कि स्पीकर साहब, हाउस में सबसे बडी हस्ती होते हैं जितना चौधरी बंसी लाल के और चौधरी सुरेन्द्र सिंह के, मैं और चौधरी देवी लाल जी खिलाफ हैं।, मेरे ख्याल में और भायद ही कोई मैम्बर होगा। इसलिए मैं हाउस से और लीडर आफ दि हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि इस मामले को ड्रौप कर दिया जाये। अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हाउस इस मामले की भावना या डिटेल्ज में न जाकर इसको खत्म कर दें, यही मेरी प्रार्थना है।

चौधरी खुर गद अहमद (ताउडू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत हाउस के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि प्रिविलेज कमेटी में कोई भी इ गू हो, उसके लिये जब तक कोजैन्ट और कन्विसिंग एबीडैंस कमेटी के सामने न आये और मैम्बर्ज के सामने काफी मैटीरियल न हो, तब तक कोई भी इ गू कामयाब नहीं हो सकता। यहां पर ऐसी सिचुए ान आ गयी है कि जब प्रिविलिज उठाया गया, उस समय हमारे आनरेबल स्पीकर साहब, एजुके ान मिनिस्टर साहब की हैसियत में थे। आज प्रिविलिज कमेटी को वही नौमीनेट करते हैं क्या ऐसा उचित होगा कि जिस कमेटी को वे खुछ नौमीनेट करते हैं, उस कमेटी के सामने स्पीकर साहब, पे ा हो ? यह ठीक नहीं होगा और इससे एक एनोमलस सी सिचुए ान आ गयी है। पहले और हालात थे, अब हालात दूसरे हैं। इसीलिये हालात के मुताबिक इसको ड्राप किया जा सकता है। क्या ऐसा उचित होगा कि स्पीकर साहब, कमेटी के सामने पे ा हों कमेटी उनसे सबूत मांगे और कानूनी तौर पर एग्जामिने ान और क्रास एग्जामिने ान हो। जेसा कि स्पीकर साहब, यह मो ान लाये हैं और लीडर आफ दि हाउस ने जैसे कहा भी है, इस मो ान को अगर ड्राप कर दिया जाये तो कमेटी के लिये भी कन्वीनिएं्ट होगा और यह प्रैक्टिकली भी अमल में लाया जा सकता है क्योंकि कमेटी कोई फाईडिंग अदरवाईज दे नहीं सकतीं इसलिये मैं हाउस में यह दरखास्त करूंगा कि इस मामले को ड्राप कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

राम किान (सफीदों): उपाध्यक्ष महोदय, मसला बडा अहम है। लेकिन माननीय मंत्री चौधरी भजन लाल और माननीय सदस्य चौधरी खुर गीद सुझाव हाउस के सामने रखा है, मैं भी उसी सुझाव का समर्थन करता मामले को ड्राप कर दिया जाये।

स्वामी अग्निवे 1: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपने इस सुझाव करना चाहता हूँ कि जब परिस्थितियां इत्यादि बदल गयी हैं तो इसके लिये कोई हल निकालना चाहिए और सच्चाई का पता लगना चाहिए कि जो माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया गया था, वह सही थी या इस मामले को वापिस कर लेते हैं तो एक साल भर जो इस कमेटी रही इतना पैसा खर्च किया गया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस को ड्राप नहीं करना चाहिए कोई न कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए।

भजन लाल: जो थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो गयी है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ चौधरी खुर गीद अहमद ने गलत समझ कर यह कहा कि जैसे लीडर आफ दि हाउस ने यह कहा कि इसे ड्राप कर दिया जाये। मुझे इस बारे में इतना ही कहना है कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि स्पीकर साहब, चूंकि आप इस कुर्सी पर हैं और आप इस मामले में इन्वालड हैं, इसलिये कोई दूसरे साहक चेयर को संभले और जैसे हालात हैं हाउस उसके मुताबिक फैसला ले लें।

स्वामी अग्निवे 1: जैसे अभी सदन के नेता ने एक बात कही कि आप स्पीकर साहब, इस कुर्सी पर न बैठें, किस अन्य सदस्य को इस चेयर पर बैठने दें तभी इस बात का फैसला हो। मेरे विचार में उन्होंने संवैधानिक कठिनाई को सुलझाने के लिये यह सुझाव दिया था। स्पीकर साहब, ने बड़ी उदारता का परिचय देते हुए कुर्सी को छोड़ने की एक स्वस्थ परम्परा कायम की है। मैं यह समझता हूँ कि कुर्सी छोड़ना और मामले को ड्राप करना दो अलग अलग मसले हैं। अध्यक्ष की हैसियत से कोई भी मामला उनके बारे में कमेटी में न आये, यह एक स्वस्थ परम्परा है और बड़ी अच्छी बात है लेकिन यदि कोई विशेषाधिकार का प्रस्ताव इस सदन में सामने आया है उसको तथा कथित उदारता का परिचय देते हुए वापिस लेना हमारी समझ में नहीं आता। या तो यह साबित हो जाये कि जो आरोप लगाया गया है वह गलत है या फिर जो सम्बन्धित सदस्य है, वे सदन में खड़े होकर माफी मांग लें तो हम समझते हैं कि इसको वापिस ले लेने का कोई औचित्य है लेकिन जिस सदस्य के विरुद्ध आरोप हैं वह माफी नहीं मांग रहा है। इस प्रस्ताव में जो आरोप लगाये गये हैं, वे बड़े गम्भीर हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि आपकी अध्यक्षता में जो भी अनुकूल या प्रतिकूल फैसला हो, उस पर अमल करना चाहिए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है वह ठीक है। स्वामी अग्निवे 1 ने कहा कि इसका निर्णय करना चाहिये। इस मामले में

आनरेबल स्पीकर इंवाल्वड हैं और छोटी मोटी बातें तो घर में भी होती रहती हैं। इसलिये हालात को देखते हुए इस मामले को खत्म करना बहुत जरूरी है। इस मामले को ज्यादा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है और न ही ऐसे मामले बढ़ाना अच्छा होता है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इत्तफाक राय से इस मामले को ड्रौप किया जाये ओर ऐसा करके हाउस में एक अच्छी परम्परा कायम की जाए। अन्त में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस मामले को ड्रौप किया जाए।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे काफी साथियों ने इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा है। स्पीकर साहब, का ओहदा बहुत बडा होता है और इसका सब को अहतराम करना चाहिए। मेरी तजवीज है कि इस मामले में बदले की भावना न रखी जाए और प्रत्येक मैम्बर को इत्तफाक राय से इस प्रस्ताव को ऐक्सेप्ट करना चाहिए और इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। यह बडी अच्छी बात हे।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह महसूस करता हूं कि चौधरी सुरेन्द्र सिंह को हाउस के अंदर खडे होकर जरूर रिग्रेट करना चाहिए और लीडर आफ दि हाउस से अपील करें कि किन्हीं गलतफहमियों या कुछ और ऐसी बातों के कारण उनसे ऐसे लफज निकल गए थे, ऐसा करने के बाद हम अपने लीडर से अपील कर सकते हैं कि वे इसको ड्रौप कर दें।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कई तरह की भावनाओं का इजहार किया जा रहा है। वास्तव में मामला इतना संगीन नहीं है कि इम सैंटीमेंटस में आ जाये। मामला बडा लीगल है। लीगल आसपैकटस से उसको देखना चाहिए। सरदार लछमन सिंह ने कहा कि चौधरी सुरेन्द्र सिंह खडे होकर माफी मांग ले और स्वामी अग्निवे 1 ने भी कहा कि खडे होकर माफी मांग लें और इस मामले को ड्रॉप कर दिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, सवाल यह है कि क्या विधान सभा ने जो प्रिविलेजिज कमेटी बनाई थी उसकी कोई रिपोर्ट आ गई है और क्या कमेटी ने चौधरी सुरेन्द्र सिंह को दोशी करार दिया हे ? ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई हैं इसलिये मसला सिर्फ यह हुआ कि अध्यक्ष महोदय ने यह अनुकूल समझा कि "चूंकि वि शेषाधिकार समिति में मुझे ऐवीडेंस के लिये जाना पडेगा तो मेरी अपनी पोजी 1न ऐम्बेरेसिंग हो जाएगी।" उन्होंने एक स्वसी परम्परा डाली है और यह परम्परा इस लिए डाली है कि वि शेषाधिकार समिति को जब मामला जाता है तो अकेले अध्यक्ष महोदय, नहीं भेजता सदन भेजता हैं इसलिये उस मामले को चलाने का अधिकार केवल सदन के पास है, किसी और के पास नहीं हैं इसमें टैक्नीकल मामला इतना ज्यादा है कि स्पीकर अपनी बनाई हुई कमेटी के सामने ऐवीडेंस देने जाए तो कमेटी और स्पीकर दोनों की पोजी 1न ऐम्बेरेसिंग हो जाएगी। इसलिए मैं लीडर आफ दि हाउस से गुजारि 1 और प्रार्थना करती हँ कि इस मामले को ड्रॉप कर दिया जाये।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, इस विषय में चौधरी उदय सिंह दलाल और दूसरे साथियों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन विचारों का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूँ। हाउस को इस मामले को लम्बा नहीं करना चाहिए और जैसा कि स्पीकर साहब, ने खुद फरमाया कि प्रिविलेज कमेटी के सामने जिसको उन्होंने खुदे बनाया है, अगर वह ऐविडेंस देने के लिये जाते हैं तो बडी ऐम्बेरेसिंग सिचुए ान हो जाएगी। चौधरी सुरेन्द्र सिंह तब तक क्षमा नहीं मांग सकते जब तक कि प्रिविलेज कमेटी उनको दोशी न ठहरायें इन हालात को देखतु हुए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले को अपनी फराखदिली से ड्राप कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह(तो ाम): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वि ोशाधिकार के उल्लंघन का सम्बंध है, मैं सदन को वि वास दिलाता हूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि सदन के सम्मानित सदस्यों को अपमान किया जाए या सदन को गुमराह किया जाये। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं हाउस की इज्जत करता और करता रहूंगा लेकिन हो सकता है कि किसी भाई को कोई बात महसूस हुई हो लेकिन मैं फिर वि वास दिलाता हूँ कि मेरे दिल में हाउस की मानहानि या किसी सदस्य की मानहानि करने की कोई बात नहीं है (ाोर)

डा० मंगल सैन: अभी भी माफी नहीं मांगी है। (ाोर)

चौधरी देवी लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर सवाल दोशी या निर्दोशी का नहीं है सवाल टैक्नीकल है और इस लिहाज से है कि हमारे स्पीकर साहब, इसमें इन्वाल्व हैं जो उनकी बनाई हुई कमेटी है अगर स्पीकर उसी कमेटी के सामने जाएं तो वहां उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनको कमेटी के सामने पेना होना पड़ेगा जो स्वस्थ परम्परा नहीं है। जैसा कि बहन सुशमा और बाबू मूल चन्द जैन ने कहा है, मैं समझता हूँ कि हाउस को उसके मुताबिक अपना मन बना लेना चाहिए और इस मामले को ज्यादा लम्बा न खींच कर ड्रौप कर देना चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: Now, I will first put the amendment by the Shri Shamsheer Singh Surjewala to the vote of the House.

Question is-

That this House recommends that the question of alleged breach of privilege against Ch. Surrinder Singh, M.L.A. may be dropped in view of the fact that one of the persons concerned in the controversy is now occupying the August office of the Speaker of this House. In view of this no extension of time is granted and the matter is deemed as closed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Since the amendment has been carried and the matter closed, there is no need to put the main motion to the vote of the House.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: जो लीडर आफ दि हाउस की रय के खिलाफ वोट दें, उसको मन्त्री नहीं रहना चाहिए। (गोर) अस्तीफा दे देना चाहिए। (विघ्न)

Dr. Mangal Sain: You are no body to say like this. I have every right to vote and express my view. (Interruptions). You are no body to interfere.

चौधरी देवी लाल: श्री पोहलू को यह बात कहना मुनासिब नहीं थी। इस किस्म के रिमाक्स नहीं कसने चाहिए। (व्यवधान)

Mr. Mangal Sein: I have voted as a member of the House. I have every right to vote मैंने इनकी (श्री भाम गोर सिंह) मो इन के खिलाफ वोट दिया है न कि मुख्य मंत्री की। (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister(s) to introduce the Bill.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड

पैन् इन आफ मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल, 1979

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैन् इन) सं गोधान विधेयक, 1979 प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assmbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1979.

Mr. Deputy Speaker: Question if -

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assmbly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1979.

The motion was carried.

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 1979 प्रस्तुत करता हूँ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) बिल, 1979

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) विधेयक 1979 प्रस्तुत करने के लिये अनुमति चाहता हूँ।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assmbly (Facilities to Members) Amendment Bill, 1979.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: पहले स्वामी जी बोलेंगे (तोर)

स्वामी अग्निवे I (पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बडा आभारी हूं कि आपने नियमानुसार मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं अपने सदन के माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं, उनको देख रहा हूं और वे सभी चाहते हैं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिये क्योंकि इस बिल के द्वारा कुछ और सुख सुविधा सदस्यों को देने की बात कही गई है। (तोर)

Mr. Deputy Speaker: Order Please.

स्वामी अग्निवे I: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है इसके माध्यम से सदस्यों को और सुविधायें दी जा रही हैं। उसमें पहले जो हमारे विधायकों को सुख सुविधाएं दी जात रही है उनके इलावा उन में और वृद्धि करने की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारा दे I कितना गरीब है और यहां हरियाणा प्रान्त के अन्दर पिछली 26 जनवरी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा था कि हमारे हरियाण प्रदे I के अंदर 48 प्रति Iत किसान, मजदूर, गांवों के रहने वाले लोग, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिये मंजबूर हैं। (तोर)

डा0 बृज मोहन गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है। स्वामी जी को भायद मिस अन्डरस्टैंडिंग हो गई

है। यह ग्रांट नहीं है यह तो एक प्रकार का लोन है जिसको कि ब्याज समेत वापिस किया जाना है और एल0आई0जी0, एम0आई0जी0 और एच0आई0जी0 के तहत जितनी भी मकान बनाने की स्कीमज हैं ये तो पहले से ही चल रही हैं।

स्वामी अग्निवे : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया जो कि यह माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैंने तो केवल यही निवेदन किया है कि हरियाणा प्रांत में डिवैल्पमेंट होने के बावजूद इसके आधे से ज्यादा लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं (गोर) उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रांत में बाढ़ का बड़ा भारी प्रकोप है, लाखों लोग बाढ़ की लपेट में आकर बेघर हो गये हैं। (गोर एवं विघ्न)

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वामी जी अपनी लम्बी लम्बी बातें बजट पर बोल लें तो अच्छा रहेगा।

स्वामी अग्निवे : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम बाढ़ से पीडित लोगों के लिये केवल 300-300 रुपये देने का प्रावधान कर रहे हैं और दूसरी तरफ विधायकों के लिये 45000 रुपये देने का प्रावधान कर रहे हैं जो कि उचित प्रतीत नहीं होता (गोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है एक तरफ तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गरीबों से पैसा न लिया जाये हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कई जगहों पर लोगों द्वारा दी गई मालाओं को जो कि गले में डाली गई, उन्हीं लोगों की डिवैल्पमेंट के कामों के लिये दे दिया और इसके साथ साथ उतने ही पैसे और भी सहायता के लिये दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिये।

स्वामी अग्निवे I: उपाध्यक्ष महोदय, भाई पोहलू जी ने मेरे ऊपर जो यह आरोप लगाया है, इसका वे यहां पर प्रमाण दें या फिर इन भाब्डों को वापिस लें (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है जैसा कि मेरे भाई गुप्ता जी ने अभी कहा कि यह ग्रांट नहीं, यह तो लोन है और उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। इस तरह अगर कोई भाई कर्जा लेकर अपना मकान बना लेता है तो इसमें क्या बुराई है ? स्वामी जी को तो न कोई घर है न बाहर, न बच्चे।वे फिर हमें क्यों मारें। (गोर—हंसी)

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहब आप बैठिये।

श्री देवेन्द्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप अभी बैठिये, जरा पहले स्वामी जी के विचार सुन लीजिये।

श्री देवेन्द्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तीन बार टाईम लेने के लिये खडा हुआ हूँ और मुझे टाईम नहीं दिया जा रहा है (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये पहले स्वामी जी बोलेंगे
(गोर)

स्वामी आदित्यवे तः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न हैं यहां पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और बहुत सारे सदस्य ये बाबा जी कह रहे हैं जो कि उनके लिये भाभा नहीं देता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम बोलने वाले माननीय सदस्य को भान्ति से सब को सुनना चाहिये। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, सब के अपने अपने मकान और बडी बडी कोठियां हैं। (गोर) वे दोबारा लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा० बृज मोहन गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी को यह गलतफहमी है कि जिन के पास पहले मकान हैं, वे दोबारा लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिनके पास मकान हैं उनको दोबारा लोन नहीं मिलेगां

श्री देवेन्द्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है अभी स्वामी जी बोल रहे थे तो भाई पोहलू जी ने उठकर मेरी आपके द्वारा उनसे रिक्वसैट है कि वे अपने इन लफजों को वापिस लें, कहीं आगे के लिये ऐसी रिवायात न कायम हो जाएं जिससे एक दूसरे के प्रति ऐसे आरोप लगाते चले जाएं।

श्री जगन नाथ: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस बिल के पास होने के बाद, दोनों स्वामियों, डाक्टर मंगल सैन और श्री गंगा राम जी को ये फेसिलिटीज न दी जाएं। (हंसी)

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। मैं उन मित्रों की बात नहीं करता जिनका नाम अभी मेरे नाम के साथ भाई जगन नाथ जी ने लिया है अगर इस बिल में किसी प्रकार का कोई संशोधन करके सरकार कोई कानून बना देती है जिसके तहत मेरे हिस्से को सारा पैसा भाई जगन नाथ जी को मिल सके तो वह उनको दे दिया जाए।

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मुझे इनके साथ मिला कर आगे के लिये मेरा रास्ता बन्द क्यों किया जा रहा है ?

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कहने से पहले भाई पोहलू जी से प्रार्थना करूंगा कि

अगर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हों तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न मान कर विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय स्वामी जी ने जो बात फरमाई है कि भारत में और हरियाणा में लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के बाढ़ में मकान टूटू, उनको हम केवल तीन सौ रुपये दे रहे हैं मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूँ कि यह बिल इस बात से संबंधित नहीं है। इस वक्त तो मैं केवल इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने के लिये सदन की अनुमति मांग रहा हूँ। स्वामी जी को अपनी बात कहने का आगे जाकर पूरा मौका मिलेगा उस वक्त ये अपना मत व्यक्त कर दें और चाहें तो मत भी खिलाफ दे दें यह इनकी अपनी इच्छा है यह तो इन्ट्रोडक्शन की स्टेज है। इसके अलावा मकानों के बारे में मैं एक बात और बता दें कि तीन सौ रुपया ही नहीं दिया गया बल्कि बैंकों से 1200 रु० लोन लेकर देने का भी प्रबंध किया गया है। इस बिल में जो बात है वह तो सिर्फ कर्जा देने की है और वह वापिस देना होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये अनुमति प्रदान की जाए।

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, पोहलू साहब ने मेरे बारे में जो भाव्य कहे, उनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री उपाध्यक्ष: वह मैंने डिसअलाउ कर दिया था।

स्वामी अग्निवे 1: क्या वे भाबद एकसपंज हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष: हाँ

Now I will put the motion to the vote of the House.

Question is -

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Bill 1979.

The motion was carried

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) विधेयक 1979 प्रस्तुत करता हूँ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी
स्पीकर्जसैलरीज

एंड अलाउंसिज (अमैडमेंट) बिल, 1979

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1979 प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved -

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1979

स्वामी आदित्यवे 1 (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये राज्य सरकार की आरे से कार खरीदने के लिये सुविधा दी जा रही है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पहले ही सरकार की ओर से कार की सुविधा प्रदान की जाती है तो अब इसके लिये अतिरिक्त कर्जा देने की में आव यकता महसूस नहीं करता। इससे राज्य पर और अधिक बोझा पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक न रखा जाएं

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वामी जी की जानकारी के लिये बता दूं कि कार खरीदने के लिये 26 हजार रुपये का प्रावधान, यह जो थोड़ी सी गिनती में महानुभाव बैठे हैं, इनकी सरकार ने किया हुआ था। हम तो कीमतों में बढ़ौतरी हो जाने की वजह से उसमें सिर्फ चार हजार रुपये की बढ़ौतरी कर रहे हैं। यह पैसा भी लोन है और यह वापिस लिया जाएगा।

स्वामी आदित्यवे 1: इसका मतलब यह है कि जो कुछ पिछली सरकार कर गई, वही आप करने जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को वापिस लिया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब, का मामला डिस्कस नहीं होना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1979

The motion was carried.

डा० मंगल सैन: मैं हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1979 प्रस्तुत करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker: Now, there will be general discussion on the Budget for the year 1979-80.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार किसान और गरीब की वोटों से बनी हुई है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी किसान के बेटे हैं। हमें अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन वे पूरी नहीं हो पाई। इस सरकार का हलधर निदान भी बहुत सुथरा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यह निदान किसी और आदमी का था लेकिन यह गलत आदमी के हाथ में चला गया। डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर साहब आम जनता का भला करेंगे लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यह जो बजट पेश किया गया है, यह किसान दुःखी जनता के खिलाफ है जो गरीब जनता के खिलाफ हैं इस बजट की सोच सरमाएदारों से जुड़ी हुई है। जब यह बजट बनाया गया तो उस वक्त इसे सरमाएदारों का ध्यान रख कर बनाया गया और गरीबों को भुला दिया गया इसलिये मैं इस बजट को मुखालफत करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा में 85 प्रतिशत लोग रात दिन

मजदूर बन कर या हल चला कर खेतों में काम करते हैं और बाकी जो 15 प्रतिशत लोग हैं वे या तो कारखानेदार हैं या व्यापारी हैं या मुलाजिम हैं वे भी खेती की पैदावार पर ही निर्भर करते हैं डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई भाव नहीं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये बजट में पैसा रखा गया है लेकिन किसान को खाद और डीजल ब्लैक में लेना पड़ता है। आज अगर किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन देखी जाए तो गेहूं पर उसका तकरीबन 150/-रु० प्रति क्विंटल खर्च आता है। बजट में इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि किसान को अपनी पैदावार का पूरा भाव मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी बहू बेटियों, बच्चे और बूढ़े रात दिन कड़कती सर्दी और धूप में खेतों में काम करते हैं और जो हमारी कर्मवती बहू बेटियां होती हैं उनको भी खेतों में काम करने के लिये जाना पड़ता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है। इतना कष्ट सहने के बाद किसान जब अपनी पैदावार मंडियों में लेकर आता है तो वहां उसको लूट लिया जाता है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने किसान को बचाना है तो सारी मंडियों को तोड़ दो और जितना किसान का अनाज है वह सारे का सारा सरकार गांवों में जाकर खुद खरीदे। जिस तरह अमेरिका में किसान की सारी पैदावार को वहां की सरकार खरीदती है चाहे वह इस्तेमाल हो या न हो, उसी तरह से हरियाणा में भी किसान की सारी पैदावार यहां की सरकार खरीदे। किसान को किसी तरह भी नुकसान नहीं होना चाहिये। आज किसान की हालत बहुत

खराब है। दो साल हो गये कभी फलड आ जाता है तो कभी तूफान आ जाता है। इस साल भी ओलों से 25 करोड रुपये का नुकसान हुआ है। में चाहूंगा कि जिस तरह से किसी कारखानेदार का नुकसान होने पर उसे पूरा मुआवजा सरकार देती है उसी तरह से किसान को भी उसके नुकसान का पूरा मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए यह जो 25 करोड रुपये का नुकसान इस साल किसान का हुआ है यह भी पूरे का पूरा सरकार को देना चाहिये और आगे के लिये सरकार किसानों की हर फसल का बीमा करे ताकि आयांदा अगर किसान का कोई नुकसान होता है उसे वह बच सके। इससे आगे जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि किसान को जो चीजें खरीदनी पडती हैं उनमें से सिवाये गुड और चीनी के बाकी सब चीजों के भाव बढ गये हैं जो ट्रैक्टर पिछले साल 57 जार रुपये का था वह आज 67 हजार रुपये का आता है। इसलिये किसानों को लूट से बचाने के लिये हर चीज की कीमत सरकार खुद मुकरर करे। जब कोई चीज किसी कारखाने में बनती है तो उससे सरकार अपना टैक्स वगैरह लगा कर उसकी प्राइस फिक्स करवाये। इसके साथ साथ दुकानों पर भी रेट लिस्ट लगवाई जानी चाहिये। हम देखते हैं कि रेट लिस्ट लगवाने के बावजूद भी दुकानदार कई बार चीजों के ज्यादा भाव लगाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए ज्यादा पुलिस मुकरर की जाए ताकि दुकानदार किसानों को लूट न सके।

16.00 बजे।

आप में भी किसान भाई बैठे हैं, आपको मालूम है कि किसान को दो चीजों की जरूरत है। एक तो फ्लड पर कंट्रोल किया जाये और दूसरे सरकार सूखी धरती को पानी दे। जहां नहरों का पानी मिल सकता है वहां नहरी पानी दे। डिप्टी स्पीकर साहब, अब भी हरियाणा में जमीन का 4/5 हिस्सा बिना पानी के है, केवल 1/5 हिस्से में पानी लगता है काफी जमीन अब भी बारानी पडी है। हमारी फसलें सूखी पडी हैं रावी ब्यास के पानी का अभी तक सरकार फैसला नहीं करवा सकी है। दूसरी तरफ हमारे हरियाणा का पानी रोपड जिले में लग रहा है। वहां पानी न भी लगे तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा परन्तु हमारे हरियाणा में बिना पानी के बहुत नुकसान हो रहा है। इस साल हरियाणा में तो कुछ फसलें अच्छी हो गई हैं। परन्तु अभी भी बहुत सी जमीन ऐसी पडी है जो सूखी है। अगर सरकार चाहे तो एक साल के अंदर जमीन को नहरी पानी लग सकता है। ज्यादा ट्यूबवैल लगाए जाये ताकि एक फुट जमीन भी सूखी न रहे, कहीं भी जमीन बारानी नहीं होनी चाहिए। पिछली साल फ्लड आने पर लोगों को कर्जे दिये गये थे। अब कहा जा रहा है कि छोटे किसान कर्जा देने में हेराफेरी कर रहे हैं। यहां जो आपके अफसर महलों में बैठे हुए हैं उनसे फील्ड में काम लें। आपका ड्रेनेज महकमा गांवों में जाकर देखे और जहां ड्रेनेज के मामले को लेकर झगडा हुआ है उसको निपटाने के किसानों का साथ दें। झगडा दूर हो सकता है अगर ड्रेनेज के मामले को हल करें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले साल हरियाणा

में फलड के नाम की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस आने वाली बरसात में कोइ बीमारी देखने में आनी चाहिए। अब मैं इंडस्ट्री के महकमे के बारे में बताना चाहता हूं जिसे डा0 मंगल सैन पूरी कोर्ि । । से चला रहे हैं। जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि बडी इंडस्ट्रीज कम लगानी चाहिये। इसके बदले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिएं ताकि छोटी इंडस्ट्री से माल पैदा हो सके और छोटे लोगों को फायदा हो। बडी इंडस्ट्रीज पर बैन लगाया जायें जो बडे बडे कारखानेदार हैं जिनकी काफी बडी बडी फ़ैक्टरियां हैं उन पर सीलिंग होनी चाहिएं पांच हजार फी एकड के हिसाब से 18 एकड जमीन की कीमत 90 हजार रुपये बैठती हैं इसलिए फ़ैक्टरी वालों पर 90 हजार रुपये की सीलिंग होनी चाहिएं 90 हजार से ज्यादा की प्रोपर्टी छीन ली जानी चाहिये इसके लिए कोई कानून होना चाहिए। आप कानून बना सकते हैं और ऐसा कानून बनायें जिससे जनता का भला हो। अपने गरीब किसान की जमीन पर 18 एकड की सीलिंग लगा दी है परन्तु इन कारखानेदारों पर इस सीलिंग का कोई असर नहीं पडतां कारखानेदारों पर जिनकी भाहरी प्रापर्टी हैं उन पर भी सिलिंग होनी चाहिए। जिस तरह गरीब किसान की जमीन छीनी गई है उसी तरह इन की प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगा कर फालतू प्रोपर्टी छीन ली जाये। यह इस बजट में कमी है, अमीर गरीब का फर्क दूर किया जाना चाहिये। किसान की खून पसीने की जमीन है, वह तो आपने छीन ली है, लेकिन इन सरमायेदारों की अर्बन प्रापटी

की तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखा जाता। आप उन पर भी सीलिंग लगाये सब सदस्य आपका पूरा समर्थन करेंगे।

अब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सडकों के बारे में बताता हूँ। पुरानी सडकों की आज हालत खराब हैं। नई सडके तो बनना दूर रहा, जो पुरानी सडके पिछले साल फलड से टूट गई थीं उनकी दोबारा मुरम्मत नहीं हो सकी है। इस महकमे का काम इतना स्लो है कि पाई से अरसोला, राजौंद से खेडो सरफअली, खेडी सरफअली से राहडा सडकों की आज तक मुरम्मत नहीं हुई।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): अभी मैं और सडकाउं को भी नाम बताऊंगा। सडकों की रिपेयर का काम स्लो है मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सरकार अगली बरसात आने से पहले इनकी मुरम्मत का इंतजाम करेगी। चीफ मिनिस्टर साहब भी जाकर सडकों की हालत देख सकते हैं। यह काम बरसात से पहले होना चाहिए वरना जो थोड़ी बहुत बची हैं, वे भी बरबाद हो जायेंगी। पिछले सै 11 में भी मैंने सडकों के बारे में लिख कर दिया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि इनकी मुरम्मत करने के लिये अभी तक एक भी कस्सी नहीं चली। इन सडकों के नाम ये हैं –गुलियाना से खेडी संदल, नरड से सेगा, अरसोला से भी 11 तथा खेडी सरमअली से राहडा। जिन सडकों के बारे में पहले ही लिख कर दिया है कि उनका तो रिपेयर का काम होना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस महकमे पर खास नजर रखें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ट्रांसपोर्ट के महकमे के बारे में कहूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह अच्छा काम किया कि जनरल मैनेजर के स्थान पर डी0एस0पी0 को लगा दिया। मैं तो डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहूंगा कि सडकों और ट्रांसपोर्ट के महकमे को मिलिटरी के सुपुर्द कुछ समय के लिये कर देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट में सरकार को इस वर्ष 36 लाख रुपया का घाटा हुआ है, जिसमें से अकेले कैथल में 13.25 लाख का घाटा हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहब, बसों की हालत यह है कि अगर आम जनता, बच्चे, बूढ़ी और गर्भवती महिला उसमें चढ जाये तो उनकी बुरी हालत हो जाती है बसों का किया जाना चाहिये। रास्ते में बसों से कड कड की आवाज आती है। मैं एक मिसाल चाहता हूँ बस नं 1590 हिसार से चण्डीगढ आती है। यह बस क्योडक से होती कैथल सुबह 6 बजे पहुंचती है। 7 तारीख को यह बस सुबह 6 बजे कैथल पहुंची। यहां यह खराब हो गई क्योंकि डीजी में पानी और ग्रीस थी। इस मिलावट को दूर करना चाहिए इससे बसों की खराबी नहीं होगी तभी लोगों का भला होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, स्पोर्ट्स के बारे में जो कदम उठाये हैं, वे अच्छे हैं। हरियाणा का राजेन्द्र सिंह इस साल दो दो गोल्ड मैडल लेकर आया है, बडौदा में अच्छे कोचिंग खोले जाने चाहिए दूसरे प्राफैसर भीम सिंह हैं, वे योग के अच्छे जानकार हैं सार पहला नम्बर लेकर आये हैं, उनको योगा का डायरैक्टर

बनाया जाये। उन्होंने 14 जनवरी को कुरुक्षेत्र और 17 जनवरी को कैथल में अपना कार्यक्रम दिखाया जो लोगों ने बहुत किया। हर जिले में ऐसा सेंटर खोला जाना चाहिये। उनको डायरेक्टर बना कर यह महकमा बना दिया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, बेरोजगारी का मसला बड़ी गम्भीर है लेकिन सरकार इसको दूर नहीं कर सकती। इस वक्त तीन लाख बेरोजगार बेकार बैठे हैं इस साल जो परीक्षाओं में पास होंगे वे भी बेकार हो जायेंगे। इसलिये कोई नये कदम उठाये जाये यह मसला सुलझ सके। जो लोग सर्विस में 55 साल पूरे कर चुके हैं उनको रिटायर दिया जाये। मैं तो यह राय दूंगा कि दिल्ली के पैटर्न पर जिनकी 25 साल की नौकरी 50 साल की उम्र हो गई है, उनको रिटायर कर दिया जाये ताकि नये लोगों को रोजगार मिल सके, इस तरह बेरोजगारी का मसला हल हो सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुछ प्रोहीबिशन के बारे में भी कहना चाहता हूं सरकार असल नीति क्या है ? एक तरफ तो भाराब के बड़े बड़े ठेके दे दिए और दूसरी तरफ भाराब बंदी की बात करते हैं। कई भाई कहते हैं कि भाराब बंदी नहीं होनी चाहिये। मैं भाराब के बारे में बंदी चाहता हूं कि जितने भी एम0एल0एज0 और वजीर साहब हैं, वह एलान करें और मैं भी रामायण का भूलोक 'प्राण जाए पर वचन न जाए' पढ़ कर ऐलान करता हूं और कसम खाता हूं कि भाराब कभी भी नहीं पीऊंगा।

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन): यह एलान आपने भाम तक का किया है हमें आ के लिये किया है ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैंने यह एलान हमें आ के लिए किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इंटों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आज जनता कैसे अपने मकान बनाए ईंट बनाने के लिए कोयला नहीं मिलता। यह मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार को खुद चलाएँ यदि सरकार भट्ठों को खुद चलाएगी तो बेरोजगारों को काफी रोजगार मिलेगा। इस बजट में यह भी रखा जाए कि जितने सरपंच और पंच हैं उनके पास काफी जायदाद होती है उसमें बहुत हेराफेरी होती है। यदि हर महीने सरपंच और पंच को 200 और 100 रुपए दिए जाएं तो यह हेराफेरी दूर हो सकती है।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): जो कुछ आपने कहा है क्या इसके बारे में आपने अपनी पार्टी से पूछ लिया है ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: जिस पार्टी में मैं हूँ उसमें आप भी तो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आजकल हरियाणा में भादियों की बहुत बुरी परम्परा चली हुई है। लोग टीके बहुत ज्यादा लेते हैं। भादियों में नाजायज खर्चा करते हैं और दहेज भी बहुत ज्यादा लेते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक पब्लिसिटी सैल बनाया जाए जो हर गांव में इस बात की पब्लिसिटी करे कि भादी में नाजायज खर्च न हो और ज्यादा दहेज कोई न ले। वह सैल दहेज के विरुद्ध प्रचार करे

और इस प्रथा को खत्म करने के लिए लोगों का हौसला बढ़ाये। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सैल को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि गरीब आदमी की लडकी भी ठीक भाादी करवा सके। इस प्रथा के कारण लोग कहीं लडकियों को मार रहे हैं, कहीं छोड रहे हैं। यह बुरी परम्परा सैल बनाने से खत्म हो जाएगी। इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बूढे और बच्चे हैं उनको पेंान दी जाए। अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना चाहें पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आप टैक्स की लीकेज को खत्म कर दें तो आपको और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनके अफसरों से कहा कि आप टैक्स दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। मैं उन भाो की कुछ टिकटें सदन के पटल पर रखना चाहता हूं इनमें कुछ 5 रुपए की कुछ 10 रुपए की और कुछ 25 रुपए की हैं।

Mr. Deputy Speaker: Please givt it to the Secretariat. It will be examined and, if permissible, allowed to be laid on the Table of the House.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं यह कहना चाहता हूं कि टैक्स की लीकेज को रोका जाए और जो कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए। टैक्स मुकम्मल तौर पर वसूल किया जाए ताकि लोग हैवी टैक्सेान से बच सकें।

इसके बाद मैं गऊ माताओं के बारे में कहना चाहता हूं बहुत सी गऊ माताएं कटने के लिए ले जाई जाती हैं, मैं इसके

बहुत खिलाफ हूँ गऊओं की भलाई के लिए एक ड्राई फार्म खोला जाए ताकि जो लाग गऊ नहीं रखना चाहते, वे उन गऊओं को उस ड्राई फार्म में भेज सकें। इस तरह गऊओं की जान बचाई जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं बिजल की महकमे के बारे में कहना चाहता हूँ कि बिजली का महकमा बहुत लापरवाही से काम करता है जिससे आम जनता का बहुत नुकसासन होता है। अभी पिछले दिनों कैथल तहसील के एक गांव में 23 दिसम्बर 1978 को 2 बच्चे और एक भैंस बिजली से मरे। कारण यह बताया गया है कि यह बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मरे हैं। जिन कर्मचारियों की यह लापरवाही है उनको सजा दी जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बिजली के कारण जिनके बच्चों और भैंस की जान गई है उनको मुआवजा देने का एलान किया जाए क्योंकि इन सब बातों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ में हमारी सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए इस बजट में कहीं भी पैसा नहीं रखा गया है उधर पंजाब सरकार चण्डीगढ़ में 1300 मकान बना रही हैं मैं कहना चाहूंगा कि जब तक चण्डीगढ़ का आखिरी फैसला न हो जाए तब तक पंजाब सरकार कैथल में सरकारी बिल्डिंगज नहीं हैं। वहां न तो सब जेल की बिल्डिंग है और न ही तहसील की बिल्डिंग है। लोग होस्पिटल में बैठे रहते हैं। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि कैथल में सरकारी बिल्डिंगज अव य बनाई

जाएं। डिप्टी स्पीकर साहब, कैथल में आई0टी0आई0 की बिल्डिंग काफी बड़ी है लेकिन उसमें ट्रेडज बहुत कम हैं। यदि रेडियो, टैलीविजन, हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनाग्राफी के ट्रेडज और दे दिए जाएं तो इससे आम आदमी का भला हो सकेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, ट्यूबवैल से जो वाटर सप्लाई जोती है उसका रेट सरकार ने बढ़ा दिया है। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। नहरी पानी पर मालिया पहले से ही बहुत ज्यादा लगा हुआ है। इसलिए ट्यूबवैल वाटर सप्लाई पर से यह टैक्स वापिस लिया जाए। इसको पास न किया जाए और जो जमीन पर टैक्स लगा रहे हैं। वह भी सारे का सारा वापिस लिया जाए। किसानों के ऊपर तो पहले ही काफी टैक्स लगे हुए हैं। उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स न लगाए जाएं। इसके बाद जो आपने हलवाईयों के ऊपर टैक्स लगाया है वह भी नहीं लगाया जाने चाहिएं। जो बड़े बड़े सरमाएदारों के बड़े बड़े काम हैं जैसे सिनेमा हैं, फ़ैक्टरीज हैं, जिनसे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है उनको नै पानेलाइज कर के खुद अपने हाथ में लेकर सरकार आमदनी का जरिया बनाएं इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने जो बसों के किराए में वृद्धि की है इससे गरीब जनता पर काफी बोझ पड़ेगा इसलिए इसको भी वापिस लिया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर अपने मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के ऊपर टैक्स न लगाया जाए। यदि किसानों पर टैक्स लगाया जाता है तो मैं इस बजट की पुरजोर मुखालफत करता हूँ।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने सदन में इस बात की घोषणा की है कि वे आज के बाद कभी भाराब नहीं पीयेंगे। उन्होंने बाकी लोगों के लिए एक मिसाल पे 1 की है, एक अच्छा काम किया है, मैं उनको इस बात पर बधाई देता हूँ। पोहलू साहब ने एक बात और की है और वह यह है कि लोकतान्त्रिक पारिपाटी के अन्तर्गत अपोजी 1न के बेंचिज की तरफ से बजट की डिबेट को भुरु किया जाता है। पोहलू साहब के जिम्मे इस डिबेट को आरम्भ करने का काम सौंपा गया था और इन्होंने इस काम को अच्छी तरह से निभाया। यह मैं मानता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चर्चा की है। इससे पहले विपक्ष का एक स्वभाव ही बना गया था कि आलोचना सिर्फ आलोचना करने के लिए की जाए। इस नाते से मैं चौधरी साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सुझाव की भाक्ल में अपने विचार सदन के सामने रखे। सुझाव इसलिए रखे क्योंकि उनको इस बात का अहसास है कि आज तक न केवल हरियाणा में बल्कि सारे दे 1 में जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट पे 1 किया है वह प्रगति की चकाचौंध का प्रतीक बनकर आया है। आज तक हिन्दुस्तान के अंदर जो कुछ किया जाता रहा है वह गांव के लोगों का नाम लेकर किया जाता रहा है। हिन्दुस्तान गांवों का दे 1 कहलाता है लेकिन आज तक जो सरकारें आई हैं वे सब गांवों का नाम लेती रही लेकिन गांवों की आमदनी का सारा पैसा गांवों पर खर्च करने की बजाये चंद लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा था। आज जनता पार्टी ने यह पैसा

गांवों पर खर्च करने का साहस ही नहीं किया बल्कि अपना मौलिक उत्तरदायित्व समझा है कि गांवों के पैसे को गांवों पर ही खर्च किया है और इस बात का एहसास पोहलू साहब को बराबर रहा है। बाढ की रोकथाम के लिए जिक्र किया गया, सडकों के बारे में जिक्र किया गया इसका जवाब देना मेरा काम नहीं है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पोहलू साहब जब बोल रहे थे तो उनके भाषण से एक बात साफ जाहिर थी कि वे इस बात को मानते हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने प्रकृति के प्रकोप को कुदरत की मार को पहले से नहीं जाना क्योंकि पहले ही प्रकृति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुदरत की मार पड गई और पीडित लोगों को सुविधायें देने के लिए जो कुछ जनता सरकार ने किया है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। इस बजट में पीडिल लोगों के लिए जो प्रावधान किया है मैं समझता हूं इसके लिए हरियाणा सरकार और वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। और पोहलू साहब को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार और यह बजट आने वाले प्रकृतिक प्रकोप को रोकने के लिए सजग है। सरकार को भलीभांति इस बात का ज्ञान है और यही कारण है कि बजट को ग्रामोन्मुख बजट बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा प्रांत विशेषकर कृषि के ऊपर आधारित है। इसलिए सरकार ने गांवों में बसने वाले लोगों की हालत सुधारने के लिए अधिक जोर दिया है और यह बिल्कुल वाजिब भी है। इसके साथ ही साथ खेती के सुधारने के लिए अधिक जोर दिया है और यह बिल्कुल वाजिब भी

है। इसके साथ ही साथ खेती के सुधार के मामले, किसानों को सबसिडी बीज और खाद देने के मामले और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के मामले में जो प्रावधान किए हैं वे काबले तारीफ हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, गांवों में वही लोग बसते हैं जिनका गुजारा खेती पर निर्भर है। इनमें से किसी के पास 50 एकड धतरी है, किसी के पास 5 एकड और किसी के पास 1 एकड है; और कई ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है। कृषि के ऊपर आधारितक का अर्थ यह है कि जिस के पास 50 एकड है वह भी कृषि पर आधारित है जिसके पास 5 एकड है वह भी और जिसके पास 1 एकड है या जो भूमिहीन हैं वह भी कृषि पर आधारित हैं। जिसके पास ज्यादा जमीन है वह भी कृषि पर आधारित है और जिसके पास कम है वह भी कृषि पर आधारित है। सरकार ने मौजूदा बजट में, गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जो प्रावधान किए हैं, जो सुविधाएं देने की बात कही है, मैं इसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर हरियाणा में बहुत से ऐसे जमींदार हैं जिनके पास 1 एकड जमीन है यह तो ठीक है कि आंध्र प्रदेश, केरल या कन्याकुमारी के इलाके के लोग एक या दो एकड जमीन में अपना गुजारा कर लेते हैं लेकिन हरियाणा में एक या दो एकड जमीन से गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। हरियाणा में 74 प्रतिशत से अधिक आदमी ऐसे हैं जो 5 एकड से कम जमीन रखते हैं। ये इस जमीन से अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर

सकते, इसी लिए सरकार ने सहायक (एडी गनल) काम देने की योजना रखी है और वह योजना है पशुपालन। बजट में 1200 मिनी डेरी यूनिट बनाने का प्रावधान किया है, इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। ये 1200 यूनिट गांवों के लोगों को अतिरिक्त काम देंगे, रोजगार देंगे। हमें इस बात का तो गौरव है कि हरियाणा को होने वाली आमदनी का 7.5 परसेंट रैवेन्यू, दूध और दूध से बनी चीजों से आता है और सरकार के खजाने में जमा होता है लेकिन इसके दूसरी तरफ इसमें एक वेदना छिपी हुई है; यह तो अच्छी चीज है कि सडकें बनी हैं, परिवहने के साधनों का विकास हुआ, दूध की बढौतरी के कार्य हुए लेकिन खेद यह है कि गांव के मासूम बच्चों के मुंह से दूध छाछ छिनती जा रही है दूध सारा भाहरों में जा रहा है। मैं पशुपालन मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बात की ओर विशेष ध्यान दें हम उनको सहयोग देंगे, पशुपालन के माध्यम से सहायोग देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरफ तुरंत कदम उड़ाये जाने चाहिए हर गांव में गरीब लोग रहते हैं जो छाछ से गुजारा करते हैं लेकिन वे छाछ से महयम हो रहे हैं। इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि उन लोगों को दूध का काम दिया जाए दूध के केन्द्र बनाये जाने चाहिए और दूध कहीं गांव में बिके। जो व्यक्ति इस सिस्टम को जानते हैं बडे योग्य व्यक्ति इस पर सोच सकते हैं एक्सपर्टस सोच सकते हैं कि कैसे सुधार हो सकता है। दूध इसलिए ज्यादा बिकता है कि दूध महंगा है और इसके मुकाबले में घी सस्ता है। सरकार ने 1200 मिनी डेरी यूनिट लगाने की एक योजना बनाई है लेकिन

इसमें एक भात है कि प्रार्थी के पास 1 एकड भूमि होना जरूरी है। जो लोग पशु पालन यूनिट बनायेंगे उनके पास जमीन का होना आवश्यक है। सभापति महोदय, इस भात की आड में कहीं अवसरवादी लोग चतुर व्यक्ति ही फायदा उठा पायेंगे, कहीं ऐसा न हो कि गरीब लोग महरूम हो जाएं इसलिए इस भात को निकाल दिया जाए। गांव के अंदर छोटे किसानों के इलावा बेजमीन और मजदूर भी हैं। ये लोग इस भात के कारण पशु पालन यूनिट नहीं लगा सकते। इसके अतिरिक्त ये जो 1200 यूनिट लगाने हैं इनमें परिगतिणत जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए 20 परसेंट का आरक्षण है। 10 यूनिट का एक समूह स्थापित किया जाए और इस तरह से 1200 यूनिट्स के 120 समूह स्थापित होंगे जो सारे हरियाणा में काम करेंगे। इससे लोगों को काम भी मिलेगा और दूध और छाछ बढ़ाने के साधन भी बनेंगे। 20 परसेंट आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वह वीकर सैव इन आफ दी सोसाइटी (कमजारे वर्ग) को मदद करना है और सरकार भी मदद करना चाहती है। हमारे समाज का जो कमजोर वर्ग है उसकी हालत सुधारने के लिए 20 परसेंट रिजर्व इनकी है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण है, वहां गांव के अंदर बैकवर्ड क्लासिज के तेली, धोबी, कुम्हार वगैरा गरीब आदमी रहते हैं जो जमीन के मालिक नहीं हैं। इनको भी दूध पालन स्कीम में आरक्षण की सुविधा दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इस सैव इन का भी भला हो जाएगा।

सभापति महोदय, यह भी गौरव की बात है कि हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर खेतीबाड़ी के साथ साथ ग्रामीण उद्योग को भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आज तक न केवल इस राज्य में न केवल इस देश में बल्कि सभी जगह सदा से यह रीति रही है कि संपन्न लोग गरीबों के नाम पर लाभ उठा रहे हैं। हमारे पोहलू साहब ने भी इस बात का जिक्र किया मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने गांव के अंदर से सामाजिक कुरीतियों को दूर करके खुलाहाली लाने की जो बात कही उस पर हमारी सरकार अमल कर रही है। सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बजट में सरकार ने बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों द्वारा उद्योग धंधे शुरू करने का जो प्रावधान किया है यह विकास की सही दिशा में चलने वाले राज्य का एक प्रतीक है। आज अपोजिशन बैंचिज की तरफ से यह आवाज आती है कि बेकारी के सुरसा के मुंह को कैसे बंद करे। सुरसा का मुंह बंद हुआ था रामायणकाल में इसे हनुमान ने बंद किया था या आज हमारी सरकार बंद कर रही है। भगवान करे कि यह इस काम में सफल हो क्योंकि इसकी नीयत साफ है और कदम सही दिशा में उठ रहे हैं लेकिन इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ग्रामीण उद्योगों के लिए जहां पैसे की सुविधा, टैक्निकल गाइडेंस की सुविधा और मार्किटिंग की सुविधा दी गई है वहां एक और सुविधा दी गई है जिसका वर्णन करना आवश्यक है। एक वक्त था जब एक व्यक्ति कहता था कि साहब हमें कर्जा दीजिए लेकिन आज सरकार

नागरिक के पास जा रही है कि आईए हम आपको काम देना चाहते हैं आप बताएं कि आप क्या काम कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में डी0आई0सी0 खोले जा रहे हैं। सभापति महोदय, इसमें एक बुनियादी बात छिपी हुई है कि मांगने वाला सरकार के पास न जाए बल्कि अधिकारी जरूरतमंदों के दरवाजे पर जाएं यह योजना बताती है कि वाक्या में यह बात गौरव की है। लोक राज में सरकार का यह निगाना होता है कि सरकार लोगों के पास जाए, लोगों को नौकरगानाही का चक्कर न काटना पड़े। इसदिगाना में सरकार ने चूंकि यह कदम उठाया है इसलिए मैं इस बात के लिए सरकार को दाद देता हूं और बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, एक और बात के लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। समाज कल्याण विभाग के लिए एक विपुल राशि। हमारे बजट में परपोज की गई है यह सही है कि हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। हमारी बुनियादी मंगाना किसी एक वर्ग के लोगों की भलाई करने की नहीं है बल्कि एक समरस समाज बनाने की है। वैल्फेयर स्टेट के अंदर जब तक सभी लोगों के पास अपना गुजारा करने के लिए कोई काम नहीं होता तब तक सहायता देना आवश्यक है। इसके लिए वैल्फेयर डिपार्टमेंट बडी अच्छी योजना लेकर आ रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के विद्यार्थियों को वर्दियां दी जाएंगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी और उनकी फीस माफ होगी। यही नहीं, सभापति

महोदय, इस बजट में एक नई चीज भी है। वह यह कि इस वर्ग की आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को निःशुल्क वर्दी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसको हम शिक्षित बनाना चाहते हैं उसके बारे में हम यह देखें कि उसे न केवल स्लेट या पेंसिल की जरूरत होती है बल्कि यह देखना तो इससे भी पहले है कि जो बालिका स्कूल में जाती है, वह अर्द्ध नग्न अवस्था में जाती है या नग्न अवस्था में जाती है या किस हालत में जाती है। मैं इस बात के लिए इस बजट की प्रस्ताव करता हूँ लेकिन साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग से यह प्रार्थना भी करता हूँ कि इस स्कीम में पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को भी शामिल कर लिया जाए।

सभापति महोदय जी हम जानते हैं कि जब किसी बहिन का पति इस संसार से चला जाता है तो पीछे जो परिवार रहता है उसका गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। ऐसी विधवा औरतों के लिए हमारी सरकार ने निःशुल्क सिलाई सिखाने की योजना बनाई है। यह बात भी बड़ी सुंदर है लेकिन इसमें भी मैं एक संशोधन करवाना चाहता हूँ। यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह स्कीम तमाम वर्ग की विधवाओं के लिए होनी चाहिए चाहे विधवा किसी हरिजन की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, बड़े आदमी की हो, यह स्कीम समाज के तमाम वर्ग के लोगों के लिए होनी चाहिए।

एक बात सभापति महोदय, मैं हाउस बिल्डिंग लोन की बाकत कहना चाहूंगा इस बजट में 8 लाख 20 हजार रुपये का प्रोविजन केवल अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया है। यह भी एक अच्छा कदम है। इसमें भी मेरा सुझाव यह है कि समाज के दूसरे कमजोर वर्गों अर्थात् बैकवर्ड क्लासिज को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाए। हाउसिंग बोर्ड ने मकान बना कर देने की जो परम्परा डाली है, यह बहुत सुंदर परंपरा है। जो भाई, जो गरीब व्यक्ति, कम आमदनी वाला व्यक्ति मकान नहीं बना सकता या मकान बनाने के लिए इतना लोन नहीं ले सकता उनके लिए यह बड़ा अच्छा मौका है कि वह बना बनाया मकान ले ले और कि तों में सरकार को पैसा देता रहे। लेकिन इसमें मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं लो इंकम वालों के नाम पर साधन सम्पन्न लोग ही इस स्कीम का फायदा न उठा जायें और जिनके लिए यह मकान बने हैं वे फायदा न उठा सकें। मिसाल के तौर पर रोहतक की एक बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। एक अच्छे डाक्टर ने अपने परिवार के एक सदस्य के नाम से आवेदन पत्र दे दिया कि आमदनी अमुक सीमा से कम है और मकान उसको अलाभ हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की पूरी कोशिश करे कि जिन गरीब लोगों के पास साधन नहीं हैं जिनकी एक सीमा से कम आमदनी है जिनके लिए यह योजना बनी है उनको ही ऐसे मकान मिले और दूसरे लोग इस योजना को झपट न लें। सभापति महोदय, इस बजट में टैक्स की बढ़ौतरी की

गई है। किसी भी राज्य के कार्य को चलाने के लिए राजस्व की वसूली भी करनी पडती है और करों में बढौतरी करनी पडती है। विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए सरकार को आमदनी के साधन भी जुटाने पडते हैं। मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री महोदय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने दोनों बातों की ओर ध्यान दिया है और कई बातों में लोगों की राहत भी दी है किसानों को सवा छः एकड तक का मालिया माफ किया है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं लेकिन उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास साढे छः एकड भूमि है वे कोई बहुत बडे भूमिबान नहीं हो जाते, वे भी गरीब किसान होते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि सवा छः एकड से लेकर 10 एकड तक जमीन रखने वाले किसानों के मालिये में बढौतरी नहीं की जानी चाहिए। वैसे तो हमारी टैक्स कमेटी भी बनी है वह भी इस बारे में विचार कर रही होगी परन्तु मेरा भी सदन के समुख सुझाव है कि मालिया की प्रस्तावित वृद्धि 10 एकड तक माफ न की जाये

इसी प्रकार से पानी के ऊपर भी आबियाना बढाने का प्रस्ताव आया है। इस विशय में मेरा सरकार से सुझाव है कि पुनर्विचार कर इसे वापिस लें और मुझे यह भी लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा होगा।

सभापति महोदय, मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कुछ विचार रखना चाहता हूँ सरकार की तरफ से बजट में बसों में किराये की वृद्धि के विषय में भी प्रस्ताव आया है जो आज बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब बसों की हालत को देखते हैं कि तो बहुत दुःख होता है। बसें टूटी हुई हैं, कई इलाकों में बसें पूरी नहीं हैं और सड़कें भी खराब हैं। इन सभी बातों को देखते हुए साधन जुटाने भी जरूरी हैं अगर हम अपनी परिवहन को ज्यादा सुंदर और आमदनी के ज्यादा साधन बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा खर्च होना स्वाभाविक है। लेकिन साढ़े बारह परसेंट बसों के भाड़े में वृद्धि होना उचित नहीं है। इसलिए इस बारे में भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जो हम करों से परिवहन की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। उसकी जगह टिकटों में हेराफेरी जो होती है आमदनी की चोरी होती है, उसकी अधिक चेंकिंग कर, इसे रोक कर जो आय बढ़ेगी उससे घाटे की पूति हो सकती है, और भी दूसरे साधन इस बारे में सोचे जा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट और लेना चाहता हूँ। सरकार ने बजट में विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया है। वैसे तो सरकार ने पहले ही रोजगार केन्द्र खोले हुए हैं लेकिन इस बजट में विशेष रोजगार केन्द्र बनाये जाने का प्रावधान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया है। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ। इसमें रिटायर्ड कास्ट को कवर किया गया है। ऐक्स सविर्समैन वैसे तो इस में

कवर नहीं हैं लेकिन ऐक्स सर्विस मैन के लिए सोलजर बोर्ड बना हुआ है जो रिक्रूटमेंट में मदद करता है। परन्तु जो हमारे बैकवर्ड क्लासिज के भाई हैं उनके लिए भी यह सुविधा मिले तो उनका भी भला हो सकता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन लोगों को भी इस स्कीम में शामिल किया जाये। सभापति महोदय, हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बजट का मुख्य मं 11 क्या है ? अगर थोडा बहुत नीचे ऊपर करना पडता है तो भी हमारी नीयत साफ है और जो भी साधन अपनाये जा रहे हैं वे भी बडे सुंदर हैं क्योंकि हमारे जो उद्दे य हैं वे बडे पाक हैं। इन पाक उद्दे यों के पीछे हमारी सरकार की नीयत साफ है इसलिए जो कर बढ़ाये गये हैं उनको कम करने के लिए सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। इस बजट में जो एकाध बातें ऐसी हैं जिनमें सुधार की गुंजाइ 1 है इसलिए सरकार इस तरफ अव य ही ध्यान देगी। इन भाब्दों के साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का और मुख्य मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी योजनायें इस बजट में रखी हैं और जनता की भलाई के लिए कार्य करने का प्रयास किया है। मैं इस बजट की ताइद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): चेयरमैन साहब, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बजट पर बोलने के लिए मुझे पहले ही दिन मौका दे दिया। मैं तो पहले ही हाईकोर्ट में फंसा हुआ हूं और मुझे बहुत की कम टाईम यहां हाउस में मिलता है।

चेयरमैन साहब, हमारी सरकार ने जो बजट पे 1 किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और अपने कुछ सुझाव भी सरकार के सम्मुख रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

इस बजट की आइटम नं० 8 इरीगे टन के बारे में है। हमारी सरकार ने बजट में कई योजनायें बनायी हैं। जैसा कि उन्होंने बजट में दिया है कि नहरों को पक्का कर रहे हैं, खालों को पक्का कर रहे हैं। इनके पक्का करने से जो आज कल मौजूदा आबपासी हो रही है वह डयौढी हो जायेगी दूसरे हमारी सरकार ने पलड की रोकथाम का बडा भारी प्रबंध किया है। इस बात के लिए भी मैं सरकार की सरहाना करता हूँ। पिछले साल और इस साल भी इतनी भयानक बाढ आयी जिससे हरियाणा का बहुत बडा नुक्सान हुआ है। लेकिन हमारी सरकार ने काफी साधन जुटा कर उनका प्रबंध किया। जिन इलाकों में बाढ आई उनमें ड्रैज और बांध बनाने का काम बडे जोरों भाोरों से सरकार ने किया। चेयरमैन साहब, आपको पता है कि मेरा इलाका पलडड की मार में रहता है इसलिए मैं उसके बारे में कुछ विचार हाउस में रखना चाहता हूँ मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं, वे यहां पर होते तो और भी अच्छा रहता।

सभापति महोदय, दिल्ली सरकार ने धांसा बांध की दस हजार क्यूसिक कैपेसिटी बढाने का वायदा किया था परन्तु दिल्ली सरकार ने अभी तक वह वायदा पूरी नहीं किया है। अभी कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आने वाला है अगर बरसात से

पहले यह ठीक नहीं हुआ तो मेरे इलाके को बहुत नुकसान होगा। इसी तरह से मेरे हलके में साहबी नदी की भी पानी आ जाता है उसकी तरफ सरकार का खासतौर पर तवज्जोह देनी चाहिए। ड्रेनों को बढ़ा कर फ्लड के पानी को जमना में डालने का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब से पहले जो सरकार ने बाढ के लिए प्रबंध किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ लेकिन इसके साथ ही साथ एक सुझाव भी देना चाहता हूँ और अपील भी करता हूँ कि किसी भी कहकमे के डिपार्टमेंटल चार्जिज 15-20 परसेंट से ज्यादा नहीं हैं, चाहे कोई सडक बनानी हो या कोई अन्य काम करना हो, लेकिन एम0आई0टी0सी0 के डिपार्टमेंटल चार्जिज साढे सताइस परसेंट हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। ये आइंदा के लिए कम होने चाहिए और जो पहले के लगे हुए चार्जिज हैं वे माफ होने चाहिए। जमीदारों पर नाजायज खर्चा है। इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव दूंगा कि जो साल साल की मियाद पैसा वसूल करने की रखी हुई है यह दस साल होनी चाहिए। इस दस साल के अर्से में अगर कोई खाल टूटे तो उसकी मरम्मत भी एम0आई0टी0सी0 के द्वारा होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, जहां तक नहर के पानी का सवाल है, उसके लिए मैं अपनी सरकार और इंजीनियर्ज को बधाई देता हूँ इस साल जितना पानी नहरों में चला है इतना पहले कभी नहीं चला था। इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ।

दूसरा आइटम पावर के बारे में है। इस बारे में भी सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाये हैं। पिछले कई सालों से

बिजली पर कट लगता आ रहा था और जमीदारों को दिन की बजाए रात को बिजली मिलती थी सरमायेदार निजाम जोरों पर था, दिन में थोड़े से टाईम के लिए बिजली मिलती थी। अकसर रात को ही बिजली मिलती थी। जनता सरकार ने दिन में बिजली देने का प्रबंध किया और पहले से ज्यादा बिजली देने का भी प्रबंध किया। सबसे अच्छा सरकार ने यह प्रबंध किया है फ्लैट रेट पर बिजली के पैसे किसानों से चार्ज करने आरम्भ किये हैं। अब मैं बिजली विभाग के सुधार के लिए सुझाव देना चाहता हूं कि जो गुरुकुल, गुरुद्वारे या मन्दिर गर्भियों में दो महीने के लिए ट्यूबवैल्ज के कुनैव न ले लेते हैं और दस महीने तक ट्यूबवैल्ज बंद रखते हैं उनसे सारे साले के चार्जिज न लिये जायें क्योंकि वे पतुओं को पानी पिलाने का प्रबंध करते हैं। वे धर्म का काम करते हैं। उन पर लाइन चार्जिज और दूसरा फुटकल खर्चा डाल कर काफी अमाउंट ड्यू हो गया है यह माफ किया जाना चाहिये। फ्लैट रेटस पर बिजली का खर्च चार्जन किया जाये क्योंकि वे तो दो महीने ट्यूबवैल चलाते हैं। लेकिन महकमा बदस्तूर उनसे चार्ज करता रहता है। इसीलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस चीज को चैक करे और इस किस्म के अमाउंट को माफ किया जाये अगर चार्ज करना है तो जितने दिन वे मीटर चले हैं उतने दिन का चार्ज किया जाये।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बाबत काफी स्कीमें यहां पर आयी हैं। मैं आपके

द्वारा मंत्री जी को और सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि नये नये बीज, खाद मुहैया कराने के मामले में हमने ज्यादा से ज्यादा तरक्की की है इसके इलावा हम काफी रकबा जेरे का त भी लाये हैं। बीज और खाद सस्ते दामों पर मुहैया कराने की तरफ भी काफी काम हुआ है। जरायत की तरफ हमारी सरकार ने खास तौर पर किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिये जितने ज्यादा से ज्यादा कदम उठा सकती थी उठाये हैं लेकिन मुझे एक बात का दुःख है। यह चाहे हमारी बदकिस्मती समझो चाहे हालात की मार समझो चाहे कोई और बात समझो, किसाने जो चीज पैदा करता है, उसको उसकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती जो चीज वह बेचता है उसकी तो पूरी कीमत नहीं मिलती लेकिन जिस चीज को उसने खरीदना होता है वह उसे दोगुने तिगुने दामों पर मिलती हैं। मैं आपको बताऊं एक जीटर ट्रैक्टर की कीमत 13000 रुपए उस वक्त होती थी जिस वक्त गेहूँ का मूल्य 30-35 रुपए और गुड का मूल्य 40 रुपए क्विंटली होता था। आज उसी ट्रैक्टर की कीमत 40000 रुपए हो गयी है। लेकिन इसके मुकाबले में आज उसके गन्ने को कोई नहीं पूछता। लोग गन्ने को चूल्हों में जलाने लग रहे हैं। इसीलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा यह ठीक है कि आने उसकी पैदावार बढ़ाई है लेकिन उसकी पैदावार की सही कीमत तो कम से कम दिलवाई जाये। आप देखें उसकी खरीदने की भावित बिल्कुल ही कम रह गयी है। क्योंकि उसकी पैदावार की कम कीमत मिल रही है आप देखें आज किसान की सारी की सारी जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी हुई हैं इस बात के लिये तो मैं

सरकार को बधाई देता हूं कि उसने पैदावार बढ़ाने में उसकी काफी मदद की है और काफी से ज्यादा योजनाएं बना रखी हैं। सरकार जमीदानों की पैदावार को हैफड की मार्फत या दूसरी एजेन्सियों की मार्फत खरीदे लेकिन उसे उचित भाव दिलवाने का प्रबंध अवश्य करे और यह जो ट्रैक्टर इत्यादि के इम्प्लीमेंटस हैं, इनको सस्ते भाव पर दिलवाने का प्रबंध करे।

अब मैं एनीमल हस्बैंडरी की बाबत भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि पिछले दिनों इनके महकमे ने बधाई योग्य काम किया है। इस डिपार्टमेंट के नये नये अस्पताल खोले हैं और पशुओं की अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने के लिये विशेषकर गाय वगैरा को पालने के लिये अच्छी सुविधाएं दी हैं यह बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। (व्यवधान) इस महकमे का काम सराहना के लायक है। मुझे उम्मीद है और मैं आपकी मार्फत सरकार को और संबंधित मंत्री महोदय को यह बधाई देना चाहता हूं कि वे किस तरह से अपने महकमे को आगे से आगे बढ़ाते चल जा रहे हैं। इसी तरे से चेयरमैन साहब, डेयरी की तरफ भी हमने काफी प्रगति की है। हमारी स्टेट को वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी रुपया मिला है डेयरी के नये नये प्लांट लगाये जा रहे हैं। मुझे यह भी पता लगा है कि हमारे हरियाणा में इस वक्त दूध का जो भाव दिया जा रहा है, वह भायद ही किसी दूसरी स्टेट में दिया जा रहा हो। इसके लिए भी डिपार्टमेंट बधाई का मुस्तहिक है। लेकिन मैं आपकी मार्फत

सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बल्लभगढ डेयरी प्लांट का काम पिछले दो साल से चल रहा है लेकिन वह अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसे जल्दी से जल्दी मुकम्मल करके चलाया जाये। अंत में मेरा इस डिपार्टमेंट के मुताल्लिक यही कहना है कि इस डिपार्टमेंट का काम भी सराहना के लायक हैं।

कोआप्रे इन डिपार्टमेंट ने भी काफी तरक्की की है। एक तो इन्होंने यह किया कि ये 1600 गोदाम बनाने जा रहे हैं। इस काम के लिये सरकार एक एकड जतीन हर गांव में लेगी और और यह गोदाम सरकार की तरफ से बनायेगी। इसके अलावा सरकार किसानों के लिये यह भी सोच रही है कि जो अनाज उनके घरों में पडा हुआ है उसके ऊपर बैंक उनको कर्जा दें। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को और मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि जिसके वे मुस्तहिक हैं। हमारी पिछली सरकार ने चुनाव सिस्टम खत्म कर दिया था और अपने अपने आदमियों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लगा दिया था। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही इस सिस्टम को खत्म किया। एक चरण तो चुनावों को खत्म हो गया है। और अब दूसरा चरण भुरु होने वाला है जो जल्दी ही भुरु हो जायेगा। हमारी सरकार यह चाहती है कि जितने भी डैमोक्रेटिक अदायरे हैं, वे चुने हुए आदमियों द्वारा चलाये जायें, लोगों द्वारा चुने हुए

आदमी उनका प्रबंध करें। इस महकमे ने भी इस तरह से सराहना योग्य काम किये हैं।

जहां तक पंचायती राज का ताल्लुक है उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी का मैं भी एक मैम्बर हूं। सरकार पूरी तरह से उस तरफ गौर कर रही है कि पंचायतों को ढांचा किसी तरह से ठीक किया जाये। किस तरह से उनको पूरे अख्तियारात दिये जायें और गांव की पार्टीबाजी को खत्म किया जाये। इसकेल अलावा अ गोक मेहता की अध्यक्षता में जो पंचायती राज के सिलसिले में कमेटी बनी हुई थी, उसकी जो सिफारिशें हैं, उनके ऊपर भी गौर हो रहा है कि सरपंच और पंचों को बिना वजह खामखाह सस्पेंड होने से किस तरह से मुक्ति दिलायी जाये। यह सारे मसले सरकार के विचाराधीन हैं चेयरमैन साहब, खासतौर पर हमारे एक आनरेबल मैम्बर चौधरी जगजीत सिंह पोहलू जी ने एक बात कह कर हमारा दिल खट्टा कर दिया। सडकों का जहां तक ताल्लुक है हमारी सडकों की हालत कई स्टेटों से अच्छी है। जहां तक सडकों की मुरम्मत का सवाल है जब से यह कहकमा सरदार लछमन सिंह जी के पास गया है, तमाम हरियाणा में हिन्दुस्तान के रिकार्ड टूट रहे हैं। इसलिये जितनी सरदार लछमन सिंह जी की सराहना की जाये, उतनी कम है। जिस दिन से यह महकमा उनके पास आया है, उन्होंने पिछली सारी कमी पूरी कर दही है। सडकों की मुरम्मत भी चल रही है नई सडकें भी बनने लग रही हैं 90000 के करीब आदमी इस काम

पर लगे हुए हैं। मजदूरों की कमी होने के कारण गांवों में काम करने के लिये आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। पता नहीं ये कहां रहते हैं कहां घूमते रहते हैं। इसा महकमे की जितनी सराहना की जाये उतनी ही कम है मुझे उम्मीद है कि 30 जून 1979 तक हरियाणा के अंदर किलोमीटर के हिसाब से भायद सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा सडकें बन जायेगी जो कि जनता सरकार के आने के बाद बनेगी, इतनी किलोमीटर सडकें पहले भायद ही किसी मंत्री जी के टाईम में बनी होंगी। इस वजह से मंत्री जी खासतौर पर बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने यह एलान कर दिया है कि कोई भी हमारी पार्टी का कैंडीडेट जब तक 1982 के चुनाव में कार पर चलकर वोट मांगने के लिये आपके गांव में न आये तब तक आप उसको वोट बे एक न देना। यह कितनी बडी चुनौती है यह इसलिये नहीं कहाकि ये बहुत बडे आदमी हैं बल्कि इसलिये कहा कि अगर आपकी गांव सडक से न जुडे तो आप बे एक वोट न देनां जो एम0एल0ए0 गरीक हैं और कार नहीं ले सकते। लीडर आफ दि हाउस उनके लिये कार लेने का भी इंतजाम कर दिया वे लोन लेकर अपनी कार भी ले सकते हैं ताकि वे गांव में राय के टाईम पर कार लेकर जा सकें। इसलिये इस महकमे की जितनी सराहना की जाये, उतनी कम है।

17.00 बजे।

चेयरमैन साहब, जहां तक पीने के पानी का सवाल है। महकमे ने बहुत अच्छा काम किया है। चेयरमैन साहब, पब्लिक

हैल्थ डिपार्टमेंट का जहां तक सवाल है इसके बारे में हमारी स्टेट सारे हिन्दुस्तान में सिर ऊंचा करके चल सकती है। इन्होंने न सिर्फ पीने का पानी दिया है बल्कि गांव गांव में फव्वारे चल रहे हैं। पहले हालत यह थी कि लोग गंदा पानी पीते थे, सडा हुआ पानी पीते थे, पे गाब मिला हुआ पानी तक लोग पीते थे और इसका नतीजा यह निकलता था कि लोग बीमार रहते थे। लेकिन अब वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने गांव गांव में पीने का पानी साफ और स्वच्छ पहुंचाया है। साफ पानी पीने से न तो भविष्य में आदमी बीमार होंगे और न ही मरेगी बीमार होंगे। चेयरमैन साहब, सरदार लछमान सिंह जी हाउस में आ गए हैं: मैं कहना चाहता हूं कि सारी योजनाएं और सारा पैसा तो सरकार का है लेकिन बरकत सरदार जी की है। जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है इस महकमे ने बहुत अच्छा काम किया है। जितना काम कांग्रेस भासन के तीस साल में नहीं किया गया उससे ज्यादा काम जनता सरकार ने पिछले दो साल में किया है। उस कांग्रेस सरकार ने उस जालिम सरकार ने मास्टर्स के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया था। ये हमारे मास्टर पूजा के लायक हैं और चेयरमैन साहब, आपको पता होगा कि पिछले जमाने में जब हम लोग पढा करते थे तो मास्टर के सामने कोई चारपाई पर भी नहीं बैठ सकता था लेकिन उस जालिम सरकार ने उन बेचारों मास्टर्स के बिस्तर सिर पर रखवा दिये और उनको बहुत तंग किया। अब हमारे आर्य साहब एजुकेशन मिनिस्टर साहब आए हैं। हमारे जो पन्द्रह सोलह हजार मास्टर थे उनका कोई भविष्य नहीं था।

उनको बड़ी चिन्ता रहती थी कि लेकिन हमारे आर्य साहब ने उनका बहुत भला किया है और उन सबको पक्का कर दिया है। मैं अपने एजुके टन मिनिस्टर साहब से एक प्रार्थना करूंगा कि पिछले दिनों जो एजुके टन में कमी आ गई थी उसको पूरा किया जाये। चेयरमैन साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि स्कूलों की ज्यादा से ज्यादा मुरम्मत की गई है। और ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड हुए हैं। मैं सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में जहां सरकार इतना अच्छा काम कर रही है वहां एक जुल्म करने लग रही है। वह यह है कि रोहतक यूनिवर्सिटी को दिल खोलकर पैसा देने लग रही है। चेयरमैन साहब, उस पैसे को एक ही आदमी इस्तेमाल करने लग रहा है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वहां पर जितने भी तामीरात के काम हैं उनको पी0डब्ल्यू0डभ0 के जरिए कराना चाहिए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां पर एक आर्किटेक्स मि0 झा है, उसको नक्शे बनाने के लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इस काम में वाईस चांसलर का कमी टन फिक्स है और मैं इस इल्जाम को प्रूव कर सकता हूं। हमारी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक आदमी को रुपया दिए चली जाए और उस पर कोई चैक न हो। वहां पर किसी झा के द्वारा किसी सैक्सेना की मारफत रुपया खर्च किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, गांव के स्कूल तो बिना मुरम्मत के पड़े हैं। बच्चों के बैठने के लिए फर्निचर नहीं है और दूसरी तरफ लाखों रुपए का फर्नीचर खरीदा जा रहा है। वहां पर गलीचे खरीदे जा रहे हैं अभी मकान बना नहीं और

गलीचे पहले ही खरीदे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता उनको कहां रखा जाएगा। वी०सी० सारे रुपए को बरबाद करना चाहता है। हमारी सरकार को इस इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने इस बारे में गवर्नर साहब, मु, मंत्री महोदय और एजुके इन मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर सरकार इस आदमी को पैसा देना चाहती है तो इसका वजीफा बांध दे, लेकिन इस तरह से रुपया बरबाद न कराए। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि वी०सी० का इसमें कमी इन फिक्स है और मैं पूव कर सकता हूं, अगर प्रूव न करूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

चेयरमैन साहब, जहां तक स्पोर्ट के महकमे का ताल्लुक है हमारी सरकार का काम सराहनीय है। जब से हमारी जनता सरकार आई है और चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री महोदय और आर्य साहब एजुके इन मिनिस्टर साहब बने हैं तब से खेलनेवाले लडकों की बहुत हौसला अफजाई हुई है। हमारे जो अच्छे लडके थे और जिन्होंने खेलों में नाम कमाया है उनको सरकार ने काफी इनाम दिए हैं और यकीन दिलाया है कि जो लडके रेस में या दूसरे खलों में अच्छे हैं लेकिन वे घर से गरीब हैं उनकी मदद की जाएगी। मेरा भी इस बारे में एक सुझाव है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है लेकिन खेलों में अच्छे हैं उनको वजीफा दिया जाए। इससे हमारी स्टेट के लडके खेलों में आगे आएंगे और जब कभी हमारी लडकों की टीम दूसरे दे तों में जीत

कर आएगी तो उससे हरियाणा का सिर ऊंचा होगा। वैसे मैं यह मानता हूँ कि हमारी सरकार खेलकूद की तरफ काफी ध्यान दे रही है। चेयरमैन साहब, अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जो नए टैक्स लगाए हैं, मैं इनसे सहमत नहीं। वैसे तो इनके बारे में एक कमेटी बना दी गई है और मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूँगा लेकिन मंत्री महोदय जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे मुल्क का और सारी स्टेट का रुझान बना हुआ है कि यह सरकार किसान और मजदूर की सरकार है और गांव के लोगों को भाहर के रहने वालों के मुकाबले में ऊपर उठाना चाहती है। चेयरमैन साहब, यह आव यक है कि स्टेट का खर्च चालने के लिये सरकार को रुपया चाहिए लेकिन यह रुपया वहां से वसूल किया जाना चाहिए जहां से आमदनी हो सकती हो। गांव का आदमी तो पहली ही मरा हुआ है। चेयरमैन साहब, पिछले बजट में आबियाना बढ़ाने के बारे में सोचा गया था लेकिन बाद में उसे वापिस ले लिया गया था। सरकार ने पानी पर टैक्स लगाया है उसको वापिस लेना चाहिए और इसको कहीं और सोर्स से वसूल करना चाहिए। मंत्री महोदय जी ने बसों के किराये में बढ़ौतरी की है। चेयरमैन साहब, मेरा इस बारे में कहना है कि अगर बसों की लीकेज बंद कर दी जाए इनके गोदामों को चैकिंग की जाए और वहां की चोरी रौी जाए स्पेयर पार्टस की चोरी रोकी जाए और सवारियों का बिना टिकट सफर करना रोक दिया जाए तो आमदनी बढ़ सकती है और नए टैक्स लगाने की कोई आव यकता नहीं रहेगी। जब से हमारे नये स्टेट ट्रांसपोर्ट कन्ट्रोलर आए हैं,

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काफी सुधार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आगे और भी सुधार होगा। चेयरमैन साहब, और भी कई ऐसी जगह हैं जहां से आमदनी की जा सकती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी भावना हो कि गांव के रहने वाले पर कोई टैक्स न लगे तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह 33 परसेंट सरचार्ज न लगाया जाए। अगर सरकार ने यह टैक्स लगा दिया तो गांव वालों के अंदर बड़ी मायूसी होगी। अगर सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है तो मेरा कहना यह है कि 18 एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन है उनके ऊपर यह टैक्स लगाया जाए। जिनके पास 18 एकड़ से कम जमीन है उनके कोई भी टैक्स न लिया जाए। इन भावों के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं और सरकार से दरखास्त करता हूं कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे कि किसी भी गरीब आदमी के ऊपर बोझ न पड़े।

श्री गुलजार सिंह (राजौंद): चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है इसके लिए मैं आपका भुक्रगुजार हूँ। आज बजट के ऊपर चर्चा चल रही है। बजट की तार्ईद करते हुए टैक्स वगैरह के बारे में जो एक दो आर्टिडम हैं, मैं उनके बारे में थोडा सा कहूंगा। चेयरमैन साहब, बजट बहुत अच्छा है और हमारे जैन साहब, जिनकी बहुत दिन से चर्चा है, बहुत ही बुद्धिमान हैं। चेयरमैन साहब, आज से नहीं बल्कि सदियों से कांगेस के जमान से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से भी नहीं बल्कि बाद 11हों के जमाने से एक हवा चली आ रही थी कि फलां चीज गांव वालों के

इस्तेमाल करने के लिये नहीं बल्कि भाहर वालों के इस्तेमाल करने के लिये हैं। अच्छा कपडा देहात वालों के लिये नहीं बल्कि भाहर वालों के लिए इस्तेमाल के लिये है। कोई भी अच्छी चीज गांवा वालों के लिये नहीं है बल्कि भाहर वालों के लिये हैं। लेकिन आज युग बदल गया है जनता में जागृति आ चुकी है हर गांव का रहने वाला हर व्यक्ति यह सोचने लगा है कि हम भी इंसान हैं चेयरमैन साहब, टैक्स के मामले में ऐसा वातावरण है कि लोग टैक्सों के विरुद्ध हैं इस बजट में जो टैक्स लगे हैं इनको न लगाया जाए। चेयरमैन साहब, हमारी जनता पार्टी एक मकान पार्टी है और उसके नेता हमारे माननीय चौधरी देवी लाल जी हैं जो कि एक बहुत ऊंचा सत्ता की लीडर हैं किसानों और मजदूरों के पालन हारा हैं, उनका जीवन जदोजहद में गुजरा है। इसलिये मेरा विचार है कि इस माहौल में ऐसी सरकार के और ऐसे अच्छे नेता के होते हुए जो हमारी सरकार की तरफ से टैक्स लगाये गये हैं, यह भाभा नहीं देते। मेरी भाई पोहलू जी ने बोलते हुए भी सरकार की काफी नुक्ताचीनी की वैसे सरकार की तरफ से काम तो बहुत अच्छे हुए हैं पर अपोजी इन बैचिज पर बैठ कर उन्हें कुछ न कुछ तो बोलना ही पडता है। (गोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, काम क्या हुए हैं ? लोग तो ईख को फूंकने लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलजार सिंह: चेयरमैन साहब, मुझ नाचीज की तो यह राय है कि सरकार इसके लिये थोडा बहुत रास्ता जरूर

निकाले कि लोगों के राहत मिलें मेरे विचार में यही ठीक है कि सभी एम0एल0ए0 तथा मंत्री महोदय अपने ऊपर संयम करके थोड़ी थोड़ी बचत करें तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा और टैक्स लगाने की की कम जरूरत पड़ेगी जैसे हमारे बुजुर्ग कहते भी आये हैं कि घर का समय और दखिन की लू भी बराबर होती है, इसलिये हमें हर तरह से कम खर्च करने के प्रयत्न करने चाहिए। चेयरमैन साहब, अभी स्वामी जी को बोलते समय टोका जा रहा था। वैसे तो हर एम0एल0ए0 यह चाहता है कि उसके पास घर हो लेकिन इसके साथ ही साथ हमें उन लाखों लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने हमें यहां पर वोट देकर भेजा है। हमें उनकी बहबूदों के लिये भी कुछ न कुछ करना चाहिए। लोगों को यह आ ता होती है कि हमारे एम0एल0ए0 जिनको उन्होंने वोट दिये हैं वे उनके भले के लिये कुछ न कुछ जरूर करेंगे अतः सरकार को गरीब लोगों व किसान मजदूरों की भलाई के लिये अच्छे काम करने चाहियें और टैक्स को कम करना चाहिए

चेयरमैन साहब, जहां तक तरक्की का सवाल है इस बारे सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। अभी पीछे हमारी स्टेट के अंदर फ्लड का काफी जार रहा और इसकी रोकथाम के लिये हमारी सरकार ने काफी जद्दोजहद के साथ सराहनीय कार्य किया है। चेयरमैन साहब, जो भला आदमी होता है वह सभी की भलाई की बात सोचता है और हमारे मुख्य मंत्री महोदय चौधरी देवी लाल जी ने लोगों की भलाई के लिये

बड़ा कार्य किया है। चेयरमैन साहब, पहले यह होता था कि डी0सी0 और दूसर अफसरान फ्लड इफैक्टिड ऐरियाज को देखने के लिये मौके पर चले जाते थे और टैम्पोररी सा इंतजाम करके आ जाते थे और अगले साल लाखों गरीबों को फ्लड की लपेट से करने के लिये छोड़ देते थे। अब हमारे माननीय नेता चौधरी देवी लाल जी ने अच्छी स्कीम बनाकर पायेदार और परमानेंट हल ढूँढ लिया है और सरकार ने अरबों रुपए का प्रावधान किया है।

चेयरमैन साहब, आपने झज्जर असंध और बहादुरगढ के इलाके देखें होंगे। वह इलाके फ्लड से बिल्कुल मातम का अड्डा बना हुआ था। लोगों की बडी परे ानी थी लेकिन इस सरकार के अच्छे कार्यक्रम के कारण आज हर तरफ खु ाहाली है और लोग आराम से रह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर राहत का काम बडा धीमा चल रहा है। पता नहीं वहां के ठेकदारों द्वारा उजरात में कमी करने के कारण उन ठेकेदारों को मजदूर नहीं मिलते जिसकी वजह से काम बंद हुए पडे हैं इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

चेयरमैन साहब, बिजली के बारे में भी आप को पता है कि हमारी सरकार ने बडा लाजवाब काम किया है, एक मिसाल कायम की। कांग्रेस के भासन काल में हमारे साथ बीती हैं, और हमें अच्छी तरह याद भी है कि आधी रात तक बिजली के फिक्र में नींद नहीं आती थी, बिजली की इंतजार में रातों बैठे रहते थे कि

पता नहीं कब बिजली आती है लेकिन अब हमारी सरकार ने जो लाजवाब काम किये हैं उसके कारण 24 घंटे बिजली मिल रही है पहले बिजली के बिलों पर सरचार्ज लिया जाता था लेकिन अब हमारी सरकार ने यह सारा झंझट ही खत्म कर दिया है और प्लैट रेट सिस्टम लागू करके एक बढ़िया हल ढूँढ निकाला है। लेकिन चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ एक बात सरकार से अब य कहूंगा कि किसानों ने अपने खेत में जो छोटी छोटी चारे की कूटिया लगा रखी हैं उसके ऊपर थोड़ी से ड्यूटी लगी हुई है यह ड्यूटी भी माफ कर दी जानी चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस तरफ अब य ध्यान देगी और इस छोटे से काम को अब य ही पूरा करेगीं

चेयरमैन साहब, नहरी पानी के मुताल्लिक भी मैं अपनी सरकार और अपने मंत्री महोदय जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि उसने लोगों के पीने के पानी का बडा अच्छा प्रबंध किया है लेकिन हमारे राजौंद के हलके में अभी भी पानी की कमी है जिसकी तरफ सरकार को खास तवज्जो देनी चाहिए। कई हलको में पानी दे दिया गया है और हमारे राजौंद का नम्बर काफी पीछे रह गया है। जैसे पहले खाने वाले को काफी खाना मिल जाता है और जो बाद में आता है उसे कम ही मिलता है। और उसके हिस्से में बहुत कम आता है इसी तरह हमारे राजौंद के हलके के साथ हुआ है। इसलिये मेरी सरकार से पुरजोर अपील है

कि सरकार इस कार्य को जल्दी ही करे ताकि राजौंद के लोगों को राहत मिल सके ।

चेयरमैन साहब, एम0आई0टी0सी0 ने जो सिंचाई के कार्य किये हैं मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। एम0आई0टी0सी0 ने बड़े सराहनीय कदम उठाये हैं फिर भी जैसा कि भाई गंगा राम जी ने कहा कि कई इलाके ऐसे हैं जो कागजों में केवल नहरी लिखे हुए हैं लेकिन वास्तव में वहां पर एक बूंद भी पानी की नहीं मिलती। इसके लिये मैं भी एम0आई0टी0सी0 के आफिसरों को मिला और बात की उन्होंने कहा कि जो रकबा बहुत गहरा है वहां पर ट्यूबवैल्ज नहीं लगाये जा सकते। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस तरफ भी गौर करे। यह न हो कि केवल कागजों में ही नहरी लिखा हुआ हो और असलीयत में पानी न मिले। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस तरफ अवश्य जल्दी ही ध्यान देगी और लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। जहां तक वाटर सप्लाई और सडकों का सम्बंध है इनमें तो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद खास कर सरदार लछमन सिंह जी के मिनिस्टर साहब बनने के बाद इंकलाब सा भुरू हो गया। वैसे मैं अपने हल्के के बारे में एक बात जरूर कहूंगा ताकि सरदार जी को दोबारा याद आ जाए। मेरे हल्के में 29 गांव हैं और सभी में खारा पानी है। सरदार जी ने इस बारे में मुझे पूरा यकीन दिलाया था कि वह इलाका भी पीदे नहीं रहेगा, उसको भी सुधार देंगे लेकिन

अभी इस दिना में कदम नहीं उठाये गये। जहां तक बच्चों की पढाई का ताल्लुक है इसमें सुधार लाने के लिये हमारे आर्य साहब ने कोई कसर नहीं छोडी है आप देखेंगे कि 15 हजार टीचर्ज बेचार भटकते फिर रहे थे। उनकी बात को आर्य साहब ने सुना और रैगुलर किया। इसके अलावा जिस टीचर ने यह कहा कि मैंने अपने मुहल्ले के स्कूल में लगना है, उसको वहीं लगा दिया। यह तो शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन मैं उनको हाथ जोड कर प्रार्थना करूंगा कि वे बच्चों की पढाई की तरफ भी ध्यान दें। बच्चे ही सारे देश का ढांचा है। आज हरियाणा में शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। अगर शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं लाया जाएगा तो इससे हमारे बच्चों का भविश्य उज्ज्वल नहीं होग। मुझे बडी खुशी होती है जब टीचरों को सहूलियत दी जाती है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसके साथ साथ तालीम में भी सुधार किया जाए। तालीम की बात चल रही है इसलिये मेरे को रोहतक मैडिकल कालेज की एक बात याद आ गई। वहां पर पिछले साल यह फैसलाच हुआ था कि 20 प्रतिशत सीटें देहाती लडकों के लिये रिजर्व रखी जाएंगी यह बात अमल में भी आई लेकिन बाद में इस बात को लेकर हाई कोर्ट में रिट हो गई क्योंकि देहात के रहने वाले भूखे व्यक्ति को कोई डाक्टर बनाना पसंद नहीं करता। सुना है हाई कोर्ट ने उस फैसले का रद्द कर दिया है। ठीक है हाई कोर्ट को हम चेलेंज नहीं कर सकते लेकिन मैं सरकार से जरूर कहूंगा कि सरकार देहातियों की भलाई

के संबंध में जरूरर कुछ न कुछ सोचे ताकि देहात के लोग भी डाक्टरी लाइन में आ सकें ।

जहां तक लैंड रिकलेमे ान का संबंध है इस वि ाय में भी बहुत तरक्की हुई है करनाल जिले में और खास कर गोहाना और रोहतक जिलों में बहुत सी जमीनें बेकार थीं लेकिन अब उनकी बहुत तरक्की हुई है हमारी सरकार ने इस कार्य में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरकी की है । मैंने देखा है कि पानीपति से रोहतक जाते हुए गोहाना तक मीलों का रकबा बेकार पडा है और उसके बारे में पता करने पर यह मालूम हुआ कि यह जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भामलात जमीन है । भूमि सुधार के मामले में आज हरियाणा बहुत आगे है इसलिये मेरा यह सुझाव है कि क्यों ने ऐसा कानून बना दिया जाए जिसके तहत सरकार पंचायतों से यह जमीन लेकर उसका सुधार करे, बे ाक बाद में अगर सरकार चाहे तो उस जमीन को पंचायतों का ही लौटा दें । इस तरह की जमीन सफीदों, गोहाना और रोहतक में बहुत ज्यादा पडी हैं

जहां तक ट्रांसपोर्ट का संबंध है इसमें भी हमारी जनता सरकार बनने के बाद बहुत सुधार हुआ है । बहुत नई बसें आई हैं । पोहलू साहब कह रहे थे कि जीन्द में बसों की बहुत बुरी हालत है लेकिन आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि जींद को तो हरियाणा के बीच मैं से गुजरने वाली बसों का सेंटर बना दिया जाएगा यानि सारी बस सर्विस वहां से चलेगी । मैं चीफ

मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमारी इस
िकायत को दूर किया है।

जहां तक हैल्थ का संबंध है इस क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय काम हो रहे हैं। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गांव गांव में जा रहे हैं और हस्पतालों का उदघाटन कर रहे हैं 30-30 बैडों के हस्पताल बन रहे हैं। इस चीज में भी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। मैं भी सरकार को छोटी सी राय देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे हल्के में भी बड़े से बड़ा हस्पताल बने। जहां तक मेरी अपनी राय है वह है कि हस्पताल तो हर जगह बनाने चाहिए और बैडज की तादाद जरूरत के मुताबिक होनी चाहिये। हमारे गांवों में तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होने पर हस्पताल में जाना पंसद करते हैं। यह ठीक है कि हस्पताल हर जगह होना चाहिए लेकिन वह जो बैडों की तादाद बढ़ाने की दौड़ लग रही है यह गलत बात है। एक छोटा सा गांव है वहां पर भी 30 बैड का हस्पताल बने और एक काफी बड़ा गांव है वहां पर भी 30 बैड का हस्पताल बने, यह बात ठीक नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि हस्पताल हर गांव में खोला जाए चाहे वह पांच बैडज का हो, चाहे छः बैड का हो चाहे दस बैडज का हो यानी जरूरत के मुताबिक बैडज की संख्या निश्चित की जाए। ऐसा करने से जैन साहब के खजाने को भी राहत मिलेगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस सुझाव पर भी जरूर गौर किया जाए। पोहलू साहब कह रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद

कोई काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ यह तो लीडर आफ दि अपोजी इन के फर्ज अदा करने वाली बात है। हरियाणा में जनता सरकार बनने के काद इतने काम हुए हैं जिनको गिनवाया नहीं जा सकता कुछ मोटे काम हैं जिनको मैं गिनवाता हूँ; ये काम हैं बिजली का काम, बैंको का सूद कम करने संबंधी काम, खाद की कीमत कम करने का काम। खाद के मामले में तो सैन्टर से पहले ही हमारी सरकार ने कमी कर दी। इसके अलावा गन्ने के रेट में करोडो रुपए की सबसिडी दी गई है। हमार यहां इतने काम हुए हैं कि अगर मैं उनकी तारीफ करने लगूँ तो दो घंटे तक खत्म नहीं होगी। बजट के बारे में मैं यही कहूँगा कि पहली बार देहात की डिवैल्पमेंट के लिए बजट में इतना तगडा कदम उड़ाया गया है। टैक्स तो हमे 11 से लगते आए हैं और लगते भी रहेंगे क्योंकि इसके बिना सरकार का काम नहीं चल सकता फिर भी मैं जैन साहब से प्रार्थना करूँगा कि आज हवा ऐसी है कि टैक्स कम से कम लेगे इसलिये वे कोई न कोई ऐसा नुकता ढूँढें जिनसे यह टैक्स माफ हो सके और विभागों को राहत मिल सके। चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर इस बजट की पुरजोर ताइद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल): आदरणीय चेयरमैन साहब, बजट के बारे में मैं कुछ आइटमों पर बोलना चाहूँगा। पहली आइटम आर्थिक व्यवस्था पर है इस पर मैं कहूँगा कि पिछले

तीन चार साल से हमारे हरियाणा में बाढ आनी भुरू हुई उसके कारण जनता परे तान हो गई बारि 1 के दिनों में मेरा जिला एक प्रकार का समुद्र दिखाई देता था। लेकिन उस पानी को जब उजीना डाइव र्नि ड्रेन के जरिये निकाला गया तो उससे किसान को बहुत राहत मिली। बारि 1 की वजह से पहले जो तबाही होती थी अब उसका नामोनि तान नहीं है।

चेयरमैन साहब, इस प्रकार की तबाही अगर कांग्रेस सरकार के वक्त में आती थी तो किसान परे तान होता था, उसके पास पीने का पानी नहीं होता था। आज हम देखते हैं कि बाड को रोकने के लिये जो खालें बनाई गई हैं उनसे किसान की पूरी इमदाद हुई है जब से हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अमीर गरीब सभी खु 1 हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि श्रमदान द्वारा नालियां बनायी गई। यह काम एक आदमी नहीं कर सकता और जब सब ने मिलकर एकम किया ड्रेज बनायी तो किसानों को बेहद खु 1ी हुई जो बाढ का पानी किसानों के खेतों में और घरों में भर जाता था वह ड्रेज के जरिए से बाहर निकल गया। दूसरी बात यह कि जिस काम को करने के लिये सरकार का काफी पैसा लग सकता था वह श्रमदान के थोडे से पैसे से हो गया। इससे जनता में वि वास बनता है कि अगर वे खुद काम करें तो कितना अच्छा है। श्रमदान से जो काम हुआ है वह सराहना के काबिल है। साथ ही मैं चाहूंगा कि मेरे पलवल के क्षेत्र में 40 ड्रेज हैं जो यू0पी0 गवर्नमेंट के अधीन हैं उनसे पानी लैने

में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि न उनकी रिपेयर का काम होता है न मिट्टी निकाली जाती है। हमारी सरकार को आशा है कि इन ड्रेज को यू0पी0 गवर्नमेंट से टेक ओवर कर लिया जाए परन्तु यू0पी0 गवर्नमेंट आसानी से नहीं दे रही है। हमारी सरकार को आशा है कि इन ड्रेज को जल्दी से जल्दी अपने अधीन ले ले ताकि पलवल क्षेत्र में ड्रेज ल जाने में जो परेशानी होती है वह आगे के लिये दूर हो जाये और जो जमीन बेकार पडी हुई है उसका सही इस्तेमाल हो सके। अगर हमारी यू0पी0 सरकार से ये ड्रेज अपने अधिकार में ले ले तो मैं समझता हूँ कि सरकार बधाई की पात्र होगी। इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे इंजिनियर्स और मजदूर भी बधाई के पात्र होंगे। इस डाईवर्सन पर जिन कर्मचारियों ने काम किया है वह सारे का सारा सराहनीय हैं मजदूर बहुत काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर तो तीन तीन चार चार फुट कीचड होती है परन्तु वे फिर भी काम करते रहते हैं। कीचड में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ हमारे इंजिनियर्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने यह काम किया। साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पहले किसान को खेती के लिये पूरी बिजली नहीं मिलती थी, बड़े बड़े कारखानेदारों को ही दी जाती थी। किसानों को पूरी बिजली देने से सारे सारे हरियाणा की पैदावार लगातार बढ़ रही है जिससे आम आदमी भी इस मदद से खुश है। सरकार ने 24 घंटे बिजली देकर किसानों को राहत दी है। यह भी आवश्यक है कि गांवों में छोटे छोटे कारखाने खोले जायें और इन कारखानों को बिजली भी दी

जायेगी यह तारीफ की बात है। साथ ही बिजली से ट्यूबवैल चलाये जायेंगे यह भी सराहनीय है। लेकिन मैं एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा कि पलवल क्षेत्र में दस दस घरों के छोटे छोटे गांव हैं लेकिन आज भी उनको पीने का पानी मुहैया नहीं हुआ। मंत्री महोदय मेरे इलाके में जायें और देखें कि क्या हालत है। मैं उनकसे निवेदन करूंगा कि इस इलाके में सात गांव ऐसे हैं जहां लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। उनके लिये पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है, आज भी तमाम के तमाम लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। मेरे पास इन गांवों का नक्शा है, इसमें दी गई इंडिकेटरों से आपको पता लग जायेगा कि यहां का पानी बिल्कुल खारी है। यहां खारी पानी की बैल्ट है जिसमें आबपा भी नहीं हो सकती। आबपा भी न होने के कारण लोग बारिश के पानी पर डिपेंड करते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस इलाके में पीने के पानी का प्रबंध किया जाये। (इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा पदासनी हुए) मेरे इलाके के 18 गांवों में से 7 गांव ऐसे हैं जो जोहड़ का पानी पीते हैं। उनको पानी दिया जाये ताकि पानी पीने के साथ साथ वे खेतों की सिंचाई भी कर सकें। सिंचाई की स्कीम के अंतर्गत जो माइनर्ज सैकशन की गई है उन्हें सैकशन किये हुए 8 साल हो गये। आप दो तीन करोड़ रुपया पंजाब के एरिया में नहर निकालने के लिए पंजाब सरकार को दे चुके हैं परंतु अभी तक कोई प्रबंध नहीं हुआ है। अगर इस पानी का इंतजाम को जाये तो विकास कार्यों में इस वक्त जो रुकावट आ रही है वह

दूर हो जायेगी। अगर यह रूकावट दूर न हुई तो पता नहीं कैसे लोगों का काम चलेगा। पानी के सिलसिले में अभी अभी मुझे एक लैटर मिला था उसमें लिखा था कि 12 किलोमीटर लम्बी खारे पानी की बैल्ट है जहां पर पानी ले जाने में मुश्किल हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे अधिकारियों और मंत्री महोदय से अगर 12 किलोमीटर लम्बी ड्रेन नहीं ले जायी जाती तो उन लोगों को आज भी जौहड का ही पानी पीना पड़ेगा। ये लोग बरसों से जौहड का पानी पीते आये हैं और आज भी वे पी रहे हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने अधिकारियों से कह कर नालियां बनाने का इंतजाम करें। इस इलाके में औरतें तीन तीन मील की दूरी से पानी लेकर आती हैं। अगर वे तीन तीन मील से पानी ला सकती है तो क्या कारण है कि हमारी सरकार 10-12 मील लम्बी ड्रेन नहीं निकाल सकती। यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

अब मैं सडकों के बारे में कहूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में पिछले दो साल से एक भी सडक नहीं बनी। यह खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की भावना है कि हर क्षेत्र में सडकों का निर्माण हो। यह अच्छी भावना है परन्तु मेरे इलाके में पिछले दो साल में केवल 4 किलोमीटर तक भी सडकें बनी हैं। अब कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर कहीं 40-40 किलोमीटर तक भी सडकें बनी हैं अब कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर सडकों का काम पूरा हो जायेगा, यह दूसरी

बात है। जैसे एक आदमी भूख है और उसको कहा जाये कि अभी तीन चार दिन और ठहर जाओ, उसके बाद रोटी मिलेगी, यह आवासन ठीक नहीं है। इसी तरह हमें भी आवासन दिया जा रहा है कि जल्दी सडकें बनवायेंगे। अब देखना यह है कि कब तक यह काम पूरा होता है। क्या इस क्षेत्र में नई सडकें बनाने का कोई प्रोग्राम सरकार चालू करने जा रही है? जहां लोग पैसा दे सकते हैं, सडकें बनाने के लिए वहां भी सडकों का बनना जरूरी है।

चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो रिवाइज्ड सेल्ज टैक्स सिस्टम चलाया जा रहा है, इससे स्टेट को 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस घाटे को पूरा करने के लिए हमें फजूलखर्ची बंद करनी चाहिए, हमें अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए। जब हरियाणा में जनता सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऐलान किया था कि जनता पर कोई टैक्स हमारी ओर से नहीं लगाया जायेगा। हम टैक्स बढ़ने नहीं देंगे बल्कि इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता से किये गये वे वायदे काहं गये? आज तक टैक्स तो बढ़ते ही गये हैं हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम कर्ज कम लें और खर्चों में कमी करें ताकि यह 35 करोड़ का घाटा पूरा हो सके। टैक्स लगाना कोई बढिया कदम नहीं है। हमारे मंत्री महोदय को चाहिए कि सेल्ज टैक्स को खत्म करें। मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारी स्टेट को

60 करोड की आमदनी टैक्स से ही होती है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार यह कोर्न को करे कि सेल्ज टैक्स को खत्म किया जाये। सेल्ज टैक्स खत्म करने से हमें जो नुक्सान होगा उस नुक्सान का आधा यानी 30-35 करोड का नुक्सान रहता है इसको आप सरकारी खर्च में कमी करके पूरा कर सकते हैं। अगर आपने दुकानदारों पर टैक्स लगाना ही है तो दुकानदार पर फिक्सड टैक्स लगा दिया जाए। अगर दुकानदार फिक्सड टैक्स देगा तो वह काफी परे गानियों से बच जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय जानते हैं कि दुकानदारों के लिए सैल्ज टैक्स एक परे गानी की चीज है। चेयरमैन साहब, सेल्ज टैक्स के जो फार्म दुकानदारों को सप्लाई किए जाते हैं वे अंग्रेजी में होते हैं। बहुत सारे दुकानदार अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनको बडी मुकिल का सामना करना पडता है। मुकिल से 5 परसेंट दुकानदार ऐसे हैं जो उस फार्म को कम्पलीट भर सकते हैं। जब ये हिसाब पे ग करते हैं तो उनके तरीके से पास कराया जाता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस फार्म का अच्छी तरह से निरीक्षण करके सादा करें या हिन्दी भाशा में प्रिंट करें और हिन्दी भाशा में भी बिल्कुल सिम्पल हो। मंत्री महोदय जब सदस्य थे तो कहा करते थे कि फार्म सिम्पल होने चाहिए लेकिन अब मंत्री महोदय बनने के बाद इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं ? मुझे यह समझ नहीं आता कि छोटे हलवाईयों पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं ? बजट में 40 हजार रुपए वार्षिक बिक्री करने वाले हलवाईयों पर टैक्स लगाने का प्रावधान

किया है। जो साधारण हलवाई हैं, होटलों वाले हैं यदि उनके पास सेजल टैक्स वसूल करने के लिए कोई अधिकारी आये तो भायद 50 या 100 रुपए की मिठाई उनको रि वत के रूप में लिखनी पड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा ? मैंने अपने मंत्री महोदय को लिख कर दिया कि मैं उनसे इस मामले पर बातचीत करूंगा। मैं समझता हूँ कि आमदनी के जरिए ऐसे बनाए जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़े और गरीब तबके पर भी बुरा असर न पड़े। चेरमैन साहब, अब मैं करण्डान के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारी जनता पार्टी ने कहा था कि हम करण्डान को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से यह करण्डान दूर होगी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एक नारा दिया है कि 'पानी का प्रबन्ध भ्रष्टाचार बंद' मैं समझता हूँ कि आज उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया होगा। वास्तव में आज भ्रष्टाचार कम नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। जो लोग हमारे पास आते हैं, चाहे किसी आफिस से आए, चाहे किसी और जगह से आए, सब यही कहते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस बारे में सरकार की ओर से यह कह देना काफी नहीं है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके नाम हमारे पास लिखे हुए हैं। आप अपनी सीआईडी या दूसरे लोगों के द्वारा यह पता करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो और इसको कैसे दूर किया जा सकता है ? यह ठीक है कि कुछ दिन हमारी जनता पार्टी में भ्रष्टाचार कम होता दिखाई दिया था लेकिन आज यह भ्रष्टाचार फिर बढ़ रहा है। मैं जनता पार्टी का

सदस्य होने के नाते यह बात कहने के लिए मजबूर हुआ हूँ। इस सरकार से जो सहूलियतें जनता को मिलनी चाहिए थी, आराम मिलना चाहिए था। करण कम होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। आप बड़े किसानों को छोड़ें, बड़े व्यापारियों को छोड़ें लेकिन जो साधारण किसान हैं, जो साधारण मजदूर हैं और विद्यार्थी हैं या कोई सरकार एम्पलाई हैं, चाहे कोई भी है, आज कोई भी वर्ग सुख की सांस नहीं ले रहा है। चेरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि हमें यह निरीक्षण करना होगा कि हम किस प्रकार से भ्रष्टाचार बन्द कर सकते हैं।

अब मैं पानी के बारे में कहना चाहता हूँ। यह कहा गया है किसानों का ट्यूबवैल से पानी दिया जा रहा है। अगर हमारा किसान वर्ग देश की पैदावार बढ़ाता है तो यह बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की बात कहूँगा कि मेरे क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बहुत होती है। एक भूगर मिल को ओप्रेटिव बेसिस पर लगाने की प्रयत्न थी और उसके भोयर भी काफी बिकवाए थे लेकिन आज तक वह मिल नहीं लगाया गया। गन्ना मेरे क्षेत्र में 5 रुपए क्विंटल बिक रहा है लेकिन दूसरी कई जगहों पर 10 रुपए क्विंटल तो वैसे ही बिकता है, इसके साथ ही साथ 2 रुपए क्विंटल सरकार उसको सबसिडि भी दे रही है। मैं इस बात को कहने से नहीं हिचकिचाऊँगा कि या तो हमारे क्षेत्र में किसानों को सबसिडी दी जाए या वहां पर भूगर मिल लगाया जाए। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि गन्ने

की का त कम की जाए। यह बात ठीक है, लेकिन जहां गन्ना बोया हुआ है या किसी मजबूरी से किसान को गन्ना बोना पड़ता है तो उसको भी युटिलाइज करने के लिए कोई आल्टरनेटिव रखना पड़ेगा। अगर सरकार का यही फैसला है कि वहां पर भूगर मिल नहीं लगाएंगें तो रोजाना जो हजारों आदमी आकर कहते हैं कि हमारा भोयर वापिस कर दो, उनके भोयर वापिस होने चाहिए। सरकार के पास लाखों रुपए के पड़े हुए हैं।

श्री सभापति : भूगर मिल लगाने के लिए तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिखा था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एप्रूवल नहीं दी।

श्री मूल चन्द मंगला: मैं यह कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को एप्रूवल देने के लिए मजबूर किया जाए। हमारे मुख्य मंत्री महोदय अभी होडल गए थे वहां पर हजारों किसानों ने ि आकायत की थी कि हमारा गन्ना 4 रुपए किंवटल भी नहीं बिक रहा। मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात को माना कि इसको कोई न कोई आल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। वहां पर कोआप्रेटिव बेसिज पर भूगर मिल लगाने की सैंकान हो चुकी थी और भोयर बेचकर पैसा इकट्ठा किया गया था लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। अगर मिल नहीं लगानी है तो ये पैसा वापिस किया जाए ताकि लोगों से कह सकें कि यह स्कीम अभी चलने वाली नहीं है। चेयरमैन साहब, या तो सरकार यह फैसला सुना दे कि मिल नहीं चलनी है या अगर कुछ उम्मीद की जाती है कि

साल या 6 महीने के अंदर मिल लगा देंगे तो हम लोगों से सरकार कह कह सकती है कि और भोयर बिकवाओ। यदि यह बात सही है कि भूगर मिल लगाने की इजाजत केन्द्रीय सरकार नहीं देगी तो फिर मैं यही कहूंगा कि उनके पैसे वापिस किए जाएं।

चेयरमैन साहब, अब मैं बस अड्डों और बसों के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के पलवल की आबादी 70 हजार है और उसके इर्द गिर्द 700 गांव लगते हैं लेकिन इनको बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। 250 बसें रोजाना वहां से गुजरती हैं लेकिन बस स्टैंड नहीं बना है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय वहां गए थे उन्होंने बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी और 3 लाख रुपए मंजूर भी किए थे। मिट्टी तो पड गई है लेकिन बस स्टैंड आज भी आसमान के नीचे खडा हुआ है कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई है। कई बार देहता के आदमी रात के दस दस, ग्यारह ग्यारह बजे तक बस की इंतजार में रहते हैं। जब कोई बस नहीं मिलती तो उनको सर्दी, गर्मी और बारिश में वहीं ठहरना पडता है, लेकिन अफसोस की बात है कि वहां ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है। गुडगांव जिले की आबादी लगभग 55 हजार की है, वह जी०टी० रोड पर आबाद हैं। वहां से 250 बसें रोजाना गुजरती हैं दूसरी स्टेटों की बसें भी गुजरती हैं। तकरीबन 100 बसें प्राइवेट भी चलती हैं। इन हालात को देखते हुए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वहां पर बस स्टैंड जरूर बनाया जाये और जनता की इस परेशानी

को दूर किया जाये। बस स्टैंड के साथ साथ दुकानें भी बनाई जा सकती हैं। इन दुकानों से किराये के रूप में सरकार को 5 हजार रुपये हर महीने आमदनी हो सकती है। इस वक्त वहां पर प्राइवेट लोगों ने दुकानें बना रखी हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर बस स्टैंड के साथ साथ दुकानें भी बना दी जायें तो जितना रुपया बस स्टैंड के बनाने पर खर्च होगा वह दुकानों की आमदनी से 5-7 साल में वसूल हो सकता है।

श्री सभापति: मंगला साहब, आप एक एक प्वायंट को ब्रीफली बता दें ताकि सारा कवर हो जाए।

श्री मूल चन्द मंगला: चेयरमैन साहब, मैं अभी दो मिनट में खत्म करता हूँ। इसके बाद में शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि शिक्षा के विषय में हमारी सरकार ने जितनी हिम्मत की है, जितना काम किया है यह बहुत ही अच्छा है। लेकिन जितना शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में आप देखें, टीचर्स जितना काम करना चाहते हैं, उतना वे कर नहीं पा रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंग इतनी खराब हैं कि उनमें बैठने को दिल नहीं करता। अगर बैठने का स्थान सुन्दर हो तो बच्चे का दिल बैठने के लिए करता है। अगर बिल्डिंग अच्छी बनी हो और 100-200 पौधे छाया के लिए लगे हों तो बच्चे छाया में बैठकर पढ़ सकते हैं। उस स्थान पर बच्चों का भी मन नहीं लगता जहां बिल्डिंग अच्छी नहीं है। बच्चों को मिट्टी में बैठना पड़ता है। अगर ज्यादा नहीं

तो कम से कम 100-200 पौधे लगा दिए जाएं ताकि बच्चे दरख्तों के नीचे हो तो पढ़ सकें। सर्दी में, वर्षा में उनको बडी परे ानी होती है। पलवल गर्ल्ज हायर सैकंडरी स्कूल के 22 सैंक ान हैं और वहां पर 700 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से 300 देहात से आते हैं। जब वर्षा होती है तो स्कूल की छुट्टी जो जाती है। बच्चे तो तीन मील से पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन वर्षा हाने पर उनको भारण लेने के लिए जगह नहीं मिलती। परिणास्वरूप उनको वापिस घर आना पडता है। पलवल के लोगों ने 1 लाख रुपया इकट्ठा करके बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है और 25 हजार और दे देंगे। इस तरह वहां से सवा लाख रुपया मिल जाएगा। इस वक्त जो बिल्डिंग बनी हुई है वह 150 साल पुरानी है केवल 7-8 कमरे और वे भी टूटे फूटे पडे हैं। सवा लाख रुपया लोग इकट्ठा करके देंगे और सवा लाख रुपये को गवर्नमेंट इंतजाम करें। इसा तरह अढाई लाख रुपये से यह काम हो सकता है और लोगों को सहूलियत हो जाएगी। जहां आप करोडों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां इतनी बडी आबादी की सहूलियत के लिए गर्ल्ज स्कूल बनवा दिया जाए। एक तरफ तरफ हम कहते हैं कि बेटियों की िक्षा के लिए वि ेश प्रबंध कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको बैठन के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए सवा लाख रुपया आपके माध्यम से सैंक ान होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बजट से पहले यह स्कूल बन कर तैयार हो जाएगा पलवल के अंदर 55 हजार की आबादी है लेकिन एक होस्पिटल सिर्फ 30 बैड का सैंक ान है, मरीज बहुत ज्यादा हैं। लोगों को

पूरे साधन न होने के कारण 200 रुपये की टैक्सी करके दिल्ली में मरीज को ले जाना पड़ता है। 55 हजार की आबादी है लेकिन इसके सामने 30 बैड का होस्पिटल कुछ मायने नहीं रखता, इसलिए 30 बैडज की जगह 100 बैडज का हस्पताल बन जाए। मैं चाहूंगा कि अगले साल मुख्य मंत्री महोदय इस हस्पताल की ओपनिंग सैरेमनी लिए आयेंगे और कम से कम आज हमें वि वास दिला दें कि 100 बैडज का हस्पताल बन जाएगा। एक्स-रे की भी बड़ी आव यकता है और भी कई सहूलतें हैं जो नहीं मिलतदं और लोगों को टैक्सी करके दिल्ली जाना पड़ता है। वहां के डाक्टर एक्सपर्ट हैं, हड्डी के मामले में बहुत अच्छे हैं। लेकिन बैडज केवल 30 हैं और मरीज 150 होते हैं। बहुत से मरीज को जमीन पर सोना पड़ता है। डाक्टर भी दिल्ली रहते हैं रोज उनको दिल्ली से आना पड़ता है। इसलिए लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए 100 बैडज का हस्पताल बनाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त स्टेट में अनेकों महकमें हैं, इन महकमों में बहुत से महकमें ऐसे हैं जिन में फजूल खर्ची होती है। इस फजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार को कोर्िा करनी चाहिए। किसी न किसी तरह से फजूलखर्ची को बन्द किया जाए और जनता के ऊपर कम से कम टैक्स लगाने चाहिए। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो टैक्स इन्होंने कजट में बढ़ाया है इसको वापिस लें। किसान के ऊपर जो टैक्स लगाया है चाहे पानी के ऊपर लगाया है, किसी और चीज पर लगाया है, इसको

वापिस लें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टैक्स से सरकार को कोई फायदा नहीं है आज कुरुप इन बढ रही है, इस कुरुप इन को रोकने के लिए सरकार एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठाए जो यह देखें कि कुरुप इन क्यों बढ रही है आढैर महकमों में फजूलखर्ची क्यों हो रही है। अगर इस चीज को रोकने में सरकार कामयाब हो गई तो टैक्स बढाने के बला से जनता को भी छुट्टी मिलेगी और सरकार भी सुख का सांस लेगी।

चौधरी नारायण सिंह (पटौदी-अनुसूचित जाति):

चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसी लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो चार सुझाव आपके सामने रखूंगा। चेयरमैन साहब, के पडौस में मेरा हलका लगता है। इस हलके में दो गांव हैं अमरखेडा और बारकपुर। इनके बीच सडका का एक टुकडा है अगर यह बना दिया जाए तो जनता को बडी सहूलियत मिल जाएगी मेरी कांस्टीच्युएंसी और चौधरी साहब की कांस्टीच्युएंसी में रेत बहुत ज्यादा है, बैल, बैलगाडी नहीं खींच सकते। अगर सडके बना दी जाए तो मंडी अनाज आ सकता है, आमदोरफत बढ जाएगी, आसपास के गांवों की फसल मंडी में जायेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ फौरी ध्यान देगी।

अगली बात ट्यूबवैल्ज कुनैव इन की है। अगर जमींदार बिजली के बिल देने में थोडी सी देर कर देत तो फौरन कुनैव इन काट देते हैं। जमींदार को दो तीन दिन का नोटिस बोलना चाहिए ताकि वह अपनी फसल को पानी देने के उद्दे य से

बिल जल्दी जमा करवा दे और अगर फिर भी बिल जमा न करवाये तब काट दिया जाए। एकदम नहीं काटना चाहिए। एक तरफ किसान ने अपनी फसल को पानी देना होता है और दूसरी तरफ कुनैव न काट दिया जाता है इससे किसान को बडी परे ानी होती है। कम से कम दो दिन का नोटिस जरूर दिया जाना चाहिए, तब कुनेव न काटना चाहिए।

श्री सभापति: नोटिस तो दिया जाता है।

चौधरी नारायण सिंह: नहीं देते जी। अगर नोटिस जाए तो जमीदार पैसा जमा करवा सकता है। जैन साहब बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बस का किराया बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जैसे फरा 1 है 150 रुपये तनखाह पाता है। सफाई मजदूर भी 150 रुपये तनखाह पाता है। इसके दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो एक हजार रुपये तनखाह पाता है। ये दोनों कर्मचारी एक बराबर नहीं हो सकते इनका कम्पेरिजन नहीं हो सकता। उसी बस में सफाई मजदूर सफर करता है उसी में एक हजार तनखाह पाने वाला आदमी सफर करता है। इसलिए मेरी गुजारि 1 है कि सफाई मजदूरों की तनखाह को बढ़ाया जाए और बस के किराये कम किए जाएं। बस का किराया गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, किराया बिल्कुल न बढ़ाया जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

स्वामी आदित्यवे I (हथीन): सभापति महोदय जी, मेरे उपनेता बैठे हैं, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसा निर्देश दें ताकि सभी मंत्री सदन में उपस्थित रहा करें।

डा० मंगल सैन: मन्त्रियों को तो हाजिर होना चाहिए, क्या सदस्यों का भी कोई फर्ज है ? (व्यवधान)

श्री सभापति: वित्त मंत्री जी बैठे हैं और ये सब महकमों के वित्त मंत्री हैं। आपके जो सुझाव हैं वे पहुंच जाएंगे।

18.00 बजे।

स्वामी आदित्यवे I: सभापति जी, 1979-80 का बजट सदन में पेश है। इसके मुताबिक कुल खर्चा 997 रुपये का है और आमदनी 973 करोड़ की है। यह बात ठीक है कि बजट अंग्रेजी में रखा गया है, लेकिन भिन्न भिन्न भागों में हिन्दी में भी रखने का प्रयास किया गया है। मैं चाहता हूँ कि लेखा जोखा हिन्दी में ही रखा जाये। जब मैंने सारे बजट पर दृष्टिपात किया तो मुझे ऐसा लगा कि यह अभिजातवर्गीय बजट है, किसानों का बजट नहीं है। इसमें मजदूर और किसान पर कुल्हाडा चलाया गया है। अन्ततोगत्वा ऐसे बजट का असर जनता पर बुरा ही पडता है। हिसाब किताब का बंटवारा करने वालों ने बहुत बेइन्साफी का बंटवारा किया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जैन जी, गरीबों की बहुत बात किया करते थे लेकिन सभापति महोदय, जी आपको पढकर हैरत होगी कि 16 मंत्रियों के लिए 49 लाख रुपये रखे गये

हैं। अगर प्रति मंत्री साहब लगाएं तो एक मंत्री के हिस्से तीन लाख रुपया आता है यानी पच्चीस हजार रुपया महीना एक मंत्री का खर्च बैठता है जबकि वित्त मंत्री जी के आंकड़ों के अनुसार सारे हरियाणा की पर कैपिटा इन्कम सिर्फ 504 रुपये है। जब 504 रुपये पर कैपिटा इन्कम है तो सभापति जी इसमें काहें औचित्य दिखाई देता है कि एक मंत्री जी अपने को बहुत बड़ा समाजवादी विचारधारा का कहता हो, किसान और मजदूर का हितैशी कहता हो और उसके लिए बड़े बड़े आंसू बहाता हो, वह अपने ऊपर पच्चीस हजार रुपये खर्च करें ? यह बात समझ में नहीं आई। इस तरह की व्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है के लिए हमने कोई समय निश्चित नहीं किया कि यह कब तक चलती रहेगी। आज तो एक ही तरीका देखने में आता है कि किसान के गले में छुरी मार दीजिए, मजदूर का गला घोंट दीजिए क्योंकि सभी जानते हैं कि वह बजट पढ नहीं सकता। उसकी आवाज सुनी नहीं जा सकती इसलिए सारा बर्डन उस पर डाल दीजिए और अपना सासरा खर्च पूरा कर लीजिए। सभापति जी आपको यह पढ कर बड़ी हैरानी होगी कि इस सारे बजट में 131 करोड रुपये इसलिये रखे गये हैं कि एक औफिस ने दूसरे औफिस से सामंजन करना है। यह तनिक नहीं सोचा गया कि एक एक पैसा इकट्ठा होकर जो सरकारी कोश बनता है। यह किसान और मजदूर के गाढे पसीने की कमाई से बनता है। इसे बड़ी बेरहमी से जिधर चाहें उधर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। पिछले साल मैंने बहुत से कटौती प्रस्ताव रखे थे लेकिन बाद में मैंने उन्हें इसलिए वापिस लिया था क्योंकि

मुख्य मंत्री जी ने आवासन दिया था कि अगली बार मितव्यता की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन सभापति जी आप सुन कर हैरान होंगे कि सारे हरियाणा में पर्यटन विभाग की आमदनी तो एक लाख रुपये है और खर्च 33 लाख रुपये का है। हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके लिये 36 लाख रुपये बजट में और रख दिए हैं। कहा जाता है कि हम वहां पर फव्वारे लगा देंगे और उस जगह हो हरा भरा बना देंगे। सभापति महोदय, यह भी कहा जाता है कि इन पर्यटन केन्द्रों में प्रत्येक आदमी जा सकता है लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें बड़े बड़े आदमी ही जा सकते हैं। धारूहेडा हरियाणा भवन, बडखल आदि जितने भी पर्यटक केन्द्र हैं, उनमें आम आदमी से तो ठहरने के 25 रुपये लिए जाते हैं लेकिन हमारे मंत्रियों और बड़े बड़े समाजवादी लोगों से केवल दो रुपये लिए जाते हैं। यह कितनी बड़ी विशमता है ? यह बात यही तक सीमित नहीं है। एक बाधा बात होती तो मैं मान जाता। 993 करोड़ रुपये का यह बजट है। इस रकम से इन्होंने क्या किया है ? बसों की व्यवस्था तो इनसे पूरी नहीं हो पाई अब ये जहाजों का इंतमाज करने लगे हैं। 40 लाख रुपये के हमारे जहाज के अड्डे बनेंगे। रोहतक में 14 लाख रुपये का अड्डा बनेगा। इसी तरह का एक अड्डा हिसार और करनाल में बनेगा। सभापति महोदय, जो लोज जहाजों में चलेंगे वे तो कारों में भी आ जा सकते हैं। अगर इस 40 लाख रुपये से लोगों को खड़े होने के लिए बस अड्डे बना दिए जाते, उनके कडाके की धूप से बचाने के लिए भौंड आदि बना दिए जाते तो कितना अच्छा होता। सरकार को रोडवेज से, अम्बाला जिला

को छोड़ कर, सबसे ज्यादा आमदनी गुडगांव जिला से होती है लेकिन आज स्थिति यह है कि गुडगांव के बस अड्डे को छोड़ कर उस जिले में कहीं और बस अड्डा नहीं हैं हमने नारा लगाया था कि हम किसान और मजदूरों की भलाई करेंगे लेकिन हो इसके उल्ट रहा है। ट्रांसपोर्ट से सरकार को 40 करोड़ रुपये की आमदनी होती है और सारा खर्च 15-20 करोड़ रुपये का है। लेकिन फिर भी सरकार ने गरीब लोगों के ऊपर टैक्स ठोक दिया है 12 परसेंट किराया बढ़ाच दिया है। एक अप्रैल को जब किसान और मजदूर अपने घर से निकलेंगे और कंडक्टर कहेगा कि 12 परसेंट किराया और बढ़ गया है तो वे क्या सोचेंगे उनके दिल के ऊपर क्या असर पड़ेगा ?

सभापति महोदय, आगे चलकर बजट में इन्होंने यह प्रोविजन किया है कि अगर कोई एम0एल0ए0 कोठी के लिए या कार के लिए कर्जा लेना चाहेगा तो उसे सरकार की ओर से कर्जा मिलेगा। इसके लिए बजट में 1 करोड़ 70 लाख रुपये रखे गए हैं। किसान से सभापति महोदय, 11 प्रति शत ब्याज लिया जाता है जबकि सरकार ने सारी संस्थाओं से कुल 416 करोड़ 7 लाख रुपये का कर्जा लिया है इस पर ब्याज की दर 4 परसेंट से लेकर 6 परसेंट तक है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार सिर्फ ब्याज से 48 करोड़ रुपया कमाती है और वह किसान और मजदूरों की जेबों से लेती है। सभापति महोदय, अगर सरकार न्याय करना चाहती है तो एम0एल0एज0 के लिये जो कार और

कोठी के लिए लोन दिया जाना है, यह भी उसी ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए जो ब्याज दर गरीब किसान और मजदूर से लिया जाता है।

सभापति महोदय, बहुचर्चित योजना बाढ की योजना है। इसके बारे में एक मास्टर प्लान बनाया गया है। पिछले साल इसके लिए 20 करोड़ रुपये रखे गये थे और इस साल भी काफी राशि रखी गई है लेकिन देखना यह है कि क्या इस पैसे का सदुपयोग भी हो रहा है या नहीं? यह एक अखबार है। इसका नाम 'आज की खोज' है। यह आगरा से निकलती है। इसमें साफ लफ्जों में कहा गया है कि उजीना डायवर्निंग ड्रेन में लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। अगर यह बात सत्य है तो सरकार इसके लिए इन्क्वायरी बैठाए। यह सूचना मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी को पहुंचाई गई लेकिन वही बात हुई कि पंचों की बात सिर माथे पर, लेकिन परनाला वहीं का वहीं गिरेगा। मैं चाहूंगा कि अगर यह बात सत्य है तो इसके ऊपर ऐक्टिव होना चाहिए और सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और अगर गलत है तो अखबार के एडिटर के विरुद्ध मुकदमा चलना चाहिए। सभापति महोदय जी, सारे मेवात एरिया में आप कहीं चले जाएं डीजल आपको सस्ता मिल जायेगा माबिल आयल आपको सस्ता मिल जाएगा लेकिन ईंटों का सारा धंध ब्लैक में चलता है सीमेंट भी ब्लैक में मिल रहा है। इसमें सरकार को तो इतना दोष नहीं है लेकिन हमारा अधिकारी तंत्र ही ऐसा है जिसके मन में गरीब के

लिए कोई जगह नहीं है। उसको तो स्वयं का फायदा होना चाहिए, अच्छी तनखाह मिलनी चाहिए, भाम को भाराब मिलना चाहिए और उसकी लडकी की भादी होनी चाहिए। किसान को आज क्या मिल रहा है ? आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा का किसान बडी देर से जागता है। दिल्ली की सरकार ने अभी कुछ दिन हुए बसों का किराया बढ़ाया था लेकिन वहां के लोगों ने जब उकसे नाम के दम किया तो सरकार ने यह फैसला किया कि 20 किलोमीटर तक 75 पैसे से ज्यादा किराया नहीं लगेगा। हमारी सरकार किसान और मजदूर की सबसे बडी हमदर्द सरकार कहलाती है। यदि दूसरे राज्यों में 60 साल से ज्यादा आयु वाले किसान को नि: शुल्क फ्री पास की सुविधा दी जा सकती है तो यहां पर क्यों नहीं दी जा सकती ? जो किसान 60 साल का हो गया है उसको बस का फ्री पास मिलना चाहिए। उस गरीब किसान ने अपने खून पसीने की कमाई सरकार को बहुत दी हुई है। अगर किसान का बच्चा दसवीं, बी0ए0 या एम0ए0 में पढता है तो उसको भी बस में आने जाने का फ्री पास मिलना चाहिए।

हम यहां पर किसानों और मजदूरों का नाम लेते हैं ताकि लोग समझें कि जनता सरकार इनके प्रति बहुत हमदर्दी रखती है। यहां पर यह कहना कि हम तुम्हारे लिए यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं सब गलत है। जिस समय चुनाव हुआ था उस वक्त गरीब लोगों के मन में यह भावना पैदा हुई थी कि जनता सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी लेकिन सही मायनों में सरकार कुछ

भी नहीं कर रही है। अब लोग यही सोचते हैं कि जब मौका आयेगा तब देखेंगे। यह कटु सत्य है कि हमने जनता पार्टी को बदनाम कर दिया है। मुझे जनता पार्टी से हमदर्दी है। मैं ये सारी बातें दुखी होकर कह रहा हूँ कि लोग कुर्सी पर बैठ कर ऐंठ कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि हमारा कहने का रूटिन बन गया है लेकिन मेरे मन पर इसका बहुत असर पडा है।

इसी प्रकार से जल प्रदाय योजना की पोजी ज्ञन है। सरदार लछमन सिंह जी यहां पर अब मौजूद नहीं हैं। अगर होते तो मैं उन्हें बताता कि वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं? उनके पास कोई आदमी किसी काम से चला जाये तो वे उसी वक्त आर्डर कर देते हैं कि उसका काम हो गया, लेकिन कागजों पर ही आर्डर होते हैं, प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं होता। मैं मुक्तभोग रही हूँ। मैं एक बार उनके पास गया था और कहा था कि आप मेरे हल्के के फलां फलां गांव के लिए पानी का प्रबन्ध करें। सरदार लछमन सिंह जी ने स्वीकार किया था कि मेरे हल्के में 80 प्रति शत गांवों में पानी का अभाव है। अभी पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि आपके हल्के के 16 गांवों के लिए साढे चार लाख रुपये की वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है। आप अपने हल्के के एस0ई0 से जा कर मालूम करें, उनको पैसा दे दिया गया है। मैंने उससे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि यहां पर कोई पैसा नहीं आया है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आपके 16 गांवों को पानी

मिल जायेगा और साढे चार लाख रुपया दे दिया है, अब ये बताये कि वह रुपया कहां गया किस क्षेत्र को अलाट किया गया है ?

इसी प्रकार सडकों की हालत है। साढे बारह करोड रुपया सडकों के लिए रखा है। साढे सात करोड रुपया पिछले साल रखा गया था। सभापति महोदय, हथीन हल्के की बात होती तो मैं मान लेता कि 89 हल्कों में तो सडकें बन रही हैं और वहां पर विकास का काम हो रहा है यदि एक क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन यहा पर 46 हल्के ऐसे हैं जहां पर दो चार सडकों पर मिटटी पडी होगी और तीस हल्के ऐसे हैं जहां पर सडक बनाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। हमारे सिद्धान्त तो यह कहते हैं कि पहले दूसरे के घर में दीपक जलाओ और बाद में अपने घर पर जलाओ लेकिन यहा तो बिल्कुल उलट हो रहा है। अब इन मंत्रियों की हालत भगवान ही जाने कि क्या कर रहे हैं। खुद तो हवा में उड रहे हैं और यहा पर कहते हैं 1982 तक सब गांवों को सडकों से जोड दिया जायेगा। सब से बडा काम वाटर सप्लाई और सडकों का है। जब ये सब से पहले अपने हल्के में काम करते हैं तो दूसरे हल्के के लोगों के मन में बहुत गलत बातें आती हैं। यह तो वही बात है ' अन्धा बांटे रेवडी अपने अपने को दे' दूसरी जगहों पर तो घोशणा कर देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। आपको ताकत मिली है जल्से में घोशणा करके चले आते हैं पिछले दिनों हस्पतालों की चर्चा की गई। स्वास्थ्य के लिए साढे बारह करोड रुपया रखा गया है। घोशणा की गई कि हथीन

हलको के बनचारी गांव में 25 बिस्तर का हस्पताल बनाया जायेगा परन्तु उस अस्सी लाख रुपये में हांसी में अस्पताल का श्रीगणेश किया गया, हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। दिया गया हमारे लिए और उदघाटन हांसी हस्पताल का हो रहा है। कोइ सिद्धान्त की बात नहीं है। सारा पैसा बागड को दिया जा रहा है और बाकी जगह पर सिर्फ घोशणा है। आप हैरा होंगे कि वर्ल्ड बैंक से 191 करोड रुपए का कर्जा मिला है। वह इस बात के लिए कर्जा मिला था कि नहरों के मार्गों को पक्का किया जाये लेकिन बडे दुःख के साथ कहना पड रहा है कि सिरसा, हिसार, जींद और रोहतक जिले में सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। 1 लाख 29 हजार फुट जल मार्गों को पक्का किया गया। सभी मार्ग उन्हीं क्षेत्रों में पक्के किये गये, बाकी हल्के तो भगवान भरोसे हैं। सभापति महोदय, जिस तरह से धन का बंटवारा होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है।

शिक्षा के लिए साढे बारह करोड रुपया रखा गया है। गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे के स्कूलों के लिए तो बहुत थोडा पैसा दिया गया लेकिन रोहतक यूनिवर्सिटी को दो करोड, हिसार यूनिवर्सिटी को एक करोड अस्सी लाख और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को एक लाख दिया गया है। हरियाणा में हजारों की तादाद में विद्यालय हैं, उनके लिए केवल 12 करोड रुपया दिया है। इस रुपये में नई नई स्कीमें भी हैं, टीचर्स की तनखाहें भी हैं। कहते हैं कि हम गरीबों का भला करना चाहते हैं। जिस प्रकार

पैसा दिया जा रहा है उससे तो अमीरों का भला कर रहे हैं सरकार ने 52 लाख रुपया स्कूलों की मुरम्मत के लिए रखा है। आठ सौ स्कूलों की मुरम्मत के लिए यह पैसा दिया गया जो बाढ से क्षतिग्रस्त हो गये थे। दूसरी तरफ पांच करोड रुपया यूनिवर्सिटीज को दिया जा रहा है। यह सब पैसा कुलीन वर्ग के लोगों के लिए दिया जा रहा है।

पिछले दिनों घोशणा की गई कि कुछ विकास के काम करेंगे। गुडगांव जिले का मेवात क्षेत्र कितना पिछडा हुआ है, वहां पर कोई औद्योगिक संस्था नहीं खोली गई। सभापति जी रोहतक जिले के आप भी हैं। आपके यहां महम में उद्योग के लिए पचार हजार रुपया दे दिया गया, गोहाना में आई0टी0आई0 खोल दिया गया। टोहाना में पैसा दे दिया गया परन्तु मेरे क्षेत्र के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया।

इस बजट का 70 परसैंट हिस्सा बागड में जा रहा है और 30 परसैंट बाकी सारे इलाकों को जा रहा है। आप ही बताये कि किस प्रकार से विकास होगा, किस प्रकार से भला होगा। केवल नारे देने से उन क्षेत्रों का भला नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कहावत है 'गुड न दे तो गुड जैसी बात जरूरव कर दे'। इन मंत्रियों की भी वही हालत है। जो कुछ जा कर कहते हैं सब कुछ मंजूर करते चले जाते हैं लेकिन इम्पलीमेंट कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरी पुरजोर अपील है कि बजट में जितना टैक्स बढ़ाया है वह सारे का सारा वापिस लिया जाना चाहिए। इंग्लैंड के

बड़े भारी अर्थ शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं ग्लैडस्टोन। उन्होंने कहा है कि जो जरूरत की चीजें हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए और जो विलासिता की चीजें हैं, उन पर टैक्स लगाना चाहिए।

पानी भगवान की तरफ से भी मुफ्त में दिया जाता है लेकिन उस पर भी आबयाना बढ़ाया जा रहा है। नारा यह दिया गया है कि सवा छ एकड़ जोत तक का मालिया माफ करेंगे लेकिन सरकार ने यह किया कि एक तरफ मालिया माफ कर दिया और दूसरी तरफ पानी पर आबयाना बढ़ा दिया वही बहुत हुई कि "छोरी चली गई तो बहू आ गई" खर्चा वही का वहीं रहा। इसी प्रकार से बेचारे गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से अपने मकान बना पाते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया। कहने का मतलब यह है कि जो लोगों की आवश्यकता की चीजें हैं, उनमें से एक को भी बिना टैक्स से नहीं छोड़ा है। हर तबके के ऊपर तो इन्होंने टैक्स लगा दिया है और नारा यह लगाया जा रहा है कि यह बजट किसान और मजदूर का भला करने वाला अपने ही ढंग का अद्वितीय बजट है। "न भूतों न भविष्यति"। और कहते यह हैं कि न आज तक ऐसा बजट कभी बना है और न आगे को कभी बनेगा। सभापति जी, आखिर हम कब तक लोगों को इस प्रकार से गुमराह करते चले जायेंगे ? कब तक लोगों को बहकाया जायेगा ? वे लोग जो 30 साल तक सत्ता में रहे हैं, यह सारे के सारे गांव के लोगों का ही गला काटते रहे हैं। मुझे एक एक बात से देखा

होगा कि इन्होंने क्या किया। 20 महीनों में 21 लाख रुपया टी0ए0 का खर्च किया। इसी प्रकार से 20-21 महीनों में टेलीफोन पर और पेट्रोल पर खर्च किया गया। पब्लिक का पैसा अंधाधुंध खर्च करते जा रहे हैं और आपकी सब बातों का जनता को पता है।

श्री सभापति: स्वामी जी अब आप समाप्त करें।

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय जी, कोई बात नहीं। आप मुझे बोल लेने दीजिये आखिर 997 करोड़ रुपये का सवाल है। यहां से पास होने के बाद तो सरकार इस पैसे को खर्च करेगी ही, इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे न रोकें। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि सरकार मेरी बातों की ओर ध्यान दे। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपने खर्चों को घटाये, तब कुछ बात बनेगी। इसी प्रकार से अयोजना वर्णित खर्च (नान प्लान एक्सपेंडीचर) पिछले साल के मुकाबले में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गये हैं। फिर यह कहते हैं कि कोई बात नहीं। खर्च 15 प्रति शत बढ़ गये हैं। यह तो स्वाभाविक ही है कि एस्टेबलि शमेंट में वृद्धि हो जाने की वजह से यह बढ़ गये हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो हम अपने खर्चों में वृद्धि करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग इस बजट को किसान और मजदूर की भलाई का बजट करें, यह सरासर उन लोगों के साथ छल है। अगर उस गरीब की तरफ आप नहीं देखते जिसके बच्चे हैं, और जिसने उनका पालन पोषण करना है तो आप किस की तरफ

देखेंगे ? अगर परमात्मा भी आज के युग में सचमुच प्रकट हो जाये तो वह आपको बड़े से बड़ा दंड देगा क्योंकि आप गरीब के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाते चल जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: नीम हकीम खतराए जान वाली बात हो रही है ?

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, दरअसल बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री जी यह समझते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट वे ही हैं, और कोई है ही नहीं। आपको मैंने जो आंकड़े दिये हैं, वे देखें क्या कहते हैं ?

श्री सभापति: स्वामी जी, अब आप समाप्त भी करें।

श्री मूल चन्द जैन: मेरे ख्याल में वह 24 लाख रुपया तो आपने पढा ही नहीं है जो हमने गरीब वर्कर्स के लिये दिया है।

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सवाल तो यह है कि आप खुद तो लें 25000 रुपया महीना और 25 लाख गरीब वर्कर्स को आप दें 25 लाख रुपया तो एक रुपया तो एक रुपया प्रति साल प्रति व्यक्ति के हिसाब से बैठता है। इस एक रुपये से गरीब व्यक्ति कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा ? क्या उनकी पढाई करवा सकेगा ? अगर वे बीमार हों जायेंगे तो क्या उनकी दवाई करेगा ? आपको अपनी इस गलती को कि इन गरीब लोगों के

लिये बहुत कम रुपया रखा है, स्वीकार करना चाहिए। सभापति महोदय, भाराब बंदी की बात की जाती है। हमारे एक साथी ने अभी अभी यहां पर एक घोशणा की। यह एक बड़ी वाजिब बात है। हमारे यहां जनता जनार्दन के लिये यह एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। एक करोड 20 लाख जनता के रिप्रेजेंटेटिव अगर यहां पर खड़े होकर यह प्रतिज्ञा करें कि वे भाराब नहीं पीयेंगे तो इससे भाराब बंद करने में बड़ी मदद मिलेगी और भाराब बंद हो जायेगी। देखिये हमारा बिहार प्रदे 17 करोड की आबादी का राज्य है। वहां के मुख्य मंत्री ने यह एलान किया है कि भाराब पीना एक बुराई है और हम इसे बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने 1 अप्रैल से इसे बंद करने की घोशणा भी कर दी है। इसी तरह से गुजरात और मद्रास ने भी पूर्ण नाराबंदी कर दी है। लेकिन आप देखिये हमारी सरकार यह कह रही है कि इस साल हम पिछले साल के मुकाबले 6 करोड रुपया ज्यादा कमायेंगे। पिछले साल 20 करोड रुपया इससे कमाई हुई थी और इस साल यह 26 करोड रुपया कमायेंगे। एक तरफ तो भाराब बंदी का नारा दिया जाता है और इसके दूसरी तरफ भाराब की आमदनी का प्रलोभन हमारी सरकार को इसे बंद करने से रोके हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो अयोजना वर्णित खर्च हैं, अगर इनमें कटौती कर दें तो कम से कम तीन साल तक कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके साथ ही भाराब बंद भी कर सकते हैं। इन्होंने किया क्या है ? पहले 6 प्रति सैत अल्कोहल वाली भाराब बनती थी लेकिन अब ये 3 प्रति सैत वाली भाराब चलायेंगे। इसका

नतीजा क्या होगा। जो व्यक्ति पहले एक बोतल पीता था अब वह 2-3 बोतल पीवेगा, तब उसको उतना नशा होगा। इसके साथ ही एक बोतल की कीमत भी बढ़ा दी है। फिर आप कहते हैं कि लोग नाजायज भाराब निकालते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि -

“दे गों में दे ग हरियाणा

जहां दूध दही का खानपा।”

भाराब के बारे में आप कहते हैं लोग नाजायज भाराब निकालते हैं। लेकिन आप देखिये अपनी पालिसी को। लोग ठेके से खरीदें तब तो ठीक है लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी से देसी भाराब या घर की निकाली हुई भाराब खरीदता है तो उसे झट से पकड़ लेते हैं। इनकी दुकानों से कोई गाल ले और पीये, कोई रूकावट नहीं है लेकिन अगर कोई अपनी घर की निकाली हुई भाराब पीता है तो उसे झट से पकड़ लेते हैं। एक तरफ तो सरकार प्रोहीबीशन की बात करती है दूसरी तरफ इस तरह से नीति अपना रही है कि जितनी मर्जी चाहे, आप लाइसेंस लेकर पीयो। जब हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह कह दिया है कि आपको भाराब बंद करने से जितना घाटा होगा, हम उस घाटे का आधा हिस्सा पूरा कर देंगे। यानी आपको जब 18 रुपये की आदमनी है तो 9 करोड़ हमारी केन्द्रीय सरकार देने के लिये तैयार है। अगर आप फिर भी इसे पूर्ण रूप से बंद नहीं करते तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि आपी नीयत में दोष हैं इसीलिये आप हिम्मत के

साथ काम नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार की न गाबंदी की नीति के बारे में आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे आबकारी व कराधान मंत्री जी ने यहां पर यह फरमाया था कि आप प्रस्ताव भेजिये हम वहां पर ठेके बंद कर देंगे। आपको यह सुनकर हैरानी होगी, बाद गाहपुर गुडगांव जिला में एक गांव है। वहां से सरकार के पास प्रस्ताव भी आया हुआ है। यहां पर सदन में खडे होकर 1 मार्च को एलान भी किया गया था कि हम वहां पर ठेका नहीं खालेंगे लेकिन वहां पर 2 लाख रुपये में ठेका नीलाम कर दिया गया है। इसी प्रकार से 997 करोड रुपये का मामला कोई साधारण मामला नहीं है

श्री सभापति: आपका टाईम खत्म हो गया है, अब आप बैठिए। आप कई बार एक ही बात कह चुके हैं।

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय, आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। हमारी सरकार की यह पालिसी है कि हम चार साल में इसे बंद कर देंगे। जब आपने इसे बंद करना ही है तो एकदम से क्यों नहीं बंद कर देते ? आप हमारी जुबान तो बंद कर सकते हैं लेकिन जनता जनार्दन की अदालीम में जब जायेंगे तो आपको वहां पर पता लगेगा कि आपने यह काम गलत किया। सभापति महोदय जी 997 करोड रुपये का मसला है और इसके लिये 7 दिन का टाईम रखा गया है हमें अपनी बात तो अच्छी तरह से कह लेने दें। मैं कोई बेमतलब की बात तो कर नहीं रहा हूँ। मैं आंकडे देकर बात कर रहा हूँ

श्री मूल चन्द जैन: आप आंकडे भी गलत दे रहे हैं।

स्वामी आदित्यवे T: मैं कोई भी गलत आंकडें नहीं दे रहा हूँ। आपने यह भी देखा होगा कि पुलिस के बारे में लोगों की आकायतें बढ़ती जा रही हैं। यह ठीक है कि इनको बहुत ज्यादा वेतन भी दिया जा रहा है और मकान वगैरा बनाने के लिये लोन वगैरा की सुविधायें भी दी जा रही हैं। इनके आवास का प्रबन्ध करने के लिये भी बजट में काफी पैसा रखा गया है। मेरे हल्के सोहना में एक गांव अलीपुर है। वहां पर पिछले साल मई, 1977 से एक आदमी लापता कर दिया गया है। उसका नाम है बनवारी लाल। उस आदमी का आज तक हमारी पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी है कि वह आदमी आखिर कहां गया, कौन उसे ले गया। मालूम नहीं वह जिन्दा भी है या नहीं पिछले दिनों भिवानी में आपकी पुलिस ने सोना क्या पकड लिया, आप इसके गुण गाते ही फिर रहे हो।

श्री सभापति: आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है, अब आप बैठिये।

स्वामी आदित्यवे T: सभापति महोदय जी 997 करोड रुपये का मसला है। इसी प्रकार से आज पुलिस किसी भी इलाके में अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से आज सारे इलाकों में बड़ी बेचैनी और रोश है। मैं सरकार से यह कहना

चाहता हूं कि लोगों के इस असंतोश को दूर करने के लिये कुछ न कुछ ध्यान अव य दिया जाये।

श्री सभापति: स्वामी जी अब आप बैठिये। अब चौधरी भागमल बोलेंगे।

स्वामी आदित्यवे T: सभापति महोदय, मुझे समाप्त तो कर लेने दें।

श्री सभापति: आपको बहुत समय मिल चुका है। अब चौधरी भागमल का मैंने नाम ले दिया है। इसलिये अब आप बैठ जाइए।

स्वामी आदित्यवे T: अन्त में मैं यही कह कर समाप्त करता हूं कि यह जो किसान मजदूर का बजट कहा जा रहा है यह मात्र उनके साथ प्रपंच है, उनके साथ छलावा है। धन्यवाद

चौधरी भाग मल (सढौरा—अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 1979—80 के बजट पर बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं जंगलात की बात पर आता हूं। जहां हमारे मुख्तलिफ आमदनी के साधन हैं, वहां उनमें एक साधन जंगलात का भी है। आज सारे हरियाणा में सिर्फ थोडा सा वह इलाका, वि ेश तौर पर वह इलाका जो हमारा िावालिफ की पहाडियों के साथ लगता है, जिसमे कालका, नारायणगढ, सढौरा और छछरौली की कांस्टीच्यूएंसीज पडती हैं, आता है जहां पर जंगल हैं। सरकार जंगल लगा भी रही है। हम

चाहते हैं कि जंगलात और लगें। लेकिन जंगल लगाने से लोगों को जो दिक्कतें हैं वह तो बतानी चाहिए। हमारी नीति है कि हम जंगल और लगायें यह तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना जरूरी भी है। लेकिन जंगलात महकमे की वजह से लोगों को जो दिक्कतें हैं, वह मैं आपके द्वारा हाउस में सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। याच तो कानून ही कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है या फिर उस डिपार्टमेंट में धांधलेबाजी है। मिसाल के तौर पर हमारे जंगलात के कानून में एक सैकान 5 है। हमारे रिजर्व जंगलात हैं जिनके अंदर कोई भी एन्टर नहीं हो सकता।

Mr. Chairaman: The Hon. Member may continue tomorrow. अब सदन कल दिनांक 20-3-1979 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

***18.30 बजे।**

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार दिनांक 20 मार्च 1979 प्रातः 9.30 तक के लिये *स्थगित हुआ।)